R.N.I. No.HIN/2002/8718 www.aksnews.com M.P./BHOPAL/642/2021-23

In Pursuit of Truth

पाक्षिक

अक्स

वर्ष : 20 । अंक : 04
16 से 30 नवम्बर 2021
पृष्ठ : 48
मूल्य : 25 रु.

गड्ढों में भोपाल

टैक्स भरपूर... सुविधाएं दूर

वीआईपी सड़क चकाचक...
आम आदमी गड्ढे में!

अनियंत्रित विकास...
अव्यवस्थित और भेदभावपूर्ण

भगवान बिरसा मुंडा

जनजातीय गौरव दिवस
15 नवंबर, भोपाल

श्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री

मध्यप्रदेश में संवर रहा जनजातीय समाज

जनजातीय गौरव दिवस पर सरकार ने खोले योजनाओं के द्वार...

भारत में जनसंख्या के आधार पर मध्यप्रदेश में सबसे अधिक जनजातीय भाई-बहन निवास करते हैं। प्रदेश का हर पांचवां व्यक्ति जनजातीय वर्ग का है। लगभग डेढ़ करोड़ आबादी वाले इस वर्ग को समाज की मुख्य-धारा से जोड़ने के लिए प्रदेश सरकार ने विकास का समग्र एक्शन प्लान बनाकर अनेक योजनाओं को लागू कर उन्हें प्रभावी मूर्तरूप भी दिया है। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो या रोजगार, स्व-रोजगार, स्वास्थ्य, पेयजल, आवास या उनके अधिकारों का संरक्षण, सब दृष्टि से मध्यप्रदेश में व्यापक पैमाने पर कार्य किए जा रहे हैं। जनजातीय वर्ग को मिलने वाले राशन के लिए राज्य सरकार द्वारा अनूठी योजना 'राशन आपके द्वार' भी शुरू की गई। योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 15 नवंबर को भोपाल के जम्बूरी मैदान से किया।

जनजातीय महानायक मध्यप्रदेश के गौरव

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का मानना है कि प्रदेश का जनजातीय वर्ग मेहनती और कर्तव्यनिष्ठ है। वर्षों से वन क्षेत्रों में रह कर इन्होंने वन और वन्य-प्राणियों का संरक्षण करते हुए अपना जीवन बिताया है। वनों में रह कर जीवन-यापन करने वाले हमारे जनजातीय भाई-बहन अपने अधिकारों की चिन्ता न करते हुए वर्षों से पर्यावरण संरक्षण के लिए भी कार्य कर रहे हैं। राज्य सरकार उन्हें उनके अधिकार दिलाएगी। जनजातीय समाज में बिरसा मुंडा जैसे अनेक महानायकों ने भी जन्म लिया और भारत की आजादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। ऐसे जनजातीय महानायकों से हमारा मध्यप्रदेश गौरव महसूस करता है। महानायक बिरसा मुंडा की जयंती - 15 नवम्बर को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आतिथ्य में मध्यप्रदेश सरकार ने 'जनजातीय गौरव दिवस' समारोह पूर्वक मनाया।

प्रतियोगी प्रतियोगिताओं के लिए स्मार्ट क्लासेज

प्रदेश में जनजातीय समाज के समग्र विकास की अवधारणा के साथ मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जो फैसले लिए हैं, उनके सुखद परिणामों से जनजातीय वर्ग न केवल आत्म-निर्भर बनेगा, बल्कि अपने अधिकारों के प्रति सजग होकर विकास की मुख्य-धारा से भी जुड़ सकेगा। जनजातीय समाज में शिक्षा का विस्तार करने के उद्देश्य से जनजाति के बेटे-बेटियों को 8वीं, 9वीं कक्षा से ही नीट और जेईई मेन्स की परीक्षा की तैयारी कराने की व्यवस्था की गई है। साथ ही स्मार्ट क्लासेज का संचालन भी किया जायेगा। नीट और जेईई में सफल जनजातीय विद्यार्थियों की पूरी फीस भी सरकार भरेगी।

रोजगार और स्व-रोजगार

जनजातीय समाज के युवाओं को रोजगार और स्व-रोजगार उपलब्ध कराने के लिए भी अहम पहल की गई है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का मानना है कि जनजाति के युवाओं को यदि रोजगार के अवसर दिये जायें तो वे अपनी कड़ी मेहनत और ईमानदारी से समाज का परिदृश्य बदल सकते हैं। मुख्यमंत्री ने फैसला किया है कि प्रत्येक जनजाति बहुल गांव में 4 युवाओं को ग्रामीण इंजीनियर के रूप में प्रशिक्षित किया जायेगा। जनजातीय भाई-बहनों को पुलिस एवं सेना में भर्ती के लिए ट्रेनिंग दिलाई जायेगी। आगामी एक वर्ष में विभिन्न शासकीय विभागों में बैकलॉग के रिक्त पदों की पूर्ति का अभियान चलाया जाएगा। साथ ही स्व-रोजगार के लिए मछली पालन, मुर्गी पालन और बकरी पालन के लिए एकीकृत योजना भी बनाई जायेगी।

शिक्षा

- छात्रावासों/आश्रमों में रहने वाले जनजातीय विद्यार्थियों की शिष्य वृत्ति की दरें बढ़ाई गईं। ये दरें बालकों के लिए 1230 रुपए से बढ़ाकर 1300 रुपए प्रतिमाह और बालिकाओं के लिए 1270 रुपए से बढ़ाकर 1340 रुपए प्रतिमाह की गई हैं।
- प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययनरत जनजातीय वर्ग की बालिकाओं की छात्रवृत्ति 15 रुपए प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह से बढ़ाकर 25 रुपए प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह किया गया। इसी प्रकार कक्षा 6 में अध्ययनरत बालिकाओं को 50 रुपए प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह की छात्रवृत्ति को बढ़ाकर 60 रुपए प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह किया गया।
- प्रदेश के 9 लाख 98 हजार विद्यार्थियों को 153 करोड़ रुपए से अधिक की प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति और 2 लाख 48 हजार विद्यार्थियों को 381 करोड़ रुपए से अधिक की पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान की गई है।
- कक्षा 9वीं से 12वीं की शिक्षा अधिक से अधिक विद्यार्थियों को मिले, इस उद्देश्य से प्रदेश के 5, जनजातीय विकासखंडों में घर से स्कूल तक विद्यार्थियों के परिवहन का पायलट प्रोजेक्ट आगामी सत्र से प्रारंभ किया जा रहा है।
- ऐसे जनजातीय विद्यार्थियों, जिन्हें छात्रावास में आवासीय सुविधा नहीं मिल पाती, उन्हें संभागीय मुख्यालयों पर किराये के आवास में रहने के लिए सहायता दी जाती है। आवास सहायता योजना के अंतर्गत पिछले 18 माह में 1 लाख 28 हजार से अधिक विद्यार्थियों को 207 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता दी गई है।
- आकांक्षा योजना के अंतर्गत 700 से अधिक विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसका परिणाम यह होगा कि जेईई मेन्स, जेईई एडवांस, नीट, क्लेट आदि प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रदेश के 346 जनजातीय विद्यार्थी इस वर्ष चयनित हुए हैं।

सिकल सेल उन्मूलन मिशन

जनजातीय वर्ग को सिकल सेल एनीमिया बीमारी से निजात दिलाने के लिए भी राज्य सरकार ने कमर कस ली है। 15 नवंबर को मध्यप्रदेश राज्य सिकल सेल मिशन शुरू किया गया। मिशन का शुभारंभ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रम में किया। मिशन में पात्र मरीजों का निःशुल्क उपचार किया जायेगा। इसके अलावा शुद्ध पेयजल की उपलब्धता के लिए जल जीवन मिशन के जरिये प्रत्येक जनजातीय ग्राम में पानी की टंकी का निर्माण एवं पाइप लाईन बिछा कर घर-घर नल कनेक्शन दिए जाएंगे।

इस अंक में

राजतंत्र

9 | 'कंट्रोल' करने आए कर रहे 'डैमेज'

मप्र भाजपा के प्रभारी पी मुरलीधर राव अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। कुछ दिन पहले तक उन्होंने अपने पार्टी के नेताओं को नालायक तक कह दिया था। अब उन्होंने फिर एक विवादित बयान दे डाला है...

राजपथ

10-11 | नेतापुत्रों की राजनीति पर...

मप्र भाजपा के दिग्गज नेताओं के पुत्रों को भविष्य की चिंता सताने लगी है। क्योंकि भाजपा ने हाल ही में हुए उपचुनाव में खंडवा और रैगांव में अपने दिवंगत सांसद, विधायक के पुत्रों को टिकट न देकर यह संदेश दे दिया है...

हादसा

16 | 'लापरवाही' का नतीजा हमीदिया...

भोपाल के हमीदिया अस्पताल के नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई में शार्ट सर्किट से आग लगने से मासूमों की मौत ने पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया है। शासन से लेकर स्थानीय प्रशासन तक कटघरे में है। प्रशासन ने आग की घटना...

समस्या

17 | विवादों में अफीम की नई नीति

मप्र के मंदसौर, नीमच और रतलाम की काली मिट्टी में काला सोना यानी अफीम होती है। यहां के करीब 35 हजार किसान अफीम की खेती करते हैं। मप्र से सटे राजस्थान के इलाकों में भी अफीम की खेती होती है। सरकार के पट्टे के बिना कोई किसान खेती नहीं कर सकता है।

आवरण कथा 24, 25, 26, 27, 28

देश के दिल मप्र की राजधानी भोपाल को पिछले 20 साल से पेरिस बनाने के वादे और दावे किए जा रहे हैं, लेकिन आज भी स्थिति यह है कि यहां विकास अनियंत्रित, अव्यवस्थित और भेदभावपूर्ण हो रहा है। मानसून की बारिश, स्मार्ट सिटी योजना, अमृत योजना, मेट्रो रेल परियोजना के कारण शहर में खराब हुई सड़कों, विकास के नाम पर जगह-जगह खुदाई के कारण ऐसा लगता है जैसे भोपाल गड्ढे में है। सड़कों की मरम्मत और गड्ढ़ों की भराई में भेदभाव इस कदर है कि वीआईपी क्षेत्र चकाचक हैं, जबकि आम आदमी गड्ढे में है।

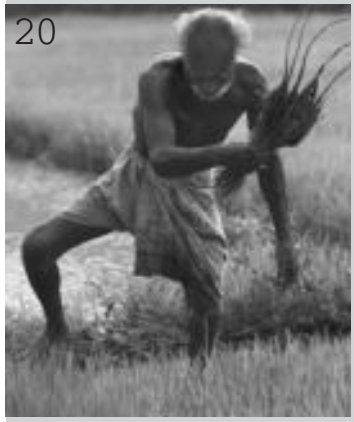

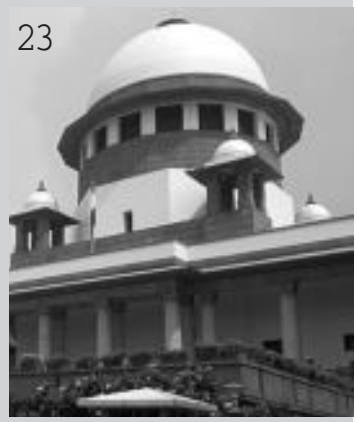

राजनीति

30-31 | कांग्रेस में टकराव

यह कोरा संयोग हो सकता है। सितंबर के आखिरी दिनों में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तथा वर्तमान अनौपचारिक कमानधारी राहुल गांधी युवा चेहरों जेएनयू छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार और दलित एक्टीविस्ट जिग्नेश मेवाणी को पार्टी में शामिल कराने के लिए...

महाराष्ट्र

35 | पिक्चर अभी बाकी है मेरे...

आर्यन खान की जमानत बॉम्बे हाईकोर्ट से मंजूर होने के बाद एनसीपी प्रवक्ता नवाब मलिक ने शाहरुख खान की ही फिल्म ओम शांति ओम के एक डायलॉग कहा था, 'पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।' ये विवाद बढ़ते-बढ़ते नवाब मलिक और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस...

बिहार

38 | लकी-चार्म नीतीश कुमार

बिहार उपचुनाव के नतीजों ने बहुत कुछ साफ कर दिया है। चुनावी जीत के लकी-चार्म नीतीश कुमार ही हैं, लालू यादव नहीं। बिहार में इस हिसाब से साफ-साफ बंटवारा हो गया है। जिधर नीतीश कुमार उधर जीत पक्की, जिधर लालू यादव उधर हार तय।

6-7 अंदर की बात
39 राजस्थान
41 पड़ोस
42 विदेश
44 खेल
45 फिल्म
46 व्यंग्य

अपनी बात

'आदिवासी' अब तेरा ही सहारा...

शा*यर शकील बदायुनी का एक शेर है...*

कांटों से गुजर जाता हूं दामन को बचाकर
फूलों की सियासत से मैं बेगाना नहीं हूं

यानी देश में आज हर वर्ग और समाज राजनीति को भलीभांति समझने लगा है। वर्तमान समय में आदिवासी राजनीति का केंद्र बने हुए हैं। भाजपा हो या कांग्रेस या फिर कोई और पार्टी अपने आपको आदिवासी हितैषी बताने में कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसी सिलसिले में बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस (15 नवंबर) का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मप्र की दोनों पार्टियों ने आदिवासी वोटबैंक को लुभाने की कोशिश की। भाजपा द्वारा भोपाल में जनजातीय गौरव दिवस पर महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। वहीं, कांग्रेस ने जबलपुर में जनजातीय महासम्मेलन का आयोजन किया। भोपाल में प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक सभी नेताओं ने आदिवासियों के पिछड़ने के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बताया वहीं जबलपुर में कांग्रेस ने जनजातीय गौरव दिवस पर भाजपा के कार्यक्रम को नौटंकी बताया। कौन आदिवासी हितैषी है, कौन नहीं, यह तो पार्टियां ही जानती हैं, लेकिन इस आयोजन के माध्यम से पार्टियों ने बड़े वोट बैंक को साधने की कोशिश की है। गौरतलब है कि प्रदेश में करीब 84 सीटों पर आदिवासी मतदाताओं का बोलबाला है। प्रदेश में 2 करोड़ से अधिक आदिवासी आबादी है। इसलिए इस वर्ग को साधने के लिए हर कोई कोशिश में जुटा है। जनजातीय महासम्मेलन को भाजपा की 2023 के विधानसभा चुनावों की तैयारियों के तौर पर देखा जा रहा है। मप्र में आदिवासी (अनुसूचित जनजाति) वर्ग के लिए 47 सीटें हैं। इसके अलावा सामान्य वर्ग की 31 सीटें ऐसी हैं, जहां आदिवासी वोटर निर्णायक हैं। 2018 के विधानसभा चुनावों में भाजपा को बहुमत नहीं मिल सका था तो कहीं न कहीं उसका कारण आदिवासी सीटों पर होल्ड गंवाना था। रिजर्व 47 सीटों में 2013 में भाजपा के पास 32 सीटें थी, जो 2018 में घटकर 16 रह गई थीं। इसलिए भाजपा ने बड़े वोटबैंक को साधने के लिए बड़ा दांव खेला है। जनजातीय गौरव दिवस पर भोपाल के जंबूरी मैदान में मुख्य समारोह में प्रधानमंत्री ने जनजातीय वर्ग के लिए कई बड़ी घोषणाएं की। साथ ही जनजातीय समुदाय के लिए संचालित योजनाओं को गिनाया। गौरतलब है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके संबद्ध संगठन जनजातीय इलाकों में लंबे समय से सक्रिय हैं। इसका भी लाभ उठाने की कोशिश की जा रही है। पिछले चुनावों में जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन (जयस) जैसे संगठनों ने भी भाजपा को परेशान किया था। उधर, भाजपा के आदिवासी प्रेम को देखते हुए कांग्रेस का भी प्रेम उमड़ आया है। इसलिए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने जबलपुर में कार्यक्रम आयोजित कर कांग्रेस को आदिवासी हितैषी बताया। उल्लेखनीय है कि 2011 की जनगणना के मुताबिक मप्र में 43 आदिवासी समूह हैं। प्रदेश में आदिवासियों की आबादी 2 करोड़ से ज्यादा है, जो 230 में से 84 विधानसभा सीटों पर असर डालती हैं। इनमें सबसे ज्यादा आबादी भील-भिलाला करीब 60 लाख, तो गोंड की आबादी करीब 50 लाख है। कोल 11 लाख, तो कोरकू और सहरिया करीब छह-छह लाख हैं। करीब 10 साल बाद ये आंकड़े काफी हद तक बदल चुके हैं। अब भाजपा और कांग्रेस की कोशिश है कि जैसे भी हो, मप्र सहित देशभर में आदिवासियों पर डोरे डालकर उनको अपने पक्ष में किया जाए।

– राजेन्द्र आगाल

पाक्षिक अक्स

वर्ष 20, अंक 4, पृष्ठ-48, 16 से 30 नवंबर, 2021

प्रकाशक एवं संपादक : राजेन्द्र आगाल

सम्पादकीय कार्यालय :
प्लाट नम्बर 150, जोन-1 मनोरमा कॉम्पलेक्स,
एफ-03, 04, प्रथम तल, एम.पी. नगर
भोपाल- 462011 (म.प्र.),
फोन नं. 0755-2557777, टेलीफेक्स - 0755-4017788
email : akshmagazine@gmail.com
Website : www.akshnews.com
RNI NO. HIN/2002/8718 MPBPL/642/2021-23

ब्यूरो
मुंबई :- ऋतेन्द्र माथुर, **कोलकाता:**- इंद्रकुमार,
जयपुर:- आर.के. बिन्नानी, **छत्तीसगढ़:**- संजय शुक्ला, मार्केण्डेय तिवारी, टी.पी. सिंह, **लखनऊ :**- मधु आलोक निगम।

प्रदेश संवाददाता
094251 25096 (इंदौर) विकास दुबे
098276 18400 (जबलपुर) धर्मेन्द्र कथूरिया
094259 85070, (उज्जैन) श्यामसिंह सिकरवार
098934 77156, (विदिशा) ज्योत्सना अनूप यादव

क्षेत्रीय कार्यालय
नई दिल्ली : ईसी 294 माया इंक्लेव मायापुरी-फोन : 9811017939
जयपुर : सी-37, शांतिपथ, श्याम नगर (राजस्थान) मोबाइल-09829 010331
रायपुर : एमआईजी 1 सेक्टर-3 शंकर नगर, फोन : 0771 2282517
भिलाई : नेहरू भवन के सामने, सुपेला, रामनगर, भिलाई, मोबाइल 094241 08015
इंदौर : 39 श्रुत्रि सिलटर निपानिया, इंदौर मोबाइल - 7000123977

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक, राजेन्द्र आगाल द्वारा आगाल प्रिंटर्स, प्लाट नं. 150, जोन-1, प्रथम तल, एफ-03, मनोरमा काम्पलेक्स, एम.पी. नगर भोपाल 462011 (म.प्र.), से मुद्रित एवं प्रकाशित

इस अंक में प्रकाशित सामग्री लेखकों के अपने विचार हैं इनसे सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं हैं समस्त विवादों के लिए न्याय क्षेत्र भोपाल होगा।

पत्र–संपादक के नाम

akshnews.com

अटक गया मास्टर प्लान

प्रदेश की राजधानी भोपाल का आखिरी मास्टर प्लान 2005 में आया था। इस मास्टर प्लान में तय की गई करीब 26 सड़कें आज तक नहीं बन पाईं। इन मास्टर प्लान की सड़कें अतिक्रमण और भू–अर्जन की वजह से अटकी हुई हैं। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

● **लाली सिंह,** भोपाल (म.प्र.)

भोपाल में भी दौड़ेगी मेट्रो

भोपाल में मेट्रो दौड़ाने के लिए सरकार ने वर्ष 2024 का लक्ष्य निर्धारित किया है। लिहाजा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का पर्पल कॉरिडोर के सिविल वर्क को पूरा करने पर जोर है। दूसरे महानगरों की तरह अब राजधानी भोपाल और व्यावसायिक राजधानी इंदौर में भी मेट्रो दौड़ेगी।

● **जितेंद्र रघुवंशी,** इंदौर (म.प्र.)

कमजोर हो रही कांग्रेस

प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति कमजोर हो गई है। वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 114 स्थानों पर जीत हासिल करके 15 साल बाद सत्ता में वापसी की थी। लेकिन 15 माह भी वह सरकार नहीं चला सकी। कांग्रेस को अपने आपको मजबूत करना होगा।

● **लोकेश शाक्या,** ग्वालियर (म.प्र.)

कश्मीर के लिए कड़े कदम उठाए सरकार

धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर में आए दिन कत्लेआम हो रहे हैं। मासूमों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। इस ओर भारत सरकार को कड़े कदम उठाने होंगे। अगर भारत सरकार आज से ही कड़े कदम उठाना शुरू नहीं करेगी, तो नासूर बन चुकी जम्मू–कश्मीर की समस्या देश के लिए घातक हो जाएगी। आतंकवाद पर पाकिस्तान का रोना रोने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि, सीमा पार से केवल आदेश आते हैं, आतंकी यहां के लोग ही बनते हैं। अब सरकार ने सेना को निर्देश दिया है कि वे राज्य के हर संदिग्ध की पहचान कर उसकी जांच पड़ताल कड़ाई से करे। केंद्र सरकार अपने फैसलों से देशभर में एक बड़ा संदेश दे सकती है कि ये भारत संविधान के आधार पर चलते हुए ही लोगों के लोकतांत्रिक हितों की रक्षा कर सकता है।

● **बृजेश नामदेव,** राजगढ़ (म.प्र.)

महंगाई से आम आदमी की कमर टूट रही

मोदी सरकार ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस पर उत्पाद शुल्क इतना बढ़ा दिया है कि इससे उसका राजस्व 2014–15 में लगभग 99,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 2020–21 में 3.73 लाख करोड़ रुपए हो गया है। लेकिन इसका सारा बोझ आम आदमी के कंधों पर आ गया है। एक तो पहले से ही आम आदमी कोरोना के कहर से जूझ रहा है। लोगों के काम–धंधे छिन चुके हैं। उसके ऊपर पेट्रोल और रसोई गैस की महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है। इस बारे में सरकार को सोचना चाहिए।

● **करमवीर सिंह,** नई दिल्ली

नर्मदा पर ध्यान देना होगा

नर्मदा को मां मानकर पूजा करने वालों की जबलपुर शहर में कोई कमी नहीं है। मां नर्मदा की रोज शाम को आरती और दर्शन करने वालों का सुबह से लेकर देर रात तक तांता लगा रहता है, बावजूद इसके नर्मदा को सबसे अधिक गंदा करने वाले शहरों में जबलपुर नंबर वन है। एनजीटी में पेश की गई रिपोर्ट में बताया गया है कि जबलपुर के ग्वारीघाट, तिलवाराघाट, भेड़ाघाट सहित नर्मदा किनारे बसे गांवों की गंदगी सीधे नर्मदा में मिल रही है।

● **नीलिमा यादव,** जबलपुर (म.प्र.)

पाठकों से निवेदन

कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं पक्ष या विपक्ष जो भी संभव हो इस पते पर भेजें

अक्स

150 जोन–1, मनोरमा काम्पलेक्स,
एफ–02, 03, एमपी नगर, भोपाल

गोवा भाजपा में बढ़ती रार

भाजपा शासित राज्यों में गोवा एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां पार्टी की आंतरिक कलह सार्वजनिक तौर पर दिखाई देती है। 40 सदस्यीय विधानसभा सीट वाले गोवा में दरअसल राजनीति पार्टी केंद्रित न होकर व्यक्ति केंद्रित रहती आई है। ऐसे में भाजपा में शामिल हुए अन्य दलों के नेता भाजपा की अनुशासन परक नीति का खुला उल्लंघन करते रहते हैं। गत दिनों केंद्रित गृहमंत्री अमित शाह के गोवा दौरे में ऐसा ही कुछ देखने को मिला। 14 अक्टूबर के दिन पार्टी की कोर कमेटी की बैठक के दौरान दो ताकतवर मंत्रियों ने अमित शाह की उपस्थिति में मुख्यमंत्री की कड़ी आलोचना कर डाली। विश्वजीत राणा और मोविन गाडइन्हों ने मुख्यमंत्री पर अपनी उपेक्षा करने का आरोप लगा डाला। विश्वजीत राणा अपनी पत्नी डॉ. दिव्या राणा के लिए पार्टी का टिकट चाहे रहे हैं जिसके लिए मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत तैयार नहीं हैं। मोविन गाडइन्हों भी नाराज बताए जा रहे हैं। उनके मंत्रालय के कई प्रस्ताव मुख्यमंत्री सावंत ने रोक रखे हैं। एक अन्य मंत्री लोबो ने तो खुलकर ऐलान कर डाला है कि यदि पार्टी उनकी पत्नी को टिकट नहीं देगी तो वे किसी अन्य दल में जा सकते है। दिनोंदिन बढ़ रही इस आंतरिक कलह का असर नजर भी आने लगा है। कुछ अर्सा पहले तक भाजपा नेता दावा कर रहे थे कि 2022 के चुनाव में पार्टी अपने दम पर अकेले सरकार बना लेगी।

हाशिए पर बैठे माधव का बढ़ा संकट

कभी भाजपा आलाकमान की आंखों का तारा हुआ करते राम माधव इन दिनों सुर्खियों के मोहताज हो चले हैं। मोदी-शाह युग के पहले चार बरसों में दिल्ली के सत्ता गलियारों में राम माधव के नाम का डंका बजता था। अमित शाह के पार्टी अध्यक्ष रहते उन्हें जम्मू-कश्मीर का प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया था। कहा जाता है कि धारा 370 समाप्त करवाने और जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश व लद्दाख को उससे अलग करने की रणनीति राम माधव ने ही तैयार की थी। फिर यकायक ही माधव को हाशिए में पटक दिया गया। अब न तो वे पार्टी के महासचिव हैं, न ही दिल्ली के सत्ता गलियारों में उनकी पहले जैसी धमक-हनक बची है। ऐसे कमजोर समय में माधव को मेघालय के राज्यपाल ने एक नई मुसीबत में डाल दिया है। राजस्थान की यात्रा पर गए राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने यह कहकर सनसनी पैदा कर डाली कि जब वे जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल थे तब उन्हें तीन सौ करोड़ की रिश्वत देने का प्रयास किया गया था। उन्होंने कहा कि उन्हें मात्र दो फाइलों पर दस्तखत करने थे जिनमें से एक फाइल उद्योगपति मुकेश अंबानी की कंपनी से संबंधित थी तो दूसरी फाइल को पास कराने में जम्मू-कश्मीर के तत्कालीन प्रभारी और संघ से जुड़े एक नेता इच्छुक थे। उनका सीधा इशारा राम माधव की तरफ था। बेचारे माधव सुर्खियों में लौटे भी तो निगेटिव कारणों के चलते। अब वे कह रहे हैं कि राज्यपाल के आरोप झूठे हैं और वे उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करेंगे।

महारानी का मौन

राजस्थान उपचुनाव के नतीजों के बाद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और भाजपा के सूबेदार सतीश पूनिया के बीच मतभेद बढ़ गए हैं। वसुंधरा खेमे को हमले का मौका मिल गया। उनके समर्थकों प्रहलाद गुंजल और भवानी सिंह राजावत ने न केवल हार पर सवाल उठा दिया बल्कि इस खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेने के लिए एक तरह से सूबेदार सतीश पूनिया को नसीहत भी दे डाली। उपचुनाव के दौरान वसुंधरा ने प्रचार से पूरी तरह दूरी बनाए रखी। वसुंधरा खेमा मांग कर रहा है कि 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए उन्हें ही मुख्यमंत्री पद का पार्टी का उम्मीदवार घोषित कर मुख्यधारा में लाया जाए। अशोक गहलोत जैसे कद्दावर कांग्रेसी को वसुंधरा ही टक्कर दे सकती हैं। लिहाजा उनकी उपेक्षा से पार्टी का अहित ही होगा। वसुंधरा 2018 से ही चुप्पी साधे हैं। पर, आलाकमान को यह संदेश जरूर दे रही हैं कि उन्हें हाशिए पर धकेलना आसान नहीं होगा। अशोक गहलोत सरकार अगर अभी तक नहीं गिर पाई है तो इसके पीछे भी वसुंधरा की अनदेखी ही असली वजह मानी जा रही है। रही सियासी नफे-नुकसान की बात तो 2018 के बाद अब तक सात सीटों के उपचुनाव हुए हैं। पर भाजपा को सफलता महज एक ही सीट पर मिल पाई।

तब प्रीतम सिंह का क्या होगा!

दिल्ली के राजनीतिक गलियारों से लेकर देहरादून तक इन दिनों चर्चा जोरों पर है कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को मुख्यमंत्री फेस बनाने का फैसला कांग्रेस आलाकमान ने लगभग ले लिया है। पंजाब के प्रभारी पद से मुक्ति मिलने के बाद रावत पूरी तरह विधानसभा चुनाव तैयारी में जुट गए हैं। धामी सरकार में मंत्री यशपाल आर्या और विधायक संजीव आर्या को कांग्रेस में वापसी कराकर रावत ने पार्टी के भीतर मौजूद अपने धुर-विरोधियों को पटखनी दे अपनी पकड़ ज्यादा मजबूत कर ली है। कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए कई नेता इन दिनों अपनी रिइंट्री के लिए हरीश रावत से संपर्क साधने में जुटे हैं। खबर यह भी गर्म है कि धामी सरकार में मंत्री हरक सिंह रावत की घर वापसी के लिए नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह पार्टी आलाकमान से जोरदार पैरवी कर चुके हैं लेकिन हरीश रावत की सहमति न होने के चलते हाल फिलहाल ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है। प्रीतम सिंह की दाल न गलती देख अब हरक सिंह बजरिए हरीश रावत कांग्रेस में अपनी रिइंट्री के लिए जोड़ जुगत में लगे हैं।

भक्ति की शक्ति

उप्र में 2022 में होने वाला चुनाव अन्य दलों के साथ आम आदमी पार्टी के लिए भी अहमियत रखता है। अभी तक उसका वर्चस्व दिल्ली में ही है। राजनीतिक विस्तार के लिए उप्र के मैदान से बेहतर कुछ हो भी नहीं सकता है। वहां के आगामी चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपना सियासी कार्ड खेल दिया है। इससे पहले दिल्ली से मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना की शुरुआत करके आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले अपना एक धार्मिक चेहरा जनता के सामने रखा था। इस यात्रा के जरिए दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के दूर-दराज के राज्यों में आम जनता को तीर्थ यात्रा करवाई जा रही है। इससे न केवल एक खास वर्ग को आम आदमी पार्टी ने अपनी तरफ जोड़ा है बल्कि श्रवण कुमार के पोस्टर के जरिए सब को धार्मिक यात्रा कराने वाली पार्टी के तौर पर खुद को तैयार किया है। आने वाले साल में उप्र के चुनाव हैं और इन चुनावों से पहले ही उपचुनाव को प्रदेश में लड़ने के लिए जमीन तैयार कर रही पार्टियां काफी अहम मान रही हैं।

नई मोहब्बत के साइड इफेक्ट्स

प्रदेश के अफसरों का पराई स्त्री प्रेम जगजाहिर है। मंत्रालयीन सूत्रों का कहना है कि मप्र के अधिकांश नौकरशाह पराई स्त्री का प्रेम पाकर अपने आपको गौरवान्वित महसूस करते हैं। ऐसे ही अफसरों में इन दिनों एक कलेक्टर महोदय की खूब चर्चा हो रही है। साहब का पराई स्त्री प्रेम जगजाहिर है। लेकिन इन दिनों साहब को एक नई प्रेमिका मिल गई है। साहब का इस नई प्रेमिका से मनुहार उनकी दूसरी प्रेमिका को बिलकुल नहीं भा रहा है और उसने साहब के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वर्तमान में ये साहब प्रदेश के एक बड़े और संस्कारवान जिले के कलेक्टर हैं। साहब को जब इस जिले की कलेक्टरी मिली थी तो हीरा के लिए ख्यात जिले से अपनी प्रेमिका का तबादला करवाकर अपने कलेक्टरी वाले जिले के नगर निगम में पदस्थ करवा दिया था। यहां दोनों का प्रेम दिनों दिन खूब परवान चढ़ा और सुर्खियों में बना रहा। लेकिन अचानक दोनों के प्रेम के बीच एक नई नायिका का प्रवेश हो गया है। फिर क्या था, साहब ने पुरानी प्रेमिका से मुंह मोड़ना शुरू कर दिया और नई प्रेमिका पर न्यौछावर होने लगे। साहब के बदले रूप को देखकर उनकी पुरानी प्रेमिका तड़प उठी है। अब उसने ठान लिया है कि साहब को सबक सिखाना है। इसके लिए उसने ऊपर तक शिकायतें करनी शुरू कर दी हैं। उधर, साहब की जगह कलेक्टरी चाहने वाले लोग भी सक्रिय हो गए हैं और लॉबिंग शुरू कर दी है।

संस्कारधानी के लिए जुगाड़

हर आईएएस और आईपीएस की इच्छा होती है उसे किसी बड़े जिले की कमान मिले। इसके लिए अफसर निरंतर सक्रिय रहते हैं। इन दिनों प्रदेश में एक आईपीएस अधिकारी संस्कारधानी जबलपुर का एसपी बनने के लिए जुगाड़ लगा रहे हैं। लेकिन उनकी जुगाड़ ऐसी है कि वह कहीं खेल न बिगाड़ दे। दरअसल, 2009 बैच के उक्त आईपीएस अधिकारी जोन के बड़े साहब के माध्यम से एसपी बनने की जुगाड़ लगा रहे हैं। बताया जाता है कि बड़े साहब ने उन्हें बताया है कि मैं जिस चैनल से यहां पहुंचा हूं, उसमें लक्ष्मी की कृपा बरसानी पड़ती है। अगर तुम्हें भी एसपी बनना है तो लक्ष्मी का दान करना होगा। बताया जाता है कि एसपी बनने के लिए उक्त अफसर ऐसा करने को तैयार हैं। वर्तमान समय में एक बटालियन में कमांडेंट के पद पर पदस्थ उक्त आईपीएस अधिकारी की लॉबिंग से पुलिस विभाग के मुखिया खासे नाराज हैं। क्योंकि प्रदेश की प्रशासनिक वीथिका में यह चर्चा जोरों पर चल रही है कि लक्ष्मी के सहारे वे एसपी बनने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि इससे नाराज होकर पुलिस विभाग के मुखिया उक्त आईपीएस अधिकारी को अपने पास फटकने भी नहीं देते हैं। ऐसे में लगता है कि उक्त आईपीएस का संस्कारधानी का एसपी बनने का सपना पूरा नहीं होगा।

आखिर क्यों बदला गया प्रस्ताव ?

प्रदेश की राजनीतिक और प्रशासनिक वीथिका में इन दिनों एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि आखिरकार माइनिंग विभाग में दो डायरेक्टर बनाने के प्रस्ताव को क्यों बदला गया। दरअसल, सरकार माइनिंग विभाग में दो डायरेक्टर बनाने जा रही है। इसके लिए प्रस्ताव बनाया गया था और अनुमोदन के लिए मंत्री को भेजा गया था। प्रस्ताव में उल्लेखित किया गया था कि विभाग में दो डायरेक्टर होंगे और दोनों खनिज विभाग से होंगे। मंत्री ने उक्त प्रस्ताव को पढ़ने के बाद अनुमति दे दी। लेकिन जब यह प्रस्ताव कैबिनेट में पारित हुआ तो मंत्री के साथ सभी यह देखकर अचंभित हो गए कि उसमें बदलाव कर दिया गया है। दरअसल, दूसरे प्रस्ताव में यह उल्लेखित किया गया है कि खनिज विभाग में दूसरा डायरेक्टर प्रतिनियुक्ति पर आएगा। यानी विभाग में किसी डिप्टी कलेक्टर या आईएएस अधिकारी को दूसरा डायरेक्टर बनाया जाएगा। सूत्र बताते हैं कि इस प्रस्ताव को प्रशासनिक मुखिया की निगरानी में बदला गया है। इसके पीछे वजह क्या है, यह तो कोई नहीं जानता, लेकिन मंत्री ने जिस प्रस्ताव पर सहमति दी थी, उसे बदलना चर्चा का विषय बन गया है। उधर, बताया जाता है कि मंत्री ने एक बार फिर से अनुमोदित प्रस्ताव को वापस बुलाया है। वैसे यहां बता दें कि इतना बड़ा बदलाव प्रशासनिक मुखिया मुख्यमंत्री से बिना पूछे नहीं कर सकते हैं।

मेरी दूसरी मुराद पूरी कर दें

वर्तमान सरकार में अपनी कारस्तानी के कारण सबसे अधिक चर्चा में रहने वाले मंत्रीजी एक बार फिर से चर्चा में हैं। इस बार उन्होंने भले ही कोई उठपटांग काम नहीं किया है, लेकिन ऐसी मांग की है जो चर्चा का विषय बन गई है। दरअसल, मंत्रीजी ने मुख्यमंत्री से लिखित मांग की है कि उनके विभाग के प्रमुख सचिव को बदल दिया जाए। इससे पहले मंत्रीजी ने विभाग के डायरेक्टर को बदलने की गुहार लगाई थी, जिसे मुख्यमंत्री ने पूरा कर दिया था। लेकिन अब मंत्रीजी ने मुख्यमंत्री के सामने नई मांग रख दी है। गौरतलब है कि मंत्रीजी और उनका पूरा कुनबा इन दिनों खाने-पीने की कमाई में जुटा हुआ है। मंत्रीजी पहले गेहूं बिक्री के मामले में विवाद में थे, फिर वे बैग टेंडर के मामले में चर्चा में रहे थे। दरअसल, पलायन करके आए नेताजी जबसे मंत्री बने हैं, तब से उनकी ख्वाहिशें दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। उनकी ख्वाहिशों से सरकार भी परेशान है। यही नहीं, मंत्रीजी लगातार विवादों में भी रहते हैं। इस कारण सरकार और पार्टी दोनों की साख में दाग लग रहा है। अब देखना यह है मंत्री की दूसरी मांग पूरी होती है या नहीं।

मुफ्त का चंदन...

जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में राजधानी पूरी तरह भगवा रंग में रंगी नजर आई। एयरपोर्ट हो या शहर का क्षेत्र या आयोजन स्थल, हर जगह जनजातीय इतिहास, जनजातीय विभूतियों, भाजपा नेताओं, योजनाओं के होर्डिंग्स लगे हुए थे। इनको देखकर लोग आयोजन में खर्च का अनुमान लगाने लगे थे। लेकिन सूत्रों का कहना है कि शहर में लगे होर्डिंग्स के लिए न तो सरकार और न ही भाजपा को एक पैसा खर्च करना पड़ा है। बताया जाता है कि सरकार ने प्रचार-प्रसार करने वाली कंपनियों को बुलाकर चाय पिलाई और उन्हें बताया कि इस आयोजन में उन्हें मुफ्त का चंदन, घिस मेरे नंदन की तर्ज पर काम करना होगा। यानी बिना शुल्क के शहरभर में होर्डिंग्स लगाना होगा। तभी आगे शासन और पार्टी के आयोजनों में उन्हें काम मिल सकेगा। बेचारे करते भी तो क्या। उन्होंने भविष्य की चिंता करते हुए होर्डिंग्स और बैनर तैयार करवाए और शहरभर में लगवाए। अब देखना यह है कि उनकी यह मेहरबानी भविष्य में उनके लिए कितनी लाभकारी होती है।

उप्र में असली विकास अब देखने को मिल रहा है। अभी तक विकास के नाम पर पार्टियों ने जनता को केवल ठगा था। लेकिन हमने पिछले चुनाव में जितने वादे किए थे, वह सब पूरा कर दिखाया है। इसी कारण प्रदेश में जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है।

● **योगी आदित्यनाथ**

कंगना रनौत ने आजादी को भीख बताकर जो अपराध किया है, उस पर न जाने क्यों शासक वर्ग चुप है। क्या देशद्रोह सिर्फ मुसलमानों के लिए है? क्या वे लोग कंगना रनौत पर देशद्रोह का आरोप लगाएंगे। वह क्वीन है, इसलिए उनके खिलाफ सब चुप हैं। अब तक उनके खिलाफ कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, लेकिन न सरकार और न ही राष्ट्रवादी बोल रहे हैं।

● **असदुद्दीन ओवैसी**

टी-20 वर्ल्डकप जीतने पर ऑस्ट्रेलिया को बधाई, लेकिन डेविड वार्नर को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट देना पाकिस्तान के कप्तान आजम खान के साथ पक्षपात करना है। यह अवार्ड बाबर आजम को मिलना चाहिए था। बाबर आजम ने सभी मैचों में अच्छा प्रदर्शन किया है। यही नहीं उन्होंने 6 मैचों में 4 फिफ्टी के साथ सबसे अधिक रन बनाए हैं।

● **शोएब अख्तर**

मैंने अपनी किताब में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, जिसको लेकर विवाद खड़ा किया जा रहा है। मुझे दुख है कि मैंने अंग्रेजी में यह किताब लिखी है। अंग्रेजी की समझ न रखने वाले लोग अपने मन से ट्रांसलेशन करके आरोप लगा रहे हैं।

● **सलमान खुर्शीद**

जब मुझे पता चला कि मेरे और राज के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, तब से मैं बहुत शॉक्ड हूं। मैं बताना चाहूंगी कि एसएफएल फिटनेस एक वेंचर है जिसे काशिफ खान चलाते थे। उन्होंने इस ब्रैंड नेम से देशभर में फिटनेस जिम खोलने के राइट्स लिए थे। सारी डील्स पर वही साइन करते थे और उन्हीं के पास इसका जिम्मा था। ना तो हमें उनके किसी भी ट्रॉन्जेक्शन के बारे में कुछ पता है और ना हमने उनसे कोई पैसे लिए हैं। सारी फ्रेंचाइज सीधे तौर पर काशिफ से ही डील करती हैं। कंपनी साल 2014 में बंद हो गई थी और उसको पूरी तरह से काशिफ खान ही चलाता था। मैं बताना चाहूंगी कि मैंने अपने जीवन के 28 साल काफी मेहनत की है। और मुझे ये देखते हुए बहुत दर्द महसूस होता है कि बड़ी सरलता से मेरा नाम और मेरी रेपोटेशन डैमेज किया जा रहा है। कितनी आसानी से मेरा नाम कहीं भी घसीट दिया जाता है।

● **शिल्पा शेट्टी**

वाक्युद्ध

अभी तक जनजातीय समाज मप्र में हाशिए पर था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर आज देशभर का जनजातीय समाज प्रगति कर रहा है। लेकिन कांग्रेस के नेताओं कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को यह अच्छा नहीं लग रहा है। ये लोग नहीं चाहते हैं कि आदिवासी समाज विकास की मुख्यधारा में आए।

● **शिवराज सिंह चौहान**

आदिवासी कल्याण का ढोंग पीट रही भाजपा के अंदर न जाने कहां से आदिवासी प्रेम उमड़ आया है। दरअसल, वोट के लिए भाजपा कुछ भी कर सकती है। शिवराज सिंह चौहान झूठ बोलने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर 15 साल में उन्होंने विकास किया होता तो आज एक-एक वोट के लिए मशक्कत क्यों?

● **कमलनाथ**

'कंट्रोल' करने आए कर रहे 'डैमेज'

मप्र भाजपा के प्रभारी पी मुरलीधर राव अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। कुछ दिन पहले तक उन्होंने अपने पार्टी के नेताओं को नालायक तक कह दिया था। अब उन्होंने फिर एक विवादित बयान दे डाला है, जिससे प्रदेश की राजनीति में नया विवाद हो खड़ा हो गया है। पार्टी के भीतर ही अब राव के खिलाफ विरोध के स्वर उठने लगे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और पार्टी के कई बड़े नेता भी मुरलीधर के बयानों से हैरान-परेशान हैं। हालांकि राव को भविष्य में ऐसे बयानों से बचने की नसीहत भी संघ और पार्टी आलाकमान की तरफ से दी जा चुकी है।

हाल ही में मुरलीधर राव का एक नया बयान सामने आया है, जिसे लेकर सियासी बखेड़ा शुरू हो गया है। उन्होंने भोपाल में एक बयान दिया कि **ब्राह्मण** और **बनिया समुदाय** के लोग उनकी जेब में हैं। राव अपने इस बयान के बाद भाजपा के साथ-साथ विपक्षी दल कांग्रेस के निशाने पर आ गए हैं। एक तरफ जहां पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने हमला बोलते हुए कहा, भाजपा के नेता सत्ता के नशे व अहंकार में चूर हो गए हैं। भाजपा के मप्र प्रभारी मुरलीधर राव कह रहे हैं कि मेरी एक जेब में ब्राह्मण हैं और एक जेब में बनिया हैं। जिस वर्ग के नेताओं ने भाजपा को खड़ा करने में महत्व भूमिका निभाई है, उन वर्गों का यह कैसा सम्मान? यही प्रभारी इसके पहले भाजपा के चार-पांच बार के सांसद-विधायकों को नालायक भी कह चुके हैं। इनके पूर्व प्रोटेम स्पीकर क्षत्रिय समाज का अपमान कर चुके हैं। उन्हें इन दोनों वर्गों से माफी मांगनी चाहिए।

वहीं दूसरी तरफ पार्टी के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष और दो बार विधायक रह चुके विजेंद्र सिंह सिसोदिया ने सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में पार्टी के ताजा हालातों पर टिप्पणी की है। उन्होंने लिखा कि, हमारे घर में बहुत से अनजान चेहरे दिखाई देने लगे हैं, कई ने हमारी बनाई दीवार पर नेम प्लेट भी लगा दी, मकान की नींव से छत तक बनाने में उन्होंने जीवन लगा दिया, वे चेहरे इस भीड़ में नहीं हैं, कुछ हैं, वे खुद को बचाने में शक्ति लगा रहे है। हां आशा-निराशा के भंवर में, अब कुछ आवाजें सुनाई देने लगी हैं। सिसोदिया ने अपने इस संदेश को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा सहित पार्टी संगठन के सभी बड़े नेताओं को टैग किया है।

वहीं राजनीतिक विश्लेषक कहते है कि मप्र भाजपा में मुरलीधर राव बहुत ही जूनियर कैडर के नेता है। स्वदेशी जागरण मंच के अलावा वे कई बौद्धिक मंच से जुड़े जरूर रहे हैं लेकिन सक्रिय राजनीति में उनकी भूमिका बहुत ही सीमित रही है। प्रदेश भाजपा में जिन नेताओं के साथ राव को पार्टी और संगठन की दृष्टिकोण से काम करना है वे राव से बहुत ही ज्यादा सीनियर हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 80 के दशक से ही राजनीति में सक्रिय भूमिका में हैं। विधायक, सांसद, प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही वे पांच बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम करने का लंबा अनुभव रहा है। वे प्रदेश भाजपा की टीम में भी कई अहम जिम्मेदारियां भी संभाल चुके हैं। आज सांसद और प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में हैं। प्रदेश संगठन में देखें तो सुहास भगत और हितानंद शर्मा को भी संघ में काम करने का लंबा अनुभव है। वहीं प्रदेश भाजपा की टीम में भी कुछ ऐसे नेता हैं जो शुरू से ही जमीनी स्तर की राजनीति करते आ रहे हैं। आज मुरलीधर राव के पास राष्ट्रीय स्तर पर तो कोई अहम जिम्मेदारी है नहीं। पार्टी ने उन्हें केवल एक राज्य का जिम्मा दे दिया है। वो भी ऐसा राज्य जहां भाजपा सरकार है और विधानसभा चुनावों में भी फिलहाल बहुत वक्त है। इसलिए यहां ज्यादा कुछ करने की गुंजाइश नहीं दिख रही है। ऐसे में राव अपना वर्चस्व साबित करने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं और सुर्खियों में रहने की कोशिशों में लगे हुए हैं।

संघ से जुड़े एक विश्वस्त सूत्र ने बताया कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुरलीधर राव को प्रदेश भाजपा को कंट्रोल करने के लिए भेजा था, लेकिन अब उन्हें खुद ही कंट्रोल करने की जरूरत पड़ रही है। राव के लगातार आ रहे विवादित बयानों से संघ और भाजपा के नेता भी परेशान हैं। पार्टी और संगठन के नेता इन बातों को हाईकमान तक पहुंचा रहे हैं कि राव को भी कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। भले ही कुछ नेता उनके हिंदी भाषा नहीं होने के कारण इस तरह की बयानों को दिक्कत का एक कारण मान रहे हों, लेकिन प्रदेश भाजपा के कई बड़े नेता उनके विवादित बयानों और व्यवहार से बहुत नाराज हैं। हाल ही में प्रदेश संगठन से जुड़े वरिष्ठ पदाधिकारियों ने केंद्रीय नेतृत्व के साथ हुई बैठक में भी राव के बयानों के अलावा उनकी कार्यशैली को लेकर भी चर्चा की है। सूत्र ने आगे बताया कि भाजपा राष्ट्रीय सह-संगठन मंत्री और मप्र के प्रभारी के तौर पर शिवप्रकाश काम देख रहे हैं। उनका बेस कैंप भोपाल में ही है। इसलिए प्रदेश में उनकी सक्रियता बढ़ रही है। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले और उनकी टीम भी प्रदेश में बेहद एक्टिव है। ऐसे में संघ स्तर से भी पी मुरलीधर राव की निगरानी शुरू हो गई है।

● **लोकेंद्र शर्मा**

राव पहले भी दे चुके हैं विवादित बयान

गत दिनों जब मीडिया ने मप्र भाजपा के प्रभारी मुरलीधर राव से पूछा था कि भाजपा के बारे में यह आम धारणा रही है कि यह ब्राह्मणों और बनियों की राजनीतिक पार्टी है और अब वह एसटी-एससी वर्ग पर ध्यान देने की बात कर रही है, जबकि भाजपा का नारा सबका साथ, सबका विकास है। इस प्रश्न का जवाब देते हुए राव ने अपने कुर्ते की जेब की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि ब्राह्मण और बनिया मेरी जेब में हैं। हालांकि उन्होंने बाद में बात को संभालते हुए कहा कि जब भाजपा में ब्राह्मण नेता थे, तब मीडिया ब्राह्मणों की पार्टी कहती थी। इससे पहले भी राव ने मप्र में एक बैठक के दौरान कहा था कि लगातार चार बार पांच बार से सांसद, विधायक बनना, लगातार प्रतिनिधित्व करना, यह जनता का दिया हुआ वरदान होता है। इसके बाद रोने के लिए कुछ नहीं होना चाहिए, ऐसे नेता अगर कहे कि उन्हें मौका नहीं मिला तो उनसे बड़ा नालायक कोई नहीं, उन्हें मौका मिलना भी नहीं चाहिए।

देश की राजनीति में परिवारवाद तेजी से बढ़ रहा है। चाहे कांग्रेस हो या भाजपा, सपा, बसपा, जदयू, राजद या अन्य कोई दल, हर पार्टी का नेता अपने परिजनों को राजनीति में आगे बढ़ाने की कवायद में लगा हुआ है। मप्र भी इससे अछूता नहीं है। मप्र कांग्रेस और भाजपा में कई नेताओं ने अपने पुत्रों की राजनीतिक लॉन्चिंग कर दी है। भाजपा में नेतापुत्रों की बाढ़ सी आई हुई है। सबको उम्मीद है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में उन्हें टिकट मिल सकता है, लेकिन पार्टी की नई रणनीति ने उनकी उम्मीदों पर प्रश्नचिन्ह लगा दिया है।

नेतापुत्रों की राजनीति पर ग्रहण...

मप्र भाजपा के दिग्गज नेताओं के पुत्रों को भविष्य की चिंता सताने लगी है। क्योंकि भाजपा ने हाल ही में हुए उपचुनाव में खंडवा और रैगांव में अपने दिवंगत सांसद, विधायक के पुत्रों को टिकट न देकर यह संदेश दे दिया है कि पार्टी में अब परिवारवाद नहीं चलेगा। इससे पहले भाजयुमो में भी नेतापुत्रों को जगह नहीं दी गई थी। ऐसा पहली बार हुआ है, जब भाजयुमो में एक भी नेता पुत्र पदाधिकारी नहीं बना।

गौरतलब है कि मप्र के कई क्षेत्रों में भाजपा हो या कांग्रेस, राजनीति में सफल नेताओं के पीछे पुत्र-पुत्री की सक्रिय भूमिका रही है। निर्वाचन क्षेत्र में सियासत के सारे सूत्र ये ही संभाल रहे हैं। अब भाजपा नेताओं को अपने पुत्रों की चिंता सताने लगी है। हाल ही में संपन्न हुए उपचुनावों में भाजपा ने खंडवा और रैगांव में अपने दिवंगत सांसद, विधायक के पुत्रों को टिकट न देकर बड़ा संदेश दिया है। इस संदेश से कई नेता सकते में हैं। वहीं कई नेताओं के पुत्रों ने अपनी राह भी बदलनी शुरू कर दी है।

पार्टी के इस कदम से भाजपा के दिग्गज नेताओं को अपने पुत्रों के लिए नई राह तलाशनी होगी। गौरतलब है कि पिछले एक दशक से प्रदेश की राजनीति में भाजपा के दिग्गज नेताओं के पुत्र अपनी जगह बना रहे थे। इनमें से कैलाश विजयवर्गीय के पुत्र आकाश विजयवर्गीय और मंत्री हर्ष सिंह के बेटे विक्रम सिंह की राजनीतिक लॉन्चिंग 2018 में हो चुकी है और वे विधायक भी बन चुके हैं। लेकिन इनके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पुत्र कार्तिकेय चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र सिंह तोमर, राज्यसभा सदस्य प्रभात झा के बेटे त्रिशमूल झा, स्व. नंदकुमार चौहान के बेटे हर्षवर्धन सिंह, मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बेटे सुकर्ण मिश्रा, मंत्री गोपाल भार्गव के बेटे अभिषेक भार्गव, जयंत मलैया के बेटे सिद्धार्थ मलैया, सुमित्रा महाजन के बेटे मंदार महाजन, पूर्व मंत्री करणसिंह वर्मा के बेटे विष्णु वर्मा, गौरीशंकर बिसेन की बेटी मौसम बिसेन, गौरीशंकर शेजवार के बेटे मुदित शेजवार, सत्यनारायण जटिया के बेटे राजकुमार जटिया, माया सिंह के बेटे पितांबर सिंह, मालिनी गौड़ के पुत्र एकलव्य, मंत्री यशोधराराजे सिंधिया के पुत्र अक्षय भंसाली, विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के पुत्र राहुल गौतम, दीपक जोशी के बेटे जयवर्धन जोशी, अर्चना चिटनीस के बेटे समर्थ चिटनीस सहित कई नेता पुत्र राजनीति में अवतरित होने को बेताब हैं। लेकिन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के फॉर्मूले में ये फिट नहीं बैठते हैं। इसलिए माना जा रहा है कि इन नेतापुत्रों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा अधूरी रह जाएगी।

उपरोक्त नेतापुत्र 2013 से प्रदेश की राजनीति में अपनी जमीन तलाश रहे हैं। इनमें से कुछ नेता पुत्रों को भाजयुमो के रास्ते राजनीति में प्रवेश दिया गया था। वहीं कुछ अपनी पिता की विरासत संभालने के लिए तैयारी कर रहे थे। 2018 में जहां दो नेतापुत्रों ने विधानसभा के लॉन्चिंग पैड से उड़ान भरी वहीं अन्य नेता पुत्रों को उम्मीद थी कि 2023 में उन्हें विधानसभा का टिकट मिल जाएगा। लेकिन हाल ही में हुए उपचुनाव में भाजपा ने दिवंगत नेताओं के पुत्रों को टिकट न देकर यह संदेश दे दिया है कि प्रदेश

देवेंद्र ने पूरे प्रदेश में खड़ा किया नेटवर्क

भाजयुमो के सहारे प्रदेश की राजनीति में प्रवेश करने वाले केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र सिंह तोमर को भले ही इस बार भाजयुमो में जगह नहीं मिली, लेकिन उन्होंने भावी राजनीति को देखते हुए प्रदेशभर में अपना नेटवर्क खड़ा कर लिया है। आलम यह है कि वे प्रदेश में जहां भी जाते हैं, उनके साथ 50-60 लग्जरी गाड़ियों का काफिला जुट जाता है। उनका भोपाल और इंदौर से खास लगाव है। युवाओं में उनकी दिन पर दिन पैठ बढ़ती जा रही है। लेकिन जिस तरह नेतापुत्रों के लिए भाजपा के दरवाजे बंद हो रहे हैं, उससे देवेंद्र सिंह तोमर का राजनीतिक भविष्य भी अधर में दिख रहा है।

भाजपा में परिवारवाद नहीं चलेगा। यदि पार्टी इसी नीति पर चली तो अगले चुनाव में भाजपा नेतापुत्रों के लिए पार्टी का दरवाजा पूरी तरह बंद हो जाएगा।

गौरतलब है कि भाजपा में कई नेताओं के पुत्र और परिजन आज सक्रिय राजनीति में मुख्य भूमिका में हैं। वर्तमान सरकार में विश्वास सारंग मंत्री हैं। वे भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद स्व. कैलाशनारायण सारंग के पुत्र हैं। वहीं ओमप्रकाश सकलेचा भी मंत्री हैं। वे पूर्व मुख्यमंत्री वीरेंद्र कुमार सकलेचा के पुत्र हैं। इनसे पहले कई नेतापुत्र मंत्री रह चुके हैं। इसी तरह कई नेतापुत्र विधायक हैं, लेकिन अब जिस तरह प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने उपचुनाव में नेतापुत्रों को टिकट नहीं दिया है, उससे पार्टी में संदेश गया है कि भविष्य में नेतापुत्रों की राह आसान नहीं है।

मौके की नजाकत को भांपते हुए नेतापुत्र राजनीति के सहारे नहीं रहना चाहते हैं। उन्हें भविष्य की चिंता सताने लगी है, इसलिए कई नेतापुत्र व्यवसाय जमाने में सक्रिय हो गए हैं। कुछ नेताओं ने अपने पुत्रों को अपने पारिवारिक कारोबार में लगा दिया है, तो कोई नेतापुत्र ठेकेदारी करने की तैयारी कर रहा है तो किसी ने उद्योग धंधों का रुख किया है। वहीं कुछ नेतापुत्र खेती-किसानी और डेयरी का व्यवसाय करने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं कुछ मॉल और मार्ट में निवेश करने की योजना बना रहे हैं। इसके लिए बकायदा विशेषज्ञों से सलाह भी ली जा रही है। कई नेतापुत्र बड़े-बड़े ठेकेदारों के साथ पार्टनरशिप करने में लग गए हैं। यह भी खबर आ रही है कि भाजपा के कुछ नेता अपने ही पुत्रों के राजनीतिक भविष्य के लिए कांग्रेस की ओर निहारने लगे हैं।

कमलदल में वंशवाद के लिए बंद होते दरवाजे को देखते हुए **दो नेतापुत्र** केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से प्रभावित हुए हैं। गौरतलब है कि गडकरी ने पेट्रोलियम पदार्थों की जगह इथेनॉल से वाहन चलाने पर जोर दिया है। ऐसे में दो नेतापुत्रों ने भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए इथेनॉल बनाने की फैक्ट्री डालने की तैयारी कर ली है। इनमें से एक हैं ग्वालियर-चंबल संभाग के एक कद्दावर नेता और मंत्री के पुत्र और दूसरे हैं भोपाल संभाग क्षेत्र के एक मंत्री के सुपुत्र। बताया जाता है कि राजनीति में नेतापुत्रों की कठोर डगर को देखते हुए दोनों मंत्रियों ने अपने-अपने बेटे के लिए लगभग 100-150 करोड़ की फैक्ट्री शुरू करने की तैयारी कर ली है। वहीं बुंदेलखंड से आने वाले एक पूर्व मंत्री के बेटे ने अपना सारा पैसा राजधानी भोपाल के एक होटल में लगा दिया है।

भाजपा में नेतापुत्रों के लिए दरवाजे बंद होते देख कांग्रेस में भी हलचल तेज हो गई है। सूत्र बताते हैं कि कई कांग्रेसी नेता अपने पुत्रों के लिए राजनीति के साथ ही अन्य क्षेत्रों में संभावनाएं तलाशने में जुट गए हैं। उधर, भाजपा के कई दिग्गज नेता अभी भी हार मानते नहीं दिख रहे हैं। खासकर ग्वालियर-चंबल अंचल के नेताओं को विश्वास है कि आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी उनके पुत्रों को टिकट दे सकती है। इसलिए नेतापुत्र क्षेत्रों में सक्रिय हैं और लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं।

● **कुमार राजेन्द्र**

भाजयुमो में एक भी नेता पुत्र नहीं

भाजपा ही एकमात्र ऐसी राजनीतिक पार्टी है, जिसमें बड़े नेता बनने का रास्ता भाजयुमो से होकर ही गुजरता है। पार्टी में आज जितने भी बड़े नेता हैं, वे भाजयुमो के पदाधिकारी रहे हैं। ऐसे में दिग्गज नेताओं के बेटा-बेटी राजनीति में आने के लिए भाजयुमो में एंट्री पाने को लालायित रहते हैं। अगर यह कहा जाए कि भाजयुमो नेतापुत्रों का लॉन्चिंग पैड है, तो अतिश्योक्ति नहीं होगी। लेकिन इस बार भाजयुमो में एक भी नेतापुत्र को जगह नहीं दी गई है। यानी प्रदेश संगठन ने नेतापुत्रों की सियासी तरक्की पर रोक लगा दी है। जबकि एक दर्जन से ज्यादा नेताओं के पुत्र अपने पिता की राजनीतिक पिच पर सियासी प्रैक्टिस कर रहे थे।

कांग्रेस में बदलाव की तैयारी

उपचुनाव के बाद अब कांग्रेस संगठन में फेरबदल की सुगबुगाहट नजर आने लगी है। इसको लेकर पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ ने प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेताओं और जिलों के संगठन प्रभारियों की बैठक भी कर ली है। जिसमें यह प्रमुखता से निकलकर आया है कि लंबे समय से पदों में डटे पदाधिकारी कामकाज में अपेक्षित तौर पर सक्रिय नहीं हैं तो कई मंडलम और सेक्टर के पदाधिकारी भी पद पाने के बाद संगठनात्मक कार्यों में रुचि नहीं ले रहे हैं। इधर सदस्यता अभियान को लेकर भी फीडबैक बहुत अच्छा नहीं आया है। इन सबको देखते हुए प्रदेशाध्यक्ष ने अब बदलाव की तैयारी के निर्देश दे दिए हैं। यह भी तय किया गया है कि संगठनात्मक बदलाव में 50 साल की उम्र को सीमा रेखा माना जाएगा। हालांकि इसे लक्ष्मण रेखा नहीं माना जाएगा, लेकिन प्राथमिकता इसी उम्र की सीमा पर दी जाएगी। इसके अलावा पदों में जातीय समीकरणों का भी ध्यान रखा जाएगा।

कांग्रेस ने उपचुनाव के बाद अब 2023 के चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। उपचुनाव के फीडबैक कांग्रेस के लिए बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। तीन उपचुनाव हार गए और इकलौती रैगांव सीट जीत पाए। लेकिन जिस तरीके से रैगांव में कांग्रेस संगठन की सक्रियता होनी थी वह नहीं दिखी। कई अपेक्षित चेहरे चुनाव के दौरान जमीनी स्तर पर वैसा काम करते नहीं दिखे जैसी अपेक्षा थी। इसके बाद जिला संगठन प्रभारियों की बैठक में तय किया गया है कि जल्द ही फेरबदल कर दिया जाना चाहिए ताकि नए चेहरे 2023 के आम चुनाव के लिए न केवल खुद तैयार हो सकें बल्कि संगठन को भी मजबूत कर सकें। इसके लिए नए चेहरों को सामने लाने पर जोर दिए जाने का निर्णय लिया गया है तो सालों से संगठन में जमे चेहरों को अब जिम्मेदारी से मुक्त करने पर भी सहमति बन गई है। हालांकि यह बदलाव पूरे प्रदेश में होना है लेकिन विंध्य में बदलाव पर सभी का फोकस है। जो संकेत मिले हैं उसमें कई जिला संगठन के पदाधिकारी रेड जोन में है। वहां बदलाव की संभावना प्रबल मानी जा रही है। इसके लिए तमाम नामों पर तलाश शुरू हो गई है। विधायकों से फीडबैक तो लिया ही जा रहा है बल्कि वरिष्ठ नेताओं से भी राय मशविरा लिया जाकर बदलाव की रणनीति और चेहरे तय किए जाएंगे। यह तय किया गया है कि बदलाव में अब पीढ़ी परिवर्तन को भी ध्यान में रखना है और नया नेतृत्व भी तैयार करना है। इसके लिए संगठन में 50 साल की उम्र का फॉर्मूला तय किया गया है। वहीं संगनात्मक पदों के लिए क्षेत्रीय और स्थानीय जातीय समीकरणों पर भी गौर किया जाएगा। इसके साथ ही कोशिश होगी कि जो भी चेहरा चुना जाए उसमें ज्यादा से ज्यादा आम सहमति बने और कम से कम विरोध की स्थिति बने साथ ही उसकी सक्रियता और सामर्थ्य आगामी 2023 के चुनाव के अनुकूल हो। जिस तरह के संकेत हैं उससे माना जा रहा है कि यह फेरबदल एक-दो माह के अंदर हो सकता है।

कांग्रेस हर वार्ड में अब वरिष्ठ नेताओं को प्रभारी बनाकर संगठन को मजबूत करने का प्रयोग कर रही है। वरिष्ठ नेताओं को उनके वार्डों से दूसरे वार्डों में प्रभारी बनाकर भेजा जाएगा, ताकि वे उस वार्ड के नेताओं में समन्वय बना सकें और पार्टी के कामों को आगे बढ़ाएं। इसके साथ ही ये लोग सदस्यता अभियान का भी काम करेंगे। उपचुनाव में भले ही तीन सीटों पर कांग्रेस हार गई हो, लेकिन एक विधानसभा सीट जीतने के बाद कांग्रेसियों का हौसला कायम है। पिछले दिनों हुई बैठक के बाद तय हुआ था कि वार्ड और बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत किया जाए। कांग्रेस ने जिले में संगठन प्रभारी तो बना दिए, लेकिन संगठन प्रभारी ही समय पर बैठकें लेने नहीं आते हैं और न ही अभी उपचुनाव में कुछ खास कर पाए। संगठन को मजबूती देने के लिए अब वार्ड स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। हर वार्ड में कांग्रेस के एक वरिष्ठ और अनुभवी नेता को प्रभारी बनाया जा रहा है, ताकि वे अपने-अपने वार्ड में कांग्रेस संगठन को मजबूत करने का काम करें। इनकी सूची तैयार की जा रही है। वार्डों के प्रभारियों को वार्ड और मंडलम स्तर पर काम करना होगा। वार्ड के नेताओं से समन्वय बनाकर उनके साथ चर्चा करनी होगी। बैठकें कर कांग्रेस के आंदोलन और आगे के कामों पर ध्यान देना होगा। इसके साथ ही अभी जो सदस्यता अभियान चल रहा है, उसमें भी भाग लेकर नए लोगों को कांग्रेस से जोड़ना होगा। इसके साथ ही सरकार को कैसे जवाब देना है और लोगों की समस्याओं को कैसे सुलझाना है, इस पर भी प्रभारी काम करेंगे। जल्द ही प्रभारियों की घोषणा कर दी जाएगी।

● **अरविंद नारद**

वर्धा में तैयार किए गए हैं पार्टी के थिंकर

संघ की तर्ज पर कांग्रेस ने वर्धा में थिंकर तैयार किए हैं। ये पार्टी के वैचारिक और समर्पित लोग हैं। तथ्यों से यह लोगों के बीच जाकर सच्चाई से अवगत कराएंगे। इसके लिए प्रशिक्षण की एक वृहद योजना बनाई गई है। इसका संगठन सेक्टर तक होगा। हर सेक्टर में 20-20 लोगों की टीम को प्रशिक्षित किया जाएगा। दरअसल कांग्रेस 15 से 29 नंवबर के बीच जनजागरण के माध्यम से महंगाई को प्रदेश में बड़ा मुद्दा बनाने में जुटी है। लोगों का समर्थन हासिल करने के लिए तकनीक की भी मदद ली जा रही है। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह के मुताबिक आज महंगाई से हर व्यक्ति परेशान है। प्रदेश में महंगाई को लेकर बड़ा आंदोलन खड़ा करने के लिए कांग्रेस 29 नवंबर तक जनजागरण अभियान चलाएगी। महंगाई सहित अन्य विषयों पर लोगों तक अपनी बात अधिक सटीकता और प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए प्रदेश के पांच लोगों की ट्रेनिंग वर्धा में हुई है। वे हर संसदीय क्षेत्र में 10-10 लोगों को ट्रेंड करेंगे। ये 10 लोग विधानसभा में गठित सेक्टर मंडल में 20-20 लोगों को प्रशिक्षित करेंगे। इनके साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी लोगों के बीच जाएंगे।

अधर में हाई सिक्युरिटी नंबर प्लेट

सड़कों पर हो रहे हादसों और वाहनों की चोरी पर नकेल कसने के लिए सरकार ने हाई सिक्युरिटी नंबर प्लेट लगाने की व्यवस्था की, लेकिन मप्र में ये व्यवस्था अधर में लटकी हुई है। इसका खामियाजा वाहन चालकों को भुगतना पड़ रहा है।

देश में 2019 से सभी नए वाहनों में हाई सिक्युरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य किया गया है। लेकिन वाहनों में हाई सिक्युरिटी नंबर प्लेट लगवाना मुश्किल नजर आ रहा है। हाल ही में कोर्ट ने परिवहन विभाग और लिंक उत्सव कंपनी के बीच चल रहे विवाद में लिंक उत्सव कंपनी को अक्टूबर 2014 से अप्रैल 2019 तक के बीच बिके वाहनों में नंबर प्लेट लगाने का फैसला दिया है। इस दौरान प्रदेश में रजिस्टर्ड हुए वाहनों की संख्या 50 लाख से ज्यादा है। लेकिन कंपनी और सरकार के बीच पहले जो अनुबंध हुआ था उस कीमत पर कंपनी के लिए प्लेट लगाना संभव नहीं है। पहले की अपेक्षा अभी लगाई जा रही प्लेटों की कीमत दुगने से ज्यादा बढ़ चुकी है।

परिवहन विभाग ने प्रदेश में वाहनों पर हाई सिक्युरिटी नंबर प्लेट लगाए जाने के लिए जनवरी 2012 में लिंक उत्सव कंपनी को ठेका दिया था। शुरुआत से ही कंपनी के काम को लेकर विभाग को शिकायतें मिल रही थी, जिसमें समय पर प्लेटें ना देने और खराब क्वालिटी की प्लेटों की शिकायतें शामिल थी। इस आधार पर सरकार ने अक्टूबर 2014 में कंपनी का ठेका निरस्त कर दिया था। कंपनी ने इसके खिलाफ ग्वालियर हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसमें कोर्ट ने कंपनी के पक्ष में फैसला दिया। सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई, जिसमें आपसी समझौते से विवाद को निपटाए जाने की बात कही गई थी। इस बीच सरकार ने अप्रैल 2019 से सभी वाहनों में हाई सिक्युरिटी नंबर प्लेट लगाकर देना अनिवार्य कर दिया है। प्लेट लगाने की जिम्मेदारी अब वाहन डीलर्स को दी गई है। वहीं हाल ही में शासन और कंपनी के बीच चल रहे विवाद में कंपनी के पक्ष में फैसला आया है और कहा गया है कि अप्रैल 2019 के पहले के वाहनों में कंपनी नंबर प्लेट लगाएगी।

परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि लिंक उत्सव कंपनी को पुराने वाहनों में नंबर प्लेट लगाने की अनुमति तो मिल गई है, लेकिन कंपनी के लिए यह काम कर पाना संभव नहीं होगा, क्योंकि कंपनी को रेट्स बढ़ाने की कोई छूट नहीं मिली है। पहले कंपनी जहां 111 रुपए में दो पहिया वाहन में और 334 रुपए में चार पहिया वाहन में नंबर प्लेट लगाती थी, वहीं प्लेट्स अब दो पहिया में करीब 300 रुपए और चार पहिया में 700 रुपए में लग रही है। कंपनी के लिए आधी कीमत में काम कर पाना मुश्किल है, जिससे पुराने वाहनों में हाई सिक्युरिटी नंबर प्लेट लग पाना भी मुश्किल है। इस पूरे मामले में सबसे बड़ी विडंबना यह भी है कि जिस कंपनी को परिवहन विभाग नंबर प्लेट बनाने के लिए प्रतिबंधित कर चुकी है अप्रैल 2019 से डीलर्स के लिए वही कंपनी नंबर प्लेट तैयार कर रही है और डीलर्स वही प्लेट लगाकर नए वाहनों को जारी कर रहे हैं। यही कंपनी डीलर्स से नई कीमत भी ले रही है जिसे अप्रत्यक्ष रूप से गाड़ी की कीमत में जोड़कर वाहन मालिक से वसूल कर रहे हैं। ऐसे में कंपनी के पास जब नई गाड़ियों की प्लेट ऊंचे दाम पर बनाने का काम उपलब्ध है तो कंपनी क्यों पुराने वाहनों की प्लेट आधी कीमत पर बनाएगी।

कई राज्यों में इस प्रकार के बिना नंबर हाई सिक्युरिटी नंबर प्लेट के वाहन होने पर 5 हजार से लेकर 5500 तक का चालान बनाया जा रहा है। मप्र में पहले हाई सिक्युरिटी नंबर प्लेट लगाने वाली कंपनी को कोर्ट ने आदेश तो दिया है, लेकिन भाव पुराने होने से कंपनी का काम शुरू करना मुश्किल है। जानकारी के अनुसार देशभर में नए वाहनों पर 2019 से हाई सिक्योरटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य किया गया है। कई राज्यों ने पुराने वाहनों पर भी इसे अनिवार्य कर दिया है। जिसमें दिल्ली, उप्र, गुजरात आदि राज्य शामिल हैं। शुरुआत में इन प्रदेश में पंजीकृत वाहनों को इस दायरे में रखा गया था। लेकिन अब दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों के लिए भी इसे अनिवार्य कर दिया गया है। जिससे प्रदेश से दूसरे राज्यों में जाने वाले लोगों के सामने दिक्कत हो गई है। जिससे प्रदेश के वाहन चालकों के दूसरे राज्यों में चालान बन रहे हैं।

● **सुनील सिंह**

महिलाओं की मुफ्त ड्राइविंग ट्रेनिंग का खर्च अब केंद्र सरकार देगी

प्रदेश में पहली बार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार द्वारा 15 जनवरी से पहली बार महिलाओं को ड्राइविंग ट्रेनिंग की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत इंदौर के नंदानगर स्थित आईटीआई ग्राउंड पर परिवहन विभाग और आईटीआई विभाग मिलकर महिलाओं को निशुल्क ड्राइविंग की ट्रेनिंग देता है। बाहर से आने वाली महिलाओं के लिए यहां रहने और भोजन की भी मुफ्त व्यवस्था की जाती है। अब तक अलग-अलग बैच में 126 महिलाएं यहां से ट्रेनिंग ले चुकी हैं और ज्यादातर रोजगार से जुड़ चुकी हैं। हाल ही में केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत भी इस योजना को शामिल कर लिया गया है। अब इस योजना के तहत पहली बैच बनाकर 30 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। हर महिला की ट्रेनिंग पर आने वाला 18 से 21 हजार रुपए का खर्च केंद्रीय तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा कौशल भारत योजना के तहत उठाया जाएगा। योजना के तहत महिलाओं के आवेदन मंगवाए जा चुके हैं और जल्द ही ट्रेनिंग शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस ट्रेनिंग भी में परिवहन विभाग का सहयोग लिया जाएगा। परिवहन विभाग की योजना के तहत भी जल्द ही एक बैच शुरू की जाने की तैयारी है।

कुपोषण मुक्त होगा मप्र

मप्र में कुपोषण के कलंक को समूल नष्ट करने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। कुपोषितों को पोषण आहार मुहैया कराने के लिए जहां सरकार ने पोषण आहार संयंत्रों की जिम्मेदारी महिलाओं के हाथ में दे दी है, वहीं प्रदेश को कुपोषण के अभिशाप से मुक्ति दिलाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 10 साल की कार्ययोजना बनाई है। कार्ययोजना के अंतर्गत तीन स्लैब रखे गए हैं। पहला स्लैब वर्ष 2022, दूसरा वर्ष 2025 और तीसरा और अंतिम वर्ष 2030 तक का है। यानी 2030 तक मप्र पूरी तरह कुपोषण मुक्त राज्य बन जाएगा।

सबल एवं सशक्त राष्ट्र निर्माण के लिए बचपन का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। कुपोषण किसी भी राष्ट्र के लिए अभिशाप के समान है। हमारे देश में कुपोषण एक अभिशाप है। मप्र में कुपोषण की गंभीर स्थिति है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने पहले शासनकाल से ही कुपोषण को खत्म करने के लिए अभियान चला रहे हैं। इसका असर यह हुआ है कि आज मप्र में कुपोषण कंट्रोल में है। लेकिन मुख्यमंत्री इतने से संतुष्ट नहीं हैं। इसलिए उन्होंने प्रदेश को कुपोषण के अभिशाप से मुक्ति दिलाने के लिए 10 साल की कार्ययोजना बनाई है। इस कार्ययोजना के तहत सरकार और आमजन मिलकर कुपोषण को दूर भगाएंगे।

गौरतलब है कि एक दशक पहले तक मप्र की गिनती सबसे अधिक कुपोषित राज्य में होती थी। लेकिन आज मप्र की स्थिति सुधर गई है। अभी हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सूचना के अधिकार (आरटीआई) कानून के तहत पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में बताया है कि देश में 33 लाख से ज्यादा बच्चे कुपोषित हैं और इनमें से आधे से अधिक अत्यंत कुपोषित की श्रेणी (एसएएम) में आते हैं। कुपोषित बच्चों वाले राज्यों में महाराष्ट्र, बिहार और गुजरात शीर्ष पर हैं। यानी मप्र में कुपोषण के मामले में लगातार गिरावट आ रही है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर जो कार्ययोजना बनाई गई है, उसमें जनभागीदारी को **विशेष महत्व** दिया गया है। सरकार का प्रयास है कि जिस तरह कोरोना महामारी को जनभागीदारी से दूर किया गया, उसी तरह कुपोषण को भी समाप्त किया जाए। गौरतलब है कि कार्ययोजना के अंतर्गत तीन स्लैब रखे गए हैं। पहला स्लैब वर्ष 2022, दूसरा वर्ष 2025 और तीसरा और अंतिम वर्ष 2030 तक का है। इसमें सरकार योजनाबद्ध तरीके से साल दर साल कार्ययोजना का क्रियान्वयन कर आंकलन करेगी कि इसमें हमने क्या हासिल किया और क्या प्रयास किए जाने चाहिए सुनिश्चित किया जाएगा। इस कार्ययोजना की तीन स्तर पर मॉनीटरिंग की जाएगी। पहली राज्य स्तर यानी पूरे राज्य स्तर की मॉनीटरिंग होगी, दूसरी जिला स्तर यानी पूरे जिला स्तर की मॉनीटरिंग होगी और तीसरी ग्राम व नगरीय निकाय स्तर की मॉनीटरिंग होगी।

लेकिन केवल सरकारी प्रयास से ही कुपोषण के अभिशाप से मुक्ति नहीं मिल सकती है। इसमें आमजन की सहभागिता जरूरी है। क्योंकि स्वास्थ्य से जुड़े कारणों के अलावा इस समस्या के सामाजिक कारण भी हैं। कुपोषण तब होता है जब किसी व्यक्ति के आहार में पोषक तत्वों की सही मात्रा नहीं होती है। भोजन आपको स्वस्थ रखने के लिए ऊर्जा और पोषक तत्व प्रदान करता है। यदि आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिजों सहित पर्याप्त पोषक तत्व नहीं मिलते हैं तो आप कुपोषण से पीड़ित हो सकते हैं। कुपोषण के कई कारण हैं। इनमें से गरीबी कुपोषण का प्रमुख कारण है। इसके अलावा लड़का-लड़की के बीच का भेदभाव, कम उम्र में मां बनना, स्तनपान का अभाव बच्चों में कुपोषण की वजह है। और इन सबकी वजह है शिक्षा और ज्ञान की कमी। इसलिए प्रदेश सरकार ने कुपोषण के अभिशाप से मुक्ति का जो अभियान शुरू किया है उसमें हर एक **व्यक्ति को सहभागी** बनना होगा। अधिकांश लोगों, विशेषकर गांव, देहात में रहने वाले व्यक्तियों को संतुलित भोजन के बारे में जानकारी नहीं होती, इस कारण वे स्वयं अपने बच्चों के भोजन में आवश्यक वस्तुओं का

कुपोषित बच्चों को मिलेंगे मेवे से बने लड्डू

प्रदेश में कुपोषण दूर करने के लिए सरकार अब कुपोषित बच्चों को मेवे से बने लड्डू खिलाएगी। इसकी शुरुआत बड़वानी जिले से हो गई है। बड़वानी जिले के कुपोषित बच्चों को सुपोषित करने के लिए बाल शक्ति मिशन की शुरुआत की गई है। इसके साथ ही बड़वानी प्रदेश का पहला जिला बन गया, जहां पर कुपोषित बच्चों को ड्रायफ्रूट (मेवे) से बने लड्डू दिए जा रहे हैं। प्रभारी मंत्री हरदीपसिंह डंग ने मिशन की शुरुआत की है। जिले में अभी 1248 कुपोषित बच्चे हैं। जिले में एनआरसी केंद्र बनाए गए हैं, जहां बच्चों के साथ माताएं भी 14 दिन तक रहती हैं तो उन्हें शासन के द्वारा 14 दिन की मजदूरी दी जाती है और अब बाल शक्ति योजना के माध्यम से बच्चे की छुट्टी होने के दिन उसे 15 दिन के लिए 3 किलो ड्रायफ्रूट के लड्डू भी दिए जाएंगे। माताएं इन ड्रायफ्रूट के लड्डुओं को घर ले जाकर बच्चों को 200 ग्राम प्रतिदिन के मान से खिलाए तो बच्चा जल्दी सुपोषित होगा।

समावेश नहीं करते, इस कारण वे स्वयं तो इस रोग से ग्रस्त होते ही हैं साथ ही अपने परिवार को भी कुपोषण का शिकार बना देते हैं। इसलिए लोगों के बीच जागरुकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

कार्ययोजना के तहत कुपोषित बच्चों का निरंतर फॉलोअप लिया जाएगा। ताकि यह पता चल सके कि बच्चे की स्थिति क्या है। जानकारी के अनुसार, परिजन कुपोषित बच्चों का एक फॉलोअप करा रहे हैं। इसके बाद दूसरी और तीसरी फॉलोअप नहीं करा रहे हैं। इससे काफी संख्या में बच्चे कुपोषित ही रह जा रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में फिलहाल 10,84,948 बच्चे मध्यम कुपोषित और 1,19,574 अति कुपोषित हैं। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी एसआरएस के आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश में कुपोषण हर 1000 में से 46 बच्चों को लील लेता है। इनमें अधिकांश वे बच्चे होते हैं जिनके चारों फॉलोअप पूरे नहीं हो पाते हैं। सूत्र बताते हैं कि एक बार किसी तरह एनआरसी कुपोषित बच्चों के इलाज के लिए पहुंच जाते हैं। यहां पर 14 दिन तक इलाज के बाद वापस चले जाते हैं लेकिन दोबारा नहीं पहुंच रहे हैं। इससे दोबारा घर जाते ही फिर कुछ दिन बाद बच्चा कुपोषित हो जाता है। इसमें जहां एक ओर परिजनों की लापरवाही सामने आ रही है, वहीं दूसरी ओर मैदानी अमले की भी उदासीनता उजागर हो रही है।

यह हालत तब हैं जब कुपोषित बच्चों के साथ भर्ती माताओं को भत्ता भी मिलता है। कुपोषित बच्चों के परिजनों को एक फॉलोअप यानी 14 दिन के लिए 1680 रुपए क्षतिपूर्ति भत्ता मिलता है। दरअसल एनआरसी में कुपोषित बच्चों के साथ भर्ती माताओं को उचित समझाइश नहीं मिल रही है। इसके चलते वे बच्चों की स्वास्थ्य को लेकर गंभीर नहीं हो पा रही हैं और पूरे फॉलोअप नहीं करा रही हैं। दरअसल कुपोषित बच्चों के साथ उनके परिजन या माता भी बच्चों के साथ रहते हैं। इसमें उनके लिए खाने की सबसे बड़ी समस्या होती है। सुबह चाय और बिस्किट के बाद सीधे दोपहर में उन्हें खाना मिलता है। इस बीच सुबह दस बजे के करीब उनको खाना खाने के लिए बाहर जाना पड़ता है। इसकी वजह से काफी संख्या में परिजन फिर से बच्चों को लेकर नहीं आते हैं।

केंद्र सरकार द्वारा जारी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (एसआरएस) बुलेटिन के अनुसार शिशु मृत्यु दर (0 से 1 साल) के मामले मप्र की स्थिति भारत में सबसे ज्यादा खराब है। यह न केवल देश का सबसे कमजोर प्रदर्शन है, बल्कि विश्व मानक में भी मप्र की स्थिति 150 देशों से भी ज्यादा खराब है। यहां आज भी हर 1000 में से 46 बच्चे एक साल की आयु से पहले दम तोड़ देते हैं। राज्य के शहरी क्षेत्रों में शिशु मृत्यु दर 32 है और ग्रामीण क्षेत्रों में 50 है। यह हालात तब, जबकि 2018 की तुलना में स्थिति कुछ संभली भी है। 2020 में शिशु मृत्यु दर 48 थी। एसआरएस की 2020 की इस रिपोर्ट में रेफरेंस ईयर 2018 का था और हाल ही में आई 2021 की इस रिपोर्ट में 2019 के आंकड़े लिए गए हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-4 (एनएफएचएस-4) के अनुसार कुपोषण के तीनों पैमानों पर मप्र सबसे कमजोर 10 प्रदेश में शामिल है। 42 प्रतिशत बच्चे कम कद के, 25.8 प्रतिशत निर्बलता और 42.8 प्रतिशत में कम वजन के होते हैं। मप्र में 52.4 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं में एनिमिया की दिक्कत। इस वजह से आने वाली संतान में भी स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें ज्यादा हो जाती हैं। राज्य में जन्म के 1 घंटे में सिर्फ 36 प्रतिशत बच्चों को मां का पहला दूध (खीस) मिलता है, जो सबसे जरूरी है। राज्य में 20-24 साल की 18.4 प्रतिशत लड़कियों की शादी 18 साल से पहले हो जाती है। वहीं रूरल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार मप्र के ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों पर 298 और आदिवासी क्षेत्रों में 85 शिशुरोग विशेषज्ञों की कमी है।

रिपोर्ट के अनुसार मप्र में शहरों की तुलना में शिशु मृत्यु दर ज्यादा है। शहरी क्षेत्र में 32 संख्या है, जबकि गांवों में प्रति हजार पर 50 की संख्या है। प्रदेश में वर्ष 2014 में आईएमआर 52 थी, जो कि 6 साल में 46 तक आ गई। इसके पहले वर्ष 2009 में 67 रही थी। दूसरे राज्यों की तुलना में सुधार काफी कम हो सका है। उप्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र सभी अच्छी स्थिति में हैं। इन राज्यों में शिशु मृत्यु दर पर काफी अंकुश लग पाया है। केरल तो इतना अव्वल है कि वहां एक हजार शिशुओं में केवल 6 की मौत होती है।

● **नवीन रघुवंशी**

महिलाओं के जिम्मे पोषण आहार

गौरतलब है कि कुपोषण के कलंक को मिटाने के लिए सरकार हर साल अरबों रुपए खर्च करती है, लेकिन कुपोषण बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में कुपोषण के खिलाफ सरकार की जंग निरंतर जारी है। अब सरकार ने इस जंग की कमान महिलाओं के हाथ में दे दी है। यानी अब 97 हजार 135 आंगनबाड़ी केंद्रों के 97 लाख से ज्यादा बच्चों, गर्भवती एवं धात्री माताओं के स्वास्थ्य का जिम्मा महिलाएं संभालने जा रही हैं। प्रदेश में पोषण आहार बनाने के लिए सरकार ने सात (देवास, धार, होशंगाबाद, शिवपुरी, रीवा, मंडला और सागर) पोषण आहार संयंत्र स्थापित किया है। इन संयंत्रों की कमान महिला स्व-सहायता समूहों को दी जा रही है। ये महिलाएं हर माह सात सौ करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार करेंगी। महिलाओं के समूह ने देवास जिले के संयंत्र का काम संभाल लिया है। अगले चरण में समूहों को धार जिले का संयंत्र सौंप दिया जाएगा। इन संयंत्रों से होने वाली आमदनी की 95 फीसदी राशि संयंत्रों से जुड़े समूहों की महिला सदस्यों को लाभांश के रूप में दी जाएगी। जानकारी के अनुसार राज्य में 45 हजार गांवों में तीन लाख 33 हजार स्व-सहायता समूह हैं। इनसे 38 लाख परिवार जुड़े हैं। इनमें से ज्यादातर परिवारों को अब स्थाई रोजगार मिलने जा रहा है। कुछ परिवार की महिलाएं सीधे संयंत्रों से जुड़ेंगी, तो ज्यादातर महिलाओं को भविष्य में अपने क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्रों तक पोषण आहार पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। हालांकि इस पर अंतिम निर्णय अभी होना है। ज्ञात हो कि सात संयंत्रों के संचालन के लिए सात महासंघ बनाए गए हैं।

'लापरवाही' का नतीजा हमीदिया अस्पताल हादसा

एक साल से मिल रहे थे हादसे के संकेत

अपने जिन शिशुओं को लेकर माता-पिता ने तरह-तरह के सपने बुने थे। अभी उन्हें जी भर देखा तक नहीं था, गले लगाने की बात तो दूर थी। लापरवाह व्यवस्था के चलते उन मासूमों का शव कांपते हाथों में उठाना पड़ा। अस्पताल में कागजों में व्यवस्थाएं दुरुस्त रहीं, पर हकीकत में मरम्मत के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए। राजधानी परियोजना प्रशासन (सीपीए) ने मरम्मत के कामों में किस कदर लापरवाही की, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले वर्ष जनवरी में नवजात शिशु वार्ड की पूरी वायरिंग बदली गई थी, इसके बाद भी घटना के दिन प्लग लगाते वक्त शार्ट सर्किट हुआ। मरम्मत का काम पुख्ता नहीं होने का दूसरा उदाहरण यह है कि पिछले साल जनवरी से लेकर अब तक शिशु रोग विभाग की तरफ से नौ पत्र लिखे गए। 24 अगस्त 2020 को सीपीए को भेजे पत्र में साफ तौर पर इस बात का जिक्र था कि प्लगों में स्पार्किंग हो रही है। विभाग के पत्र के बाद सीपीए ने मरम्मत का काम तो किया, पर इसके बाद भी जनवरी से अक्टूबर तक नौ पत्र विभाग द्वारा वायरिंग मरम्मत के लिखा जाना इसका स्पष्ट प्रमाण है कि मरम्मत का काम तय मापदंडों के अनुरूप नहीं किया गया था।

भोपाल के हमीदिया अस्पताल के नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई में शार्ट सर्किट से आग लगने से मासूमों की मौत ने पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया है। शासन से लेकर स्थानीय प्रशासन तक कटघरे में है। प्रशासन ने आग की घटना में सिर्फ चार नवजात बच्चों की मौत की पुष्टि की है, लेकिन तथ्य तो इसके दोगुना से अधिक बच्चों के मरने के हैं। उनके माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल है। सरकार ने पूरे मामले की गहराई से जांच कराने का ऐलान किया है और इसके लिए स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव (एसीएस) मोहम्मद सुलेमान को जिम्मेदारी दी है लेकिन विपक्षी कांग्रेस इससे संतुष्ट नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एसीएस को जांच का जिम्मा देने पर यह कहकर सवाल उठाया है कि हादसे के लिए जो जिम्मेदार हैं वे ही जांच कैसे कर सकते हैं। जाहिर कांग्रेस इसमें अपनी राजनीति का नया रास्ता भी देख रही है। उसने सरकार पर सच छुपाने का आरोप लगाते हुए यह भी कहा है कि पिछले 48 घंटे में हमीदिया अस्पताल में 14 बच्चों की मौत हुई है। हालांकि घटना के तीसरे दिन सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए हमीदिया अस्पताल के अधीक्षक डॉ. लोकेंद्र दवे, गांधी मेडिकल कालेज के डीन डॉ. जीतेन शुक्ला, कमला नेहरू अस्पताल के संचालक केके दुबे को उनके पद से हटा दिया है जबकि राजधानी परियोजना प्रशासन की विद्युत शाखा के उपयंत्री अवधेश भदौरिया को निलंबित कर दिया है। फौरी तौर पर सरकार ने संदेश दिया है कि दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने से वह हिचकेगी नहीं।

फिलहाल सरकार इसे हादसा मान रही है, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार लोगों को चिन्हित करना अभी शेष है। जैसे-जैसे समय बीत रहा है घटना के पीछे लापरवाही की परतें भी खुलती जा रही हैं। यह कम चौंकाने वाला तथ्य नहीं है कि राजधानी के इस महत्वपूर्ण अस्पताल का फायर सेफ्टी ऑडिट नहीं हो रहा था। जबसे अस्पताल का भवन बना है तब से लेकर आज तक फायर एनओसी ही नहीं ली गई। जिस वार्ड में हादसा हुआ वहां वेंटीलेटर के प्लग लगाने के लिए पावर शाकेट नहीं लगे थे। वेंटीलेटर भी 8 साल पुराना था। इसके लिए चाहे जो तर्क दिए जाएं लेकिन सच यह है कि ऊपर से नीचे तक सुरक्षा से जुडे विषयों को गंभीरता से नहीं लिया गया। यह भी कम चौंकाने वाली बात नहीं है कि लगभग एक साल पूर्व इसी अस्पताल का निरीक्षण करने गए चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के सामने भी व्यवस्थागत लापरवाही की पोल खुली थी। वह हमीदिया के नए ओपीडी भवन में कोरोना मरीजों के लिए बनाए 20 बिस्तर के वार्ड में सुविधाओं का जायजा लेने पहुंचे थे। फायर कंट्रोल सिस्टम में उन्होंने बाहर से जंग लगा पाया था। मंत्री को सिस्टम के बंद होने की आशंका हुई तो उन्होंने अधिकारियों से इसे चालू करके दिखाने के निर्देश दिए। इसके बाद अधिकारी मोटर पंप कनेक्शन के स्विच वाले बाक्स में लगे ताले की चाबी खोजने लगे। 30 मिनट तक खोजबीन चली और मंत्री इंतजार करते रहे। आखिरकार चाबी नहीं मिली थी। तब मंत्री नाराज हुए थे और कहा था कि अनहोनी होने पर इसी तरह जब चाबी नहीं मिलेगी तो कितना बड़ा नुकसान होगा। मंत्री ने अधीक्षक, डीन और अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई थी और अस्पताल परिसर के सभी फायर कंट्रोल सिस्टम के ऑडिट के निर्देश दिए थे। इस निर्देश पर कितना काम हुआ, यह हमीदिया में हुए हादसे से पता चलता है। सवाल यह भी है कि हमीदिया में फायर सिस्टम को दुरुस्त करने का मंत्री ने निर्देश दिया था तो इस पर अमल क्यों नहीं हुआ। अस्पताल प्रबंधन सोता रहा तो शासन ने क्या किया। आखिर मंत्री को अपने ही निर्देश की याद क्यों नहीं आई! समय रहते यदि कदम उठाए गए होते तो शायद शिशु वार्ड में आग की इतनी बड़ी घटना से बचा जा सकता था।

जिस शिशु गहन चिकित्सा कक्ष में शार्ट सर्किट से आग लगी, वहां 24 घंटे डॉक्टर, नर्स एवं अन्य पैरामेडिकल स्टाफ की ड्यूटी लगाई जाती है। इतने लोगों की मौजूदगी वाले इस संवेदनशील कक्ष में आखिर आग इतनी जल्दी कैसे फैल गई। जाहिर है वहां कोई देखने वाला नहीं था। सबकी नजर तब पड़ी जब सब कुछ बर्बाद हो गया था। प्रदेश में इसके पहले भी अस्पतालों में आग लगने की घटनाएं होती रही हैं। जांच दल बनाए जाते रहे हैं। रिपोर्ट भी तैयार होती रही है। सुधार के लिए सिफारिशें होती रही हैं, लेकिन जिम्मेदारों को जितनी गंभीरता दिखानी चाहिए उतनी नहीं हो सकी है।

● **जितेंद्र तिवारी**

विवादों में अफीम की नई नीति

मप्र के मंदसौर, नीमच और रतलाम की काली मिट्टी में काला सोना यानी अफीम होती है। यहां के करीब 35 हजार किसान अफीम की खेती करते हैं। मप्र से सटे राजस्थान के इलाकों में भी अफीम की खेती होती है। सरकार के पट्टे के बिना कोई किसान खेती नहीं कर सकता है। मंदसौर व नीमच जिले की प्रमुख फसल अफीम की खेती में अब बदलाव की आहट शुरू हो गई है। इसके तहत अब ऑस्ट्रेलिया की तर्ज पर खेती शुरू की गई है। फिलहाल लगभग चार हजार किसानों को 6-6 आरी के हरे पट्टे दिए गए हैं। इनके खेतों में फसल से निकलने वाले डोडों से सीधे मशीन से सीपीएस पद्धति से अफीम निकाली जाएगी। मूलत: ऑस्ट्रेलिया में अफीम की खेती में प्रयोग हो रही इस पद्धति के अच्छे रिजल्ट मिले हैं। अफीम की अच्छी गुणवत्ता के लिए केंद्र सरकार भी काफी समय से इसे लागू करने की कोशिश में थी, लेकिन इसमें डोडाचूरा व पोस्तादाना नहीं मिलने से किसान विरोध कर रहे हैं।

नई अफीम नीति में केंद्र सरकार ने मार्फिन का 4.2 किग्रा प्रति हेक्टेयर से अधिक का औसत देने वाले किसानों को ही परंपरागत खेती के लिए पट्टे दिए हैं। वहीं एक नया प्रयोग करने के लिए 3.7 प्रतिशत से 4.2 प्रतिशत तक औसत वाले अपात्र किसानों को 6-6 आरी के हरे पट्टे दिए गए हैं। ये किसान डोडे नारकोटिक्स विभाग को सौंपेंगे। इन डोडों से बिना चिराई के सीपीएस पद्धति से अफीम निकाली जाएगी।

भारत में यह पहली बार होगा। सीपीएस पद्धति में खेती के लिए मंदसौर जिले में 2237 किसान शामिल हैं। हरे पट्टे के लिए कागज भी हरे रंग का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। 2237 में से करीब 400 ऐसे किसान शामिल हैं, जिनके पट्टे 2019-20 व 2020-21 में कट गए थे। अब सीपीएस पद्धति के तहत पट्टे वितरण किए जा रहे हैं। निर्देश प्राप्त हुए उसके संबंध में किसानों को जानकारी दी जा रही है। सीपीएस में किसानों को हरे कागज पर पट्टा दिया जा रहा है इसलिए इस पट्टे को हरा पट्टा कहा जा रहा है।

मंदसौर-नीमच जिले के किसान नई पद्धति से खुश नहीं हैं, क्योंकि अफीम के सह उत्पाद डोडाचूरा व पोस्तादाना से किसानों को एक सीजन में दो से तीन लाख रुपए तक आय होती है। सीपीएस पट्टे की पात्रता के लिए दो मापदंड तय किए गए हैं। पहला जिन किसानों ने वर्ष 2020-21 में 3.7 से 4.2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की औसत से मार्फिन दी। दूसरा 2019-20 तथा 2020-21 में पट्टे कटने वाले किसानों ने लगातार पट्टा रद्द होने वाले साल सहित पांच साल तक मार्फिन औसत 4.2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के 100 प्रतिशत या उससे अधिक दी हो।

ऑस्ट्रेलिया में अफीम की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए डोडे से कांसन्ट्रेट पापीस्ट्रा (सीपीएस) पद्धति से ही अफीम निकाली जाती है। इसी कारण वहां की अफीम की मांग अमेरिका, जापान व अन्य देशों की मेडिकल कंपनियां ज्यादा करती हैं। इसमें डोडे से सीधे अफीम निकालने की प्रक्रिया होती है। अभी कुछ देशों में यही प्रक्रिया चल रही है। भारत में अभी तक डोडे से पुरानी पद्धति लुणी-चिरनी से खेत में अफीम निकालने और उसे एकत्र कर नारकोटिक्स विभाग को देने की प्रक्रिया चल रही है। नारकोटिक्स विभाग नीमच व गाजीपुर में स्थित अल्केलाइड फैक्टरी में इस अफीम को प्रोसेस कर कोडीन फास्फेट, मार्फिन व अन्य उपयोगी उत्पाद अलग-अलग करते हैं।

उधर नई अफीम नीति के खिलाफ किसानों ने मोर्चा खोल दिया है। इस नीति के विरोध में मालवा किसान संगठन के बैनर तले किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। गौरतलब है कि अफीम किसान अफीम नीति को तर्क संगत बनाने की मांग को लेकर पिछले डेढ दशक से संघर्ष और आंदोलन की राह पर हैं। हर बार अफीम नीति जारी होने से पहले किसान दिल्ली भी कूच करते हैं और वहां अपनी पीड़ा भी बताते हैं। अपनी समस्याओं को लेकर अफीम काश्तकार हर साल सांसद के पास भी पहुंच रहे हैं और उन्हें आश्वासन भी मिल रहा है, लेकिन हर बार अफीम नीति जारी होने के बाद किसान खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि बरसों से वे अफीम की खेती करते आए हैं। अब साल दर साल अफीम नीति को पेचीदा बनाकर केंद्र सरकार किसानों को इस खेती से दूर कर रही है। कभी औसत तो कभी घटिया और वाटर मिक्स अफीम बताकर किसानों के पट्टे काटे जा रहे हैं। नारकोटिक्स विभाग में भ्रष्टाचार के मामले पहले ही सामने आ चुके हैं। इन सब के बावजूद किसानों की सुनने वाला कोई नहीं है। डेढ दशक से किसानों की आस सिर्फ और सिर्फ नेताओं के आश्वासन पर टिकी हुई है।

● **विकास दुबे**

किसानों को रास नहीं आई नई अफीम नीति

केंद्र सरकार की ओर से जारी नई अफीम नीति किसानों को रास नहीं आई है। किसानों का आरोप है कि हर बार उनकी अफीम को घटिया बताकर पट्टे काट दिए जाते हैं, लेकिन किसानों की अफीम घटिया नहीं है। किसानों ने बताया कि 11 अक्टूबर 2021 को घोषित नई अफीम नीति देश और किसान दोनों के साथ धोखा है। अफीम किसान संघर्ष समिति के संरक्षक मांगीलाल मेघवाल ने बताया कि किसानों की प्रमुख मांगों में वर्ष 1997-98 से 2021 तक घटिया, वाटर मिक्स, सस्पेक्टेड, औसत में कमी और कम मार्फिन जैसे कारण बताकर काटे गए पट्टे बहाल करने, अफीम का मूल्य अन्तरराष्ट्रीय मानकों पर तय करने, किसानों पर थोपा गया मार्फिन का नियम खत्म कर औसत आधार पर पट्टे जारी करने, वर्ष 2015 से 2021 तक नारकोटिक्स विभाग में हुए घपलों की सीबीआई जांच करवाने तथा एसीबी की ओर से पकड़े गए नारकोटिक्स विभाग के अधिकारियों का नारको टेस्ट करवाने की मांग शामिल है। इसके अलावा अफीम नीति 2021-22 निर्धारण में किसानों की सहभागिता से बनाने और सभी किसानों को एक समान दस-दस आरी के पट्टे देने की मांग शामिल है।

उप्र को 750 एमसीएम पानी देगा मप्र

केन-बेतवा लिंक परियोजना से उप्र को पानी देने की योजना पर मप्र सरकार कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव पारित कर मुहर लगाएगी। इसके तहत उप्र के बुंदेलखंड क्षेत्र को 750 एमसीएम (मिलियन क्यूबिक मीटर) पानी मप्र सरकार देगी। इस योजना को लेकर पहले ही दोनों सरकारों के बीच समझौता हो चुका है। मप्र के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा कि पानी बंटवारे को लेकर सहमति बन गई है। नए अनुबंध के तहत पानी बंटवारे को लेकर कैबिनेट की मंजूरी होना है। प्रस्ताव जल्द पारित हो जाएगा। जानकारी के अनुसार, नदी जोड़ो अभियान के तहत देश की पहली केन-बेतवा लिंक परियोजना की आधारशिला इस साल दिसंबर में रखी जा सकती है। इससे पहले पानी बंटवारे को लेकर हुए समझौते के तहत मप्र सरकार परियोजना से 750 एमसीएम पानी उप्र को देने का प्रस्ताव कैबिनेट से पारित करेगी। प्रस्ताव पारित होने के बाद परियोजना का भूमि पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। कार्यक्रम संभवत: झांसी (उप्र) में होगा।

इस परियोजना से बुंदेलखंड के बांदा, झांसी, महोबा, ललितपुर और हमीरपुर जिलों को पानी मिलने से यहां के किसानों को फसल की सिंचाई में काफी सहूलियत मिलेगी। साथ ही इस परियोजना से इस क्षेत्र की करीब 21 लाख आबादी को 67 मिलियन क्यूबिक मीटर पीने योग्य पानी उपलब्ध कराया जाएगा। इस परियोजना से पानी के बंटवारे को लेकर दोनों राज्यों के बीच 15 साल से चल रहे विवाद का पटाक्षेप मार्च 2021 में हुआ। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में परियोजना से उप्र को 750 एमसीएम पानी देने पर सहमति बन गई। अनुबंध पर दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के हस्ताक्षर भी हो चुके हैं। समझौते के मुताबिक, मप्र सरकार को उप्र को पानी देने के प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लगानी है। इसे लेकर तैयारी चल रही है। सूत्र बताते हैं कि समझौता हो चुका है, इसलिए कैबिनेट से मंजूरी मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कैबिनेट से प्रस्ताव पारित होने के बाद प्रधानमंत्री का कार्यक्रम तय होगा।

उल्लेखनीय है कि मप्र के पन्ना जिले में आकार लेने वाली परियोजना वर्ष 2005 में मंजूर हुई है। इसके तहत नजदीक से बहने वाली केन-बेतवा पर बांध बनेगा। शुरू में उप्र को रबी फसल के लिए 547 एमसीएम (547 अरब लीटर) और खरीफ फसल के लिए 1153 एमसीएम (1153 अरब लीटर) पानी देने का अनुबंध हुआ था। विवाद रबी फसल के लिए पानी देने को लेकर शुरू हुआ था। अप्रैल, 2018 में उप्र ने रबी फसल के लिए 700 एमसीएम (700 अरब लीटर) पानी की मांग की, जो बाद में 788 एमसीएम (788 अरब लीटर) तक पहुंच गई। सहमति के पहले ही उप्र ने जुलाई, 2019 में 930 एमसीएम (930 अरब लीटर) पानी का मांग रख दी। मप्र इतना पानी देने के लिए तैयार नहीं था। बांध से बिजली उत्पादन की भी योजना है। पूरी बिजली मप्र को ही मिलेगी। मंत्रालयीन सूत्रों के अनुसार केन-बेतवा लिंक परियोजना करीब 35,111 करोड़ रुपए की है। इसमें केंद्र सरकार 90 प्रतिशत राशि देगी, वहीं दोनों राज्य सरकारें पांच-पांच प्रतिशत राशि देंगी। केन बेसिन से उप्र में 2.27 लाख हेक्टेयर की सिंचाई होगी वहीं मप्र में 4.47 लाख हेक्टेयर की सिंचाई होगी। जबकि बेतवा बेसिन से मप्र में 2.06 लाख हेक्टेयर सिंचाई होगी।

उधर छिंदवाड़ा के माचागोरा डैम की अथाह जलराशि ने अपने प्रभाव वाले क्षेत्र को खेती में संपन्न तो बना दिया, लेकिन अब भी सिवनी और छिंदवाड़ा जिले की हजारों हेक्टेयर जमीन प्यासी है। जहां एक ओर तकनीकी खामी की वजह से नहरों के जरिए मिलने वाला पानी कई किसानों के खेतों तक नहीं पहुंच पा रहा तो वहीं भौगोलिक विषमता के कारण बांध से लगे करीब दर्जनभर गांव आज भी सिंचाई के साधनों की राह देख रहे हैं। दरअसल, खेतों तक सिंचाई के लिए नहर तो बना दी गई, लेकिन टूट-फूट और गुणवत्ताहीन काम की वजह से हर खेत तक पानी पहुंचाना किसी चुनौती से कम नहीं है। शुरुआती दौर में ही कहीं नहर तो कहीं पुलिया के निर्माण में कई तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। वहीं वर्ष 2017 में ही टेस्टिंग के दौरान नहर का कांक्रीट तक धराशायी होने का मामला सामने आ चुका है। बीते बारिश में कपुर्दा के समीप नहर का करीब एक किलोमीटर का हिस्सा धंस चुका है। इससे नहरों की गुणवत्ता का अंदाजा लगाया जा सकता है। वर्तमान में भी मुख्य नहरें क्षतिग्रस्त हैं। डिस्ट्रीब्यूटरी और सब-डिस्ट्रीब्यूटरी नहरें अब भी अधूरी हैं। हर बार सिंचाई से पहले नहरों को दुरुस्त करने का दावा जरूर किया जाता है, लेकिन यदि गुणवत्ता और तकनीकी पर जोर दिया जाता तो हर बार इसकी नौबत ही न आती। वहीं दूसरी ओर माचागोरा बांध की 20 से 25 किलोमीटर की परिधि में आने वाले करीब दर्जनभर गांवों के हजारों किसान भौगोलिक विषमता का दंश झेलने को मजबूर हैं।

● **बृजेश साहू**

बाणसागर के जल बंटवारे में इस साल कटौती

इस साल पिछले साल की तुलना में मप्र, उप्र और बिहार को बाणसागर का कम जल मिलेगा। वजह है, विंध्य क्षेत्र में कम बारिश। क्षेत्र में चालू वर्ष 2021 में जल का बंटवारा हो गया है। अफसरों की मानें तो हर साल 1 नवंबर की स्थिति में पानी का बंटवारा तीनों राज्यों के बीच हो जाता है। इसके अनुसार इस साल प्रदेश को बाणसागर से 1885.83 एमसीएम (मिलियन क्यूबिक मीटर) और उप्र-बिहार को 992.915-992.915 एमसीएम पानी दिया जाएगा। बता दें कि अंतरराज्यीय बाणसागर परियोजना के पानी में 3 राज्यों का हिस्सा है। बांध के अंदर भरे पानी में 50 प्रतिशत मप्र व 25-25 प्रतिशत पानी उप्र और बिहार को दिया जाता है। 15 अक्टूबर तक मानसून सत्र रहने के बाद 1 नवंबर को 3 राज्यों के मध्य पानी का बंटवारा किया जाता है। 1 नवंबर को बाणसागर का जलस्तर 339.97 मीटर था। जिसमें कुल 4417.24 एमसीएम पानी भरा था। गौरतलब है कि 1 नवंबर की स्थिति में बाणसागर का जो जलस्तर रहता है। उससे, 1 मीटर नीचे से बंटवारा किया जाता है। ऐसे में 339.97 मीटर जलस्तर होने पर 338.97 मीटर भरे पानी का विभाजन किया गया। जल स्तर के अनुसार बांध में 4417.24 एमसीएम की जगह 3971.66 एमसीएम पानी आया है, जबकि 446 एमसीएम पानी सालभर वाष्प से उड़ने के लिए छोड़ दिया गया। अंततः 3971.66 एमसीएम बचे पानी का तीनों राज्यों में विभाजन कर दिया गया। इसमें मप्र को 1850.53 एमसीएम और उप्र-बिहार को 992.915-992.915 एमसीएम पानी मिला।

विवादित कंपनी पर किसकी मेहरबानी

वाकई मप्र अजब है गजब है। यहां कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। ऐसा मप्र में ही हो सकता है कि जो कंपनी 'नाकाम' है उसे 3,000 करोड़ का काम देने की तैयारी चल रही है। वह कंपनी है मेघा इंजीनियरिंग। 950 करोड़ के टेंडर विवाद में उलझी मेघा इंजीनियरिंग को नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण का 3,000 करोड़ का टेंडर देने की खबर के बाद सवाल उठने लगे हैं कि आखिरकार इस कंपनी पर इतनी मेहरबानी क्यों?

गौरतलब है की मेघा इंजीनियरिंग का विवादों से पुराना नाता है। पूर्व में मेघा इंजीनियरिंग ज्वाइंट वेंचर में भी मात्र 400 और 550 करोड़ रुपए के दो काम समय में नहीं कर पाई। इस पर दो मामलों में 40 करोड़ और 55 करोड़ रुपए की पेनाल्टी लगी है। यही नहीं कंपनी ने मप्र सरकार को ही ट्रिब्यूनल में खड़ा कर दिया है। नर्मदा विकास प्राधिकरण उसी कंपनी को फिर से 3 हजार करोड़ का टेंडर अवार्ड करने जा रही है। गौरतलब है कि हाल ही में नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण ने नर्मदा की दो परियोजनाओं चिंकी बैराज और सनबर खरगौन के टेंडर जारी किए थे। अपने शुरूआती समय से ही विवादों में रहा यह टेंडर फिर से उन्हीं कंपनियों को दिए जा रहे हैं। विवादास्पद कंपनी का मामला अभी आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल में विचाराधीन है। इन मामलों में 25 नवंबर और 20 दिसंबर 2021 को अगली सुनवाई होनी है।

गौरतलब है कि जिस मेघा इंजीनियरिंग को नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण 3,000 करोड़ रुपए का टेंडर देने की तैयारी की जा रही है वह पूर्व में मिला काम समय सीमा में पूरा नहीं कर पाई थी। नर्मदा विकास प्राधिकरण ने 2013 में टर्नकी बेसिस पर अपर नर्मदा प्रोजेक्ट डिंडोरी का काम हैदराबाद की मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और प्रसाद एंड कंपनी लिमिटेड के ज्वाइंट वेंचर मेल-प्रसाद को दिया गया था। 402.80 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट की समय सीमा 36 महीने निर्धारित की गई थी। यानी यह प्रोजेक्ट 18 मार्च 2018 को समाप्त होना था, लेकिन समय सीमा में काम पूरा न किए जाने के चलते नर्मदा विकास प्राधिकरण ने अनुबंध की धारा 115.1 के अनुसार कंपनी पर 40.28 करोड़ रुपए की पेनाल्टी लगाई थी। साथ ही धारा 113-6 ई-आई के तहत मोबिलाईजेशन एडवांस पर ब्याज भी लगाया था। मुख्य अभियंता ने 20 जून 2016 को अनुबंध की धारा 32 एक के अनुसार अनुबंध को खत्म कर दिया था और परफॉरमेंस बैंक गारंटी को जब्त कर लिया था।

पूर्व में मिली योजनाओं को पूरा न करने वाली विवादित कंपनी को एक बार फिर से बड़ी योजनाएं सौंप दी गई हैं। जिस मेघा इंजीनियरिंग को लगभग 3 हजार करोड़ रुपए का काम सौंपा गया है, वह कंपनी सरकार को कोर्ट में घसीट चुकी है। ऐसे में सवाल उठता है, इस कंपनी पर किसकी मेहरबानी है।

निरस्त टेंडर की फिर बुलाई निविदा

गौरतलब है कि ये पूरा मामला 8393 करोड़ की दो परियोजनाओं का है। जिनको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा में तनातनी हो गई थी। तकनीकी आधार पर इन टेंडरों को निरस्त कर दिया गया था और फिर से निविदाएं बुलाई थी, लेकिन इस बार भी उन्हीं कंपनियों को उपकृत किए जाने के संकेत मिले हैं, जिन्हें पिछली बार टेंडर मिले थे। और दवाब की इंतहा यह है कि इस बार भी उन्हीं तीन कंपनियों के अलावा किसी अन्य ने टेंडर में भागीदारी नहीं की है।

मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और प्रसाद एंड कंपनी लिमिटेड के ज्वाइंट वेंचर मेल-प्रसाद पर की गई कार्रवाई के खिलाफ ठेकेदार ने प्राधिकरण के समक्ष 6 जून 2016 को अपील की थी। अपील में ठेकेदार ने लगाई गई पेनाल्टी को वापस लेने और यदि कॉन्ट्रैक्ट निरस्त किया जाता है तो परफॉरमेंस बैंक गारंटी वापस करने के निर्देश दिए जाने की अपील की थी, लेकिन प्राधिकरण ने सर्वेक्षण एवं भू-अर्जन के काम में देरी के लिए ठेकेदार को दोषी मानते हुए अपील को खारिज कर दिया। फिलहाल मामला आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल में आरसी 58/2017 विचाराधीन है। मामले में अगले सुनवाई 25 नवंबर को होनी है। वहीं खरगौन में लिफ्ट इरीगेशन परियोजना के तहत 28 मार्च 2011 को नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण से मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड व केबीए के ज्वाइंटर वेंचर ने अनुबंध किया था। यह प्रोजेक्ट 550 करोड़ रुपए का था और अंतिम रूप से इसे 2014 में पूरा होना था, लेकिन बाद में इसकी तीन बार समय अवधि बढ़ाते हुए 30 जून 2017 तक पूर्ण करने पर सहमति हुई थी। बताया जाता है कि कंपनी समय अवधि में काम पूरा नहीं कर सकी। इस पर नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण ने कंपनी पर 55 करोड़ रुपए की पेनाल्टी अधिरोपित की। यह मामला भी आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल में पिटिशन क्रमांक 119/2016 विचाराधीन है। मामले की अंतिम सुनवाई 20 दिसंबर 2021 को नियत है।

मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड एंड प्रसाद एंड कंपनी ज्वाइंटर वेंचर द्वारा डिंडोरी में लिए गए टेंडर एवं मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड एंड केबीए ज्वाइंट वेंचर द्वारा खरगौन में लिए गए टेंडरों के विवाद के बावजूद कंपनियों पर मेहरबानी किसी की समझ में नहीं आ रहा है। इस मामले में अधिकारी भी कुछ बोलने को तैयार नहीं हैं। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के मेंबर टेक्नीकल राजीव सुकलीकर का कहना है कि उन्हें इन मामलों की जानकारी नहीं है। उनसे जब पूछा गया कि कब तक जानकारी दे पाएंगे तो उन्होंने कहा कि इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। वहीं एक अन्य सदस्य आरके सिंहल ने कहा कि यह मामले उनके संज्ञान में नहीं है, साथ ही टेक्नीकल वालों से बात करने की सलाह दे डाली।

● **राकेश ग्रोवर**

किस काम का फसल बीमा

हर तरह के व्यवसाय में जोखिम उठाना शामिल होता है, लेकिन भारत में सिंचाई की कम उपलब्धता को देखते हुए खेती स्वाभाविक रूप से अधिक जोखिम भरा हो जाता है, क्योंकि यह इसे मौसमी परिस्थितियों में बदलाव, खास तौर पर बारिश जो या तो सूखे या फिर बाढ़ का कारण बनती है, के प्रति बहुत संवेदनशील बनाती है। 2015-16 में केवल 49 प्रतिशत कृषि भूमि ही सिंचाई के अधीन थी और इसमें भी फसलों के हिसाब से व्यापक भिन्नता थी।

फसल में होने वाले रोगों के कारण उत्पादन का नुकसान और साथ ही कृषि उत्पादन की कीमतों में अस्थिरता भी काफी अधिक बनी हुई है, जिसके परिणामस्वरूप कृषि आय में लगातार बदलाव (उतार-चढ़ाव) होता रहता है। खेती से जुड़े जोखिमों का सामना करने के लिए एक तरीका फसल बीमा लेना भी है। हाल ही में भारत के कुछ हिस्सों में बेमौसम भारी बारिश कई सारी मौतों और भारी विनाश का कारण बन रही है। हालांकि, कुल मिलाकर एक राष्ट्र के रूप में हम पिछले तीन वर्षों से मानसून के मामले में भाग्यशाली रहे हैं। दक्षिण-पश्चिम मानसून (जून-सितंबर के दौरान) का लगातार तीन साल तक सामान्य होना एक दुर्लभ घटना है। इस साल वर्षा के मौसम में होने वाली बारिश सामान्य रही है जबकि पिछले दो वर्षों में यह सामान्य से अधिक रही है। कोविड महामारी के कारण गैर-कृषि अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई, फिर भी कृषि क्षेत्र ने 3.6 प्रतिशत की वृद्धि के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था को और भी अधिक गर्त में जाने से बचाया।

पिछली बार सामान्य से कम दक्षिण-पश्चिम मानसून 2018 में देखा गया था, जब यह लंबी अवधि के औसत से 9 प्रतिशत कम था। हाल ही में जारी आंकड़ों से पता चलता है कि जुलाई से दिसंबर 2018 तक 40 प्रतिशत से अधिक किसानों को कई फसलों में नुकसान हुआ। अधिकांश मामलों में, इसका प्राथमिक/मुख्य कारण कम वर्षा या सूखा था, जिसके बाद फसल की बीमारी का नंबर था। लेकिन काफी अधिक जोखिम और सरकारी एजेंसियों द्वारा किए जा रहे लगातार प्रयासों के बावजूद भारत में फसल बीमा को कम अपनाया गया है। 2018-19 में बीमा के तहत आने वाला फसली क्षेत्र भारत सरकार द्वारा तय लक्ष्य, फसली क्षेत्र के 50 प्रतिशत को फसल बीमा के तहत लाने, की तुलना में सिर्फ 26 प्रतिशत था। यह स्थिति 2016 में नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा फसल बीमा योजनाओं में आमूलचूल परिवर्तन लाए जाने के बावजूद है, जब उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाय) की शुरुआत की और साथ ही मौजूदा योजनाओं, जैसे कि पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (रिस्ट्रक्चर्ड वेदर-बेस्ड क्रॉप इन्श्योरेंस स्कीम-आरडब्ल्यूबीसीआईएस), में भी काफी संशोधन किए थे। इन दोनों योजनाओं में पिछले साल भी फिर से काफी सारे सुधार किए गए हैं।

फसल बीमा को कम अपनाए जाने के कई कारण हैं, जिनमें पहला कारण 'फसल बीमा के बारे में जानकारी नहीं होना' और 'रूचि नहीं होना' शामिल हैं। यह तब है जब उस समय अनिवार्य आवश्यकता से अधिक बीमा कराने वाले आधे से अधिक कृषि परिवारों ने जून से दिसंबर 2018 तक ज्वार, मक्का, रागी, अरहर, मूंग, मूंगफली, सोयाबीन और यहां तक कि नारियल की फसल में भी नुकसान उठाया है। यहां एक अहम सवाल यह है कि अगर हम किसानों को फसल बीमा के बारे में जागरूक करें और उन्हें समझाएं कि उन्हें बीमा की जरूरत है, तो भी क्या उनके लिए फसल बीमा लेने का कोई मतलब है या फिर भी उनकी दिलचस्पी नहीं होगी?

किसी भी तरह का बीमा करवाना (फसल, स्वास्थ्य, दुर्घटना) खरीदार की ओर से एक तर्कसंगत निर्णय तभी होता है यदि बीमा के दावों को समय पर संसाधित किया (प्रोसेस्ड) और निपटाया जाता है। यदि अधिकांश दावे खारिज ही हो जाते हैं तो फिर लोगों (उपभोक्ताओं) को बीमा कवर लेने के लिए बहुत कम प्रोत्साहन मिलता है। फसल बीमा के संदर्भ में दावों के निपटाए जाने से संबंधित आंकड़े क्या दर्शाते हैं?

पिछले साल तक, अपने किसान क्रेडिट कार्ड पर ऋण लेने वाले सभी किसानों के फसल बीमा के प्रीमियम की राशि उनकी ऋण राशि में से अनिवार्य रूप से काट ली जाती थी। इसके अलावा कुछ किसान अपनी फसल का बीमा अलग से करते हैं न कि कृषि ऋण लेने के एक हिस्से के रूप में। 2018 की दूसरी छमाही के दौरान अतिरिक्त बीमा कराने वाले ऐसे किसानों में से 70 से 100 प्रतिशत किसानों (फसल के आधार पर भिन्न प्रतिशत) जिन्होंने फसल के नुकसान के लिए बीमा दावा किया, उन्हें कोई मुआवजा नहीं मिला। (फिगर-3)। सबसे अच्छी स्थिति बाजरे के किसानों की थी, जिनमें से 42 प्रतिशत ने अपने बीमा दावे के प्रति क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त की।

● **धर्मेंद्र सिंह कथूरिया**

अंतहीन देरी, कोई भुगतान नहीं

आखिर इस तरह से निराशाजनक रूप से कम बीमा दावा निपटान के क्या कारण हैं? दरअसल फसल बीमा के दावों को इसलिए खारिज नहीं किया जाता है क्योंकि वे योजना के दायरे से बाहर आते हैं या फिर किसानों द्वारा अपने पास मौजूद दस्तावेज खो दिए जाते हैं। लगभग सभी दावों को 'अन्य' कारणों से खारिज कर दिया जाता है। ये अन्य कारण इस बात से संबंधित हैं कि फसल बीमा योजनाओं को कैसे गठित, वित्त पोषित और कार्यान्वित किया जाता है। हाल के वर्षों में पीएमएफबीवाय के तहत राज्य सरकारों की ओर से देय प्रीमियम सब्सिडी के अपने हिस्से के भुगतान में देरी हुई है। इस योजना के तहत, केंद्र और राज्य सरकारें बीमा प्रीमियम पर सब्सिडी (अनुदान) प्रदान करती हैं, जिसका भुगतान ये सरकारें सीधे बीमा कंपनी को करती हैं। इसके बाद यह निर्णय लिया गया कि जिन राज्यों ने संबंधित बीमा कंपनियों को प्रीमियम सब्सिडी जारी करने में निर्धारित समय सीमा से अधिक की देरी की है, उन्हें इसके बाद वाले सीजन (सत्र) में इस योजना को लागू करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दरअसल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे राज्यों ने प्रीमियम सब्सिडी की ऊंची लागत का हवाला देते हुए इस योजना को ही छोड़ दिया जिससे कृषि बीमा कवर बढ़ाने के उद्देश्य को विफलता मिली है।

टाइगर स्टेट मप्र में बाघों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। इससे बाघों का निवास क्षेत्र छोटा पड़ने लगा है। हालांकि सरकार ने प्रदेश में 10 नए अभयारण्य और 3 नेशनल पार्क बनाने का खाका तैयार किया है, लेकिन अभी तक वह कागजों में है।

मप्र बढ़ते बाघ, घटता बसेरा

बाघों की गुर्राहट टकरा रही है। खुले जंगलों में विचरण करने वाले वनराज अब पगडंडियों पर हैं। लड़-झगड़कर बाघों ने समझौता कर लिया है। वे चिड़ियाघर के बाघों की तरह मिलकर रह रहे हैं। शावकों में भी जंगल का राजा बनने की कोई होड़ नहीं है। ये सब सुनने में अजीब लग सकता है, मगर हालात जस के तस रहे तो कुछ साल बाद टाइगर स्टेट के जंगलों की तस्वीर ऐसी ही हो जाए तो आश्चर्य की बात नहीं।

दरअसल, प्रदेश में जैसे-जैसे बाघ बढ़ते जा रहे हैं, वैसे-वैसे उनका बसेरा कम होता जा रहा है। शहरों का विस्तार और गांव के खेत जंगलों की हदों पर कब्जा कर रहे हैं। नतीजा यह है कि बाघ और अन्य जंगली जानवर आबादी वाले क्षेत्रों का रुख कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बाघों में क्षेत्र संघर्ष (टेरेटोरियल फाइट) भी छिड़ गया है। जानकारों के मुताबिक, एक बाघ का इलाका पांच सौ वर्ग किमी तक होता है और वह भी तब जबकि उसे भोजन, पानी और बाघिन उपलब्ध हों। बाघों के मौजूदा कुनबे के हिसाब से बाघों को इतनी जगह नहीं मिल रही है।

वैसे तो बाघ सघन जंगलों में रहते हैं, लेकिन बीते सात वर्षों में वे सामान्य जंगलों को भी अपना बसेरा बनाने लगे हैं। अब सतना, कटनी, भोपाल, शहडोल, देवास, रायसेन, सीहोर, बालाघाट, दमोह, विदिशा, बैतूल, खंडवा, इंदौर, हरदा, बुरहानपुर, डिंडोरी, श्योपुर जिले भी बाघों के घर बने हैं। वर्ष 2018 के बाद अब फिर से बाघों की गणना शुरू हो रही है। वर्ष 2018 के आंकड़ों के अनुसार, 526 बाघों के साथ प्रदेश देश में अव्वल था और वन्य जीव विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस बार यह संख्या 750 से अधिक हो सकती है। बीते तीन वर्षों में जंगलों का दायरा बढ़ाने की कोई बड़ी कोशिश नहीं हुई है। सघन, विरल, खुले वन मिलाकर 77482 वर्ग किलोमीटर है। इनमें से बाघों के लिए सिर्फ 42 हजार वर्ग किमी ही है, क्योंकि शेष खुले जंगलों में बाघ नहीं रहते हैं।

दरअसल, जंगलों में मनुष्यों की बसाहट बढ़ने से घास के मैदान घट रहे हैं। ऐसे में शाकाहारी वन्य जीव संकट में हैं और उनकी कमी होने पर बाघों का भोजन सिमट रहा है। वहीं वन क्षेत्रों में खनिज संपदा भी छिपी हुई है और सरकारें उत्खनन करना चाहती हैं। ऐसे में बाघों के जीवन में खलल पैदा हो रहा है। वहीं प्रदेश में दस साल में करीब पांच बड़ी परियोजनाएं आई हैं। इसमें हजारों हैक्टेयर जमीन वनों से गई। भरपाई के लिए सरकार पैसा और जमीन देती है, लेकिन वन तैयार होने में 20 साल लग जाते हैं और दो साल के अंदर इन परियोजनाओं के लिए वनों की कटाई हो जाती है। उधर लकड़ी और वन संपदा पर माफिया की निगाह है। वे अंदर ही अंदर जंगलों को खोखला कर रहे हैं। इसकी भरपाई संभव ही नहीं। हालांकि प्रदेश में दस अभयारण्य और तीन नेशनल पार्क का प्रस्ताव तैयार है। इसे अमल में लाया जाए। श्योपुर, सीहोर, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, मंडला, हरदा, इंदौर, नरसिंहपुर, सागर और श्योपुर अभयारण्य के लिए प्रस्तावित हैं। वहीं, ओंकारेश्वर, रातापानी और मानधाता नेशनल पार्क के लिए चिन्हित किए गए हैं। बाघ प्रदेश की सीमाओं में बंधे नहीं हैं और वे पड़ोसी राज्यों में जा रहे हैं। ऐसे में जंगलों के कॉरिडोर पर राष्ट्रीय स्तर पर ठोस चर्चा की जानी चाहिए। वन क्षेत्रों में बसे आदिवासियों को भरोसे में लेकर उन्हें संरक्षित करके जंगलों को बचाया जाए। विशेषज्ञों का कहना है कि बाघ परियोजनाओं पर बजट बढ़ाया जाए क्योंकि बीते तीन वर्षों से राशि पर्याप्त नहीं मिल रही है। इससे जंगलों के विकास और संरक्षण के काम प्रभावित हो रहे हैं।

बाघों की संख्या के मामले में मप्र अपना अव्वल दर्जा देश में कायम रख पाएगा या नहीं, यह तो अगले साल प्रस्तावित बाघों की देशव्यापी गणना के बाद तय होगा, पर प्रदेश के जंगलों से अच्छे संकेत मिलने लगे हैं। वन विभाग की आंतरिक गिनती में प्रदेश के टाइगर रिजर्व में वर्ष 2018 की तुलना में औसतन पांच से 60 फीसदी तक बाघ बढ़ गए हैं। ये आंकड़े भरोसा दिलाते हैं कि मप्र देश में सबसे ज्यादा बाघ वाले राज्य (टाइगर स्टेट) के रूप में पहचान कायम रखेगा। प्रदेश के पांच नेशनल पार्क, 24 अभयारण्य और 63 सामान्य वनमंडलों में दो साल में 100 से ज्यादा बाघ बढ़े हैं। इसके अलावा 45 से ज्यादा शावक हैं, जो अगले साल गिनती शुरू होने तक एक वर्ष की उम्र पार कर लेंगे और गिनती में शामिल हो जाएंगे।

● श्याम सिंह सिकरवार

एक साल में जन्मे हैं 100 से ज्यादा शावक

वन मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार, बीते तीन साल में मप्र में देश में सबसे ज्यादा 80 बाघों की अलग-अलग कारणों से मौत हुई। इनमें से आधे से ज्यादा बाघों ने टेरिटोरियल फाइट में अपनी जान गंवाई। इधर, बीते एक साल में 100 से ज्यादा शावक जन्मे भी हैं। प्रदेश के टाइगर रिजर्व में बाघ आंकलन फेज-4 के तहत पिछले साल आंतरिक गणना की गई थी। इसके हाल में सामने आए उत्साहजनक आंकड़ों ने वन विभाग में नई उम्मीदों का संचार कर दिया है। यदि इसी अनुपात में बाघों की संख्या बढ़ी, तो आगामी गणना में बाघों की संख्या 660 के आसपास होगी। हालांकि वर्ष 2018 में कर्नाटक में 524 और मप्र में 526 बाघ गिने गए थे। दोनों में बड़ा अंतर नहीं है इसलिए वन विभाग को सावधानी बरतनी होगी। पहले तो बाघों की मौत के ग्राफ को कम करने की कोशिश करनी होगी, जो मॉनीटरिंग बढ़ाकर ही संभव है। वहीं तकनीक का अधिकतम उपयोग कर प्रत्येक बाघ को गिनने का प्रयास करना होगा।

चुनावी मुद्दा बनेंगे अन्ना पशु

बुंदेलखंड में खेती घाटे का सौदा मानी जाती है। यहां सिंचाई जितनी बड़ी समस्या है, उससे भी विकट समस्या यहां के अन्ना (आवारा) पशु हैं, जो खेतों में खड़ी किसान की फसल को चट कर जाते हैं। योगी सरकार ने बुंदेलखंड में गोशालाएं तो खुलवाईं, लेकिन इसके बावजूद अन्ना पशुओं पर प्रभावी नियंत्रण नहीं किया जा सका है। अन्ना पशुओं से किसान आज भी हलकान हैं। बुंदेलखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में अन्ना पशु एक बार फिर चुनावी मुद्दा बन सकते हैं। महोबा जिले के जैतपुर विकासखंड के महेवा समेत दर्जनों गांव ऐसे हैं, जहां के किसानों की पूरी रात अन्ना पशुओं को डंडा लेकर हांकने में निकल जाती है। किसान अगर रातभर जागकर चौकीदारी न करें तो अन्ना पशु उनकी सारी फसल चट कर जाएं। ऐसे किसान पशुओं से फसल को चट होने से बचाने के लिए शिफ्टों में खेतों पर चौकीदारी करने को मजबूर हैं।

बुंदेलखंड के सात जिलों महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, झांसी, ललितपुर और जालौन में सरकारी गणना के मुताबिक, 23 लाख 50 हजार पशु हैं। जिनमें सबसे ज्यादा बदहाल स्थिति गायों की है। गाय जब तक दूध देती है, तब तक पशुपालक उसे अपने घर में रखता है। उसके बाद उसे घर के खूंटे या गोशाला में बांधने के बजाय छुट्टा छोड़ देता है। पशुपालक को दूध न देने वाली गाय को घर पर रखना और उसके लिए चारे का इंतजाम करना भारी पड़ता है। ऐसे आवारा पशु खेतों में खड़ी फसल को उजाड़ देते हैं। अन्ना पशुओं की समस्या लंबे अरसे से बुंदेलखंड में अभिशाप बनी हुई है। चित्रकूट मंडल में सरकारी स्तर पर 1,29,385 गोशालाओं में पशु संरक्षित हैं, जबकि दो लाख 16 हजार से ज्यादा पशुओं को गोशाला में रखने का लक्ष्य था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, लगभग 90 हजार पशु अभी भी छुट्टा घूम रहे हैं।

भले गाय को लोग माता कहते न थकते हों, लेकिन बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा बेकदरी गाय की है, जबकि भैंस, बकरी, गधा, खच्चर और सुअर को लेकर इतने बुरे हाल नहीं हैं। ये आज भी इनको पालने वालों की कैश प्रापर्टी कहलाते हैं। रातभर जागकर अन्ना पशुओं से फसल बचाने के लिए खेतों में रखवाली कर रहे किसान इन आवारा पशुओं से आजिज आ चुके हैं। महेवा के किसान उत्तम सिंह के अनुसार, अन्ना पशुओं पर सरकार प्रभावी अंकुश नहीं लगा पाई है। इस बार के चुनावों में किसान इस मुद्दे को ध्यान में रखकर वोट डालेगा। बुधौरा के किसान हरीसिंह के अनुसार, प्राकृतिक आपदाओं से किसान को जूझना पड़ता है। अन्ना पशु मानव जनित आपदा है। जिस पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकता है। सरकार के चलताऊ रवैए से इस समस्या से निजात नहीं मिल सकता है। उनके अनुसार बुंदेलखंड में अन्ना पशु बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगा, क्योंकि किसान अन्ना पशुओं से बुरी तरह हलकान है। बम्हौरी के किसान देवपाल के अनुसार, अब किसानों को वादों का लॉलीपॉप देकर नहीं बहलाया जा सकता है। बुंदेलखंड का किसान मेहनतकश है। यहां की मिट्टी भी उपजाऊ है। यदि अन्ना पशुओं पर लगाम लग जाए तो किसान को बहुत सारी समस्याओं से निजात मिल सकती है। साथ ही खेती भी लाभकारी सौदा साबित हो सकती है। इस बार के चुनावों में अन्ना पशुओं को लेकर मुद्दा फिर गर्म रहने की संभावना है।

गोवंश से चार गुना ज्यादा आबादी वाले बुंदेलखंडी गो माता के प्रति लापरवाह हैं। चार बुंदेलियों पर एक गोवंश का औसत है। इसके बाद भी पूरे बुंदेलखंड में अन्ना प्रथा चरम पर है। जिसे मां के नाम से पुकारा जाता है उस गोमाता को अन्ना से जाना जा रहा है। प्रदेश की तुलना में बुंदेलखंड में मात्र 12 फीसदी ही गोवंश हैं। पिछली पशु गणना के मुताबिक, उप्र में गोवंशीय पशुओं की संख्या 1,95,57,067 है, जबकि बुंदेलखंड के सातों जिलों बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, जालौन, झांसी और ललितपुर में 23,50,882 गोवंश हैं। यह 12.2 फीसदी हैं। सबसे ज्यादा 4,83,033 गोवंश ललितपुर जिले में हैं। धर्मनगरी चित्रकूट जनपद में गोवंशों की संख्या 4,21,332 है। दूसरी तरफ बुंदेलखंड की जनसंख्या 96,81,552 (वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक) है। मौजूदा समय में आबादी का आंकड़ा एक करोड़ से भी ज्यादा हो गया है। बुंदेलखंड में प्राचीन समय से ही गोवंश पालने की प्रथा रही है। खासकर ग्रामीण इलाकों में शायद ही कोई घर ऐसा हो जहां गाय-भैंस न हों, लेकिन पिछले कुछ दशकों से इस परंपरा में बड़ा बदलाव आया है। बुंदेलखंडी गोवंश को घाटे का सौदा मान बैठे हैं। हालांकि, इसके पीछे खेती की दुर्दशा और अक्सर आ रहीं दैवी आपदाएं भी कारण हैं। इन परिस्थितियों का सबसे ज्यादा खामियाजा गायों को भुगतना पड़ रहा है। भैंस और बैल की स्थिति ठीक है।

● **सिद्धार्थ पांडे**

सड़कों पर गाय, गोशालाओं में करोड़ों खिलाए

अन्ना पशु की सड़कों पर भरमार है। दूसरी तरफ पशुपालन विभाग इन्हें गोशालाओं में संरक्षित बताकर करोड़ों रुपए का चारा-भूसा खिलाने का खेल खेल रहा है। बीते 28 माह में चित्रकूटधाम मंडल के चारों जिलों बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट और महोबा में गोशालाओं में पशुओं के भरण-पोषण पर 58 करोड़ 92 लाख 37 हजार रुपए खर्च हुए हैं। बांदा जिले में 26 करोड़ 7 लाख, चित्रकूट जिले में 8 करोड़ 94 लाख, महोबा जिले में 12 करोड़ 70 लाख और हमीरपुर जिले 11 करोड़ 13 लाख रुपए खर्च बताया गया है। चित्रकूटधाम मंडल में पशुपालन विभाग के कागजी आंकड़ों के मुताबिक, 1,29,385 पशु गोशालाओं में संरक्षित हैं। इनके अलावा चारों जनपदों में 8615 अन्ना पशुओं को किसानों-ग्रामीणों की सुपुर्दगी में सौंपा गया है। इसमें हमीरपुर जिले 3477, महोबा जिले में 2447, बांदा जिले में 561 और चित्रकूट जिले में 2130 अन्ना गायें शामिल हैं।

राजद्रोह का प्रावधान समाप्त करना जरूरी

दुबई में भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच में पाकिस्तान की विजय के बाद देश के कुछ हिस्सों में जश्न मनाने वाले युवकों के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज होने के साथ ही एक बार फिर ब्रिटिशकाल का यह दमनात्मक कानून चर्चा में है। कानून की किताब में शामिल राजद्रोह के प्रावधान के बारे में हम इसके ब्रिटिशकाल का काला कानून होने या लोकतांत्रिक व्यवस्था में इसके लिए कोई स्थान नहीं होने जैसी टिप्पणियां करते रहें लेकिन इस प्रावधान को हटाना आसान नहीं लग रहा है, मौजूदा दौर में न्यायपालिका अक्सर इस कानूनी प्रावधान पर नए सिरे से विचार करने पर जोर दे रही है तो दूसरी ओर सरकार इसे निरस्त करने के पक्ष में नहीं है। वह इसका दुरुपयोग रोकने के लिए उचित दिशा-निर्देश बनाने के पक्ष में है। इस कानूनी प्रावधान के भविष्य का तो पता नहीं लेकिन इस समय यह कानून लागू है और भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच के बाद की घटनाओं के सिलसिले में कुछ व्यक्तियों के खिलाफ इसके तहत मामला भी दर्ज किया गया है।

दूसरी ओर, यह भी सच है कि हाल ही उच्चतम न्यायालय ने केरल के एक मामले में आरोपी को राजद्रोह के आरोप से मुक्त करने के उच्च न्यायालय के एक आदेश को तकनीकी आधार पर निरस्त कर दिया है। भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच में पाकिस्तान की विजय के बाद कुछ युवकों के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज किए जाने पर शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश दीपक गुप्ता ने इस पर असहमति व्यक्त की है, न्यायमूर्ति गुप्ता का मानना है कि निश्चित रूप से यह राजद्रोह नहीं है और यह अदालत में टिक नहीं पाएगा। इससे पहले, शीर्ष अदालत के ही एक अन्य न्यायाधीश आरएफ रोहिंग्टन ने भी सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद एक कार्यक्रम में राजद्रोह कानून से असहमति व्यक्त की थी।

न्यायमूर्ति नरीमन ने विश्वनाथ पसायत स्मारक समिति के एक समारोह में भारतीयों और स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ ब्रिटिश हुकूमत द्वारा इस कानून के दुरुपयोग का जिक्र करते हुए शीर्ष अदालत से अनुरोध किया था कि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) कानून, 1967 के आपत्तिजनक अंश और राजद्रोह को अपराध की श्रेणी में रखने वाली भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए निरस्त किए जाएं। न्यायमूर्ति नरीमन ने कहा कि शीर्ष अदालत को इन आपत्तिजनक प्रावधानों को कानून की किताब से हटाने का मामला सरकार पर नहीं छोड़ना चाहिए बल्कि उसे न्यायिक समीक्षा के अपने अधिकार का इस्तेमाल करके इसे निरस्त कर देना चाहिए ताकि नागरिक ज्यादा खुलकर सांस ले सकें।

न्यायमूर्ति नरीमन ने कहा था कि राजद्रोह का प्रावधान भारतीय दंड संहिता के मसौदे में था, लेकिन इसे अंतिम संहिता में शामिल नहीं किया गया था। उन्होंने दावा किया कि इसका पता बाद में लगा और इसे फिर से तैयार किया गया। दलील यह दी गई थी कि यह नजरअंदाज हो गया था। इसके शब्द भी अस्पष्ट थे। धारा 124ए के तहत सजा भी बहुत अधिक थी क्योंकि इसमें आजीवन देश निकाला और तीन साल की कैद का प्रावधान था।

नरीमन ने कानून की किताब में यूएपीए को शामिल किए जाने की परिस्थितियों का भी जिक्र किया और कहा कि चीन और पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध हो चुका था। इसके बाद ही बेहद कठोर प्रावधान वाला गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून लागू किया गया। इसमें अग्रिम जमानत का कोई प्रावधान नहीं था जबकि इसके तहत न्यूनतम सजा पांच साल की थी। यह कानून अभी तक न्यायिक समीक्षा के दायरे में नहीं है लेकिन राजद्रोह के कानूनी प्रावधान के साथ ही इस पर भी गौर करने की आवश्यकता है। इस समय, राजद्रोह के अपराध से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं शीर्ष अदालत में लंबित हैं। इनमें दावा किया गया है कि राजद्रोह के अपराध से संबंधित प्रावधान से संविधान के अनुच्छेद 19 (1) में प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का हनन होता है और केंद्र तथा राज्य सरकारें इसका दुरुपयोग कर रही हैं। यह मामला फिलहाल 14 दिसंबर, 2021 के लिए सूचीबद्ध है।

भारतीय दंड संहिता के इस प्रावधान को भाजपा नेता अरुण शौरी, किशोरचंद्र वांगखेमचा, कन्हैया लाल शुक्ला, पेट्रीसिया मुखिम और 'कश्मीर टाइम्स' की मालिक अनुराधा भसीन, एडीटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, गैर सरकारी संगठन कॉमन कॉज और मानवाधिकार कार्यकर्ता मेजर-जनरल (अवकाशप्राप्त) एसजी वोम्बटकेरे आदि ने चुनाती दे रखी है। लेकिन, इस बीच, न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की पीठ ने स्टेट ऑफ केरला एंड ओआरएस बनाम रूपेश प्रकरण 29 अक्टूबर, 2021 को कानूनी विसंगति के आधार पर फिर से विचार के लिए वापस केरल उच्च न्यायालय भेज दिया। राजद्रोह से संबंधित इस मामले में अब उच्च न्यायालय की खंडपीठ को इस पर विचार करना है। राजद्रोह से संबंधित इस मामले में उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने माओवादियों से कथित तौर पर संबंध रखने के आरोप में गिरफ्तार एक व्यक्ति को राजद्रोह सहित आतंकवाद रोधी कानून और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) कानून के तहत तीन मामलों में आरोप मुक्त कर दिया था।

● **राजेश बोरकर**

यह है प्रावधान

धारा 124ए में प्रदत्त राजद्रोह की परिभाषा के अनुसार अगर कोई व्यक्ति सरकार विरोधी सामग्री लिखता या बोलता है या ऐसी सामग्री का समर्थन करता है जिससे असंतोष पैदा हो तो यह राजद्रोह है, जो एक दंडनीय अपराध है। लेकिन सवाल यह है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब हमारा संविधान प्रत्येक व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है तो सरकार विरोधी सामग्री लिखने या बोलने अथवा ऐसी किसी सामग्री का समर्थन राजद्रोह कैसे हो जाएगी। यह विडंबना ही है कि न्यायपालिका द्वारा अनेक व्यवस्थाओं के माध्यम से राजद्रोह के बारे में राय व्यक्त किये जाने के बावजूद आज भी राज्यों में पुलिस प्रशासन विरोधियों के खिलाफ राजद्रोह के मामले दर्ज करने से गुरेज नहीं करता है। यह दीगर बात है कि अदालत में पहुंचने पर आरोपियों के खिलाफ राजद्रोह के आरोप न्यायिक समीक्षा के दौरान टिक नहीं पाते हैं और अभियोजन को बार-बार शर्मसार होना पड़ता है। उम्मीद है कि शीर्ष अदालत पुलिस द्वारा घड़ी-घड़ी आरोपियों के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज करने की प्रवृत्ति पर अंकुश के लिए सख्त दिशा-निर्देश देगी ताकि राजनीतिक विरोधियों से हिसाब-किताब बराबर करने के लिए इस कानून का दुरुपयोग न हो।

गड्ढों में भोपाल

टैक्स भरपूर... सुविधाएं दूर

देश के दिल मप्र की राजधानी भोपाल को पिछले 20 साल से पेरिस बनाने के वादे और दावे किए जा रहे हैं, लेकिन आज भी स्थिति यह है कि यहां विकास अनियंत्रित, अव्यवस्थित और भेदभावपूर्ण हो रहा है। मानसून की बारिश, स्मार्ट सिटी योजना, अमृत योजना, मेट्रो रेल परियोजना के कारण शहर में खराब हुई सड़कों, विकास के नाम पर जगह-जगह खुदाई के कारण ऐसा लगता है जैसे भोपाल गड्ढे में है। सड़कों की मरम्मत और गड्ढों की भराई में भेदभाव इस कदर है कि वीआईपी क्षेत्र चकाचक हैं, जबकि आम आदमी गड्ढे में है।

● राजेंद्र आगाल

देश में अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए ख्यात मप्र की राजधानी भोपाल कभी राजाभोज, कभी दोस्त मोहम्मद खान, कभी गोंड महारानी कमलापति, कभी आबिदा सुल्तान, कभी भोपाल गैस त्रासदी के लिए सुर्खियों में रहा है। लेकिन इन दिनों यह शहर अनियंत्रित तथा भेदभावपूर्ण विकास और गांवों से भी जर्जर सड़कों के कारण सुर्खियों में है। यह स्थिति तब है जब शहर की करीब 20 लाख आबादी से भरपूर टैक्स लिया जा रहा है। लेकिन विडंबना यह है कि सर्वाधिक टैक्स देने वाली निजी कॉलोनियों और वहां के लोगों को सुविधाओं के नाम पर छला जा रहा है। आमजन से विभिन्न प्रकार के विकास का टैक्स लेकर वीआईपी कॉलोनियों को सजाया और संवारा जा रहा है। सरकार से लाखों रुपए की पगार लेने वाले साहेबान सरकारी कॉलोनियों में ऐश कर रहे हैं वहीं टैक्स देने वाले आम लोग धूल, कचरा और गड्ढों से युक्त कॉलोनियों में रहने को मजबूर हो रहे हैं।

हवाई जहाज से जब दूसरे प्रदेश या विदेश का व्यक्ति भोपाल आता है तो ऊपर से यहां का प्राकृतिक सौंदर्य देखकर मोहित हो जाता है। वाकई भोपाल का प्राकृतिक सौंदर्य मनमोहक है भी। लेकिन जब वही व्यक्ति शहर के रहवासी क्षेत्रों में जाता है तो उसे भोपाल रेशम के कपड़े में लगे पेबंद जैसा नजर आता है। यह भोपालवासियों के लिए ही नहीं बल्कि सरकार के लिए भी शर्म की बात है। जिस शहर के विकास के लिए अकेले नगर निगम करीब 2600 करोड़ रुपए का बजट स्वाहा करता है, उस शहर में गड्ढ़े, गंदगी और धूल का गुबार यह दर्शाता है कि यहां का विकास केवल कागजों में हो रहा है। हां, वही व्यक्ति जब चार इमली, 74 बंगला, 45 बंगला, अरेरा कॉलोनी क्षेत्र में जाता है तो उसे अहसास होता है कि वाकई वह स्मार्ट सिटी में आ गया है। शहर के विकास में यह भेदभाव वाकई चिंता का विषय है।

विकास में भेदभाव

भोपाल भ्रमण करने पर ये साफ नजर आता है कि वाकई मप्र अजब है, गजब है। इसकी वजह यह है कि एक तरफ भोपाल सुंदर, आकर्षक, हरी-भरी और व्यवस्थित कॉलोनियों वाला शहर नजर आता है, वहीं दूसरी तरफ विकास के गड्ढ़े नजर आते हैं। हैरानी की बात यह है कि राजधानी में विकास का यह भेदभाव आज से नहीं बल्कि वर्षों से चला आ रहा है। लेकिन इस पर न तो शासन और न ही प्रशासन ने कोई कदम उठाया है। हैरानी की वजह यह है कि मानसून के कारण जब पूरे शहर की सड़कें खराब होती हैं तो सड़कों की मरम्मत और गड्ढ़ों की भराई में भी भेदभाव इस कदर होता है कि वीआईपी क्षेत्र चकाचक नजर आता है, जबकि आम आदमी गड्ढ़े में। यह स्थिति तब है जब शहर की आम कॉलोनियों के लोग सबसे अधिक टैक्स दे रहे हैं, जबकि वीआईपी कॉलोनियों से नगर निगम को कुछ नहीं मिलता। राजधानी में आम आदमी से तो भरपूर टैक्स लिया जा रहा है, लेकिन सुविधाएं वीआईपी क्षेत्रों को दी जा रही है। इस कारण जहां चार इमली, 74 बंगला, 45 बंगला, अरेरा कॉलोनी क्षेत्र में विकास नजर आ रहा है, वहीं आम आदमी वाली कॉलोनियों की पहचान टूटी सड़क, खुदी सड़क, उड़ती धूल, सड़कों पर अंधेरा बन गया है। जब राजधानी भोपाल में यह हाल है तो अन्य क्षेत्रों का क्या होगा?

70 फीसदी नौकरशाहों का अपना आवास फिर भी सरकारी में निवास

राजधानी भोपाल में एक विडंबना यह भी है कि यहां सबसे अधिक विकास वीआईपी क्षेत्रों में होता है। इसकी वजह यह है कि इन क्षेत्रों में मंत्री, विधायक, सांसद, आईएएस, आईपीएस के सरकारी आवास हैं। हैरानी की बात यह है कि सरकार जिन अफसरों के आवास पर सालाना करोड़ों रुपए खर्च करती है, उनमें से 70 फीसदी के अपने मकान भोपाल में हैं। लेकिन सरकारी सुविधाओं के आदी हो चुके ये अफसर अपने निजी मकान में जाने की बजाय सरकारी मकान में ही रहते हैं। इसकी वजह यह है कि जिन क्षेत्रों में इनके सरकारी मकान हैं, यानी चार इमली, 74 बंगले और 45 बंगले में सबसे अधिक विकास पर खर्च होता है। यहां की सड़कें सालभर चकाचक रहती हैं। घरों में बराबर पानी आता है। सड़कों की सफाई निरंतर होती है। फॉगिंग बराबर होती है। स्ट्रीट लाइट कभी भी दगा नहीं देती है। मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन की तर्ज पर अफसर सरकारी आवासों में रह रहे हैं। इसके लिए उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। वहीं जो अफसर या आम आदमी निजी कॉलोनियों में रह रहे हैं, उन्हें कई तरह के टैक्स तो देने पड़ रहे हैं, लेकिन सुविधाएं नदारद हैं।

शहर की सड़कों की रिपेयरिंग में भी वीआईपी और आम ट्रीटमेंट नजर आ रहा है। जहां से मंत्री, विधायक या अफसर गुजरते हैं, वहां तो सड़क पर डामर की परत बिछाई जा रही है, लेकिन जिन सड़कों से आमजन गुजरते हैं, उनके गड्ढ़े भी सही ढंग से नहीं भरे जा सके हैं। वीआईपी ट्रीटमेंट वाली सड़कों में मंत्रालय और चार इमली का हिस्सा प्रमुख है। दूसरी ओर शाहपुरा, कोलार, अयोध्या बायपास, बावड़ियाकलां, होशंगाबाद रोड, कोहेफिजा, दानिश नगर, इंद्रपुरी, आनंद नगर, करोंद, भोपाल टॉकीज के सामने आदि इलाकों में सड़कें अब तक चकाचक नहीं हो पाई है।

300 से अधिक कॉलोनियां गड्ढ़ायुक्त

मानसून की विदाई के बाद भी शहर की उखड़ी, टूटी, खुदी व खराब सड़कें वैसी की वैसी हैं। इस साल मानसून की बारिश से 300 से अधिक कॉलोनियों के लोग दिक्कत में आ गए हैं। इनमें 60 फीसदी कॉलोनियां कोलार में हैं। बाकी नेहरू नगर, भदभदा क्षेत्र, करोंद, बैरागढ़, पुराने शहर, गोविंदपुरा व कटारा हिल्स से जुड़ी हुई कॉलोनियां हैं। यहां बीते एक साल के दौरान सड़क खुदाई से लेकर नाली निर्माण के काम हुए हैं। यहां काम करने के बाद सड़क दुरूस्त नहीं की गई, जिससे अब रिमझिम बारिश में यहां सड़क से बाहर पड़ी धूल-मिट्टी कीचड़ में बदल गई। कुछ सड़कों पर तो बड़े गड्ढ़े हो गए। कुछ सड़कों पर कीचड़ फिसलन की बड़ी वजह बन गया। लोगों को बेहद संभलकर जाना पड़ रहा है। यहां थोड़ी सी लापरवाही दुर्घटना का कारण बन रही है। कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां दो साल से सड़कें खोदी हुई हैं। निर्देश के बावजूद ठेका एजेंसी दुरूस्त नहीं कर रही। बारिश के बाद हर बार यहां कीचड़ और इससे लोगों को परेशानी की स्थिति बनती है। कोलार की राजहर्ष कॉलोनी, प्रियंका नगर, ललिता नगर, नम्रता नगर, सनखेड़ी रोड, वंदना नगर से लेकर मिसरोद, बावड़िया, गुलमोहर से जुड़ी कॉलोनियां हैं। शाहपुरा में तो निगमायुक्त बीते दो माह में तीन बार निरीक्षण कर खुदी सड़कों को दुरूस्त करने का कह चुके, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। सड़कें दुरूस्त रहे इसके लिए निर्माण एजेंसी की सिविल शाखा जिम्मेदार है। शहर के अंदरूनी गलियों, मोहल्लों की सड़कों में कीचड़

इंग्लैंड की तरह निजी कॉलोनियों में क्यों नहीं रहते नौकरशाह?

मप्र सहित पूरे देश में विडंबना यह है कि नौकरशाह सर्व सुविधायुक्त सरकारी कॉलोनियों में रहते हैं। अगर वे निजी कॉलोनियों में आमजन के साथ रहते तो उन्हें समस्याओं का भान होता। इंग्लैंड की नौकरशाही सबसे पुरानी है। लेकिन वहां कोई सरकारी कॉलोनी नहीं है। वहां अफसरों को हाउस रेंट दिया जाता है। जिससे वे निजी कॉलोनियों में किराए के मकान में रहते हैं। ऐसे में वे आम लोगों की तरह सभी समस्याओं का सामना करते हैं। भारत में भी अफसरों को हाउस रेंट दिया जाता है। गौरतलब है कि भारत में इंग्लैंड के ही कायदे-कानून लागू हैं। ऐसे में अगर सरकार सरकारी मकानों की व्यवस्था को खत्म कर दे तो यहां के अफसर भी आमजन के साथ रहने लगेंगे। ऐसे में वे कम से कम क्षेत्रीय समस्या का समाधान तो कर सकते हैं।

की स्थित अधिक है। इसके लिए संबंधित जोन के कार्यपालन यंत्री-डिप्टी सिटी इंजीनियर, सहायक यंत्री सिविल जिम्मेदार है।

बारिश में बह गई सड़कें

भोपाल में नगर निगम, पीडब्ल्यूडी, बीडीए और सीपीए (राजधानी परियोजना प्रशासन) की करीब 4700 किलोमीटर सड़कें हैं। इनमें से लगभग 50 प्रतिशत सड़कें बारिश के कारण जर्जर हो गई हैं। इन्हीं सड़कों को लेकर जहां सियासत गरमा गई है तो वहीं लाखों लोग परेशान हो रहे हैं। कोलार की कई सड़कों पर पैदल चलना तक मुश्किल है तो पुराने शहर के भोपाल टॉकीज, हमीदिया रोड और करोंद में भी सड़कें गड्ढ़ों में गायब हो गई हैं। सीवरेज और कोलार ग्रेविटी लाइन की खुदाई होने से कोलार गेस्ट हाउस से बैरागढ़ चिचली तक सड़क पूरी तरह से उखड़ी हुई है। कुछ जगह ही पक्का पेचवर्क हुआ है, जबकि बाकी में गिट्टी और मिट्टी डालकर लीपापोती कर दी गई है। बीमाकुंज से बैरागढ़ चिचली तक का हिस्सा सबसे ज्यादा जर्जर है। रायसेन रोड के इंद्रपुरी, आनंद नगर में सड़क पर ढेरों गड्ढ़े हैं। होशंगाबाद रोड पर मिसरोद तक सड़क पर बड़े-बड़े गड्ढ़े हो चुके हैं। वहीं पुराने शहर में हमीदिया रोड, भोपाल टॉकीज, घोड़ा नक्कास, लोहा बाजार, नवबहार सब्जी मंडी, करोंद में हालत ठीक नहीं है। उधर, कमला पार्क के पास सड़क गड्ढ़ों में गायब हो गई है। शाहपुरा चौराहे से बंसल हॉस्पिटल तक सड़क जर्जर है। बावड़ियाकलां के मुख्य मार्ग पर कीचड़ और गड्ढ़ों के कारण लोगों का गुजरना मुश्किल हो गया है। बता दें कि राजधानी की सड़कों के बहाने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अरुण यादव समेत कई नेताओं ने सरकार को घेरा था। इसके बाद ताबड़तोड़ नगर निगम, पीडब्ल्यूडी ने अपनी सड़कों की सुध ली। हालांकि, पेचवर्क के नाम पर ईंट के टुकड़े और गिट्टी-मुरम गड्ढ़ों में भरी गई है, जो गाड़ियों के पहियों के साथ सड़कों पर फैलकर राहगीरों के लिए और बड़ी मुसीबत बन गए हैं। नगर निगम कमिश्नर केवीएस चौधरी का कहना है कि निगम की सड़कों का पेचवर्क कराया जा रहा है। कोलार में सीवेज और पाइप लाइन के काम के बाद सड़क की बेहतर तरीके से मरम्मत करने के निर्देश ठेकेदार को दिए गए हैं। लेकिन आज तक सड़कों की स्थिति जस की तस है। कहीं-कहीं मिट्टी और मुरम से गड्ढ़े भरने की कोशिश भी की गई है, लेकिन अब वही मिट्टी और मुरम परेशानी का सबब बन गई है।

जोनवार प्राप्त राजस्व

क्षेत्र	प्राप्त राजस्व
जोन क्रमांक-1	3,07,61,668
जोन क्रमांक-2	2,91,36,189
जोन क्रमांक-3	89,51,867
जोन क्रमांक-4	2,13,91,701
जोन क्रमांक-5	2,17,90,157
जोन क्रमांक-6	2,38,04,396
जोन क्रमांक-7	5,17,32,980
जोन क्रमांक-8	1,68,93,647
जोन क्रमांक-9	11,44,50,792
जोन क्रमांक-10	1,87,76,749
जोन क्रमांक-11	1,24,97,962
जोन क्रमांक-12	3,67,72,926
जोन क्रमांक-13	8,68,63,505
जोन क्रमांक-14	3,96,93,560
जोन क्रमांक-15	5,32,69,190
जोन क्रमांक-16	4,96,85,895
जोन क्रमांक-17	2,45,25,408
जोन क्रमांक-18	6,48,03,775
जोन क्रमांक-19	3,72,31,882

इन मदों से हुई आय

संपत्तिकर	74,30,34,248
कचरा कलेक्शन	4,39,80,596
जल कर	19,03,03,077
होर्डिंग्स शुल्क	1,36,65,943
पार्किंग शुल्क	26,79,676
मनोरंजन कर	1,14,200
बिल्डिंग परमीशन शुल्क	4,26,70,433
कॉलोनी सेल	6,96,76,858

सीवरेज की फजीहत

नगर निगम का दावा है कि शहर के सभी बड़े नालों का चैनेलाइजेशन हो चुका है, लेकिन वास्तविकता यह है कि शहर के 789 छोटे-बड़े नालों का चैनेलाइजेशन पिछले 14 सालों में 130 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी नहीं हो पाया है। नगर निगम सालाना 20 करोड़ रुपए स्टॉर्म वाटर ड्रेन नेटवर्क डेवलपमेंट और मेंटेनेंस पर खर्च करता है। साथ ही बारिश पूर्व नालों की सफाई में 20 लाख रुपए से ज्यादा खर्च होते हैं। इसके बावजूद शहर में कई जगहों पर अब भी जलभराव की स्थिति बनती है। इधर, अगर बीते पांच साल की बात करें, तो नगर निगम स्टॉर्म वॉटर नेटवर्क पर 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम खर्च कर चुका है। तीन साल पहले अमृत योजना के तहत 125 करोड़ रुपए की लागत से नाला चैनेलाइजेशन अधूरा काम दोबारा शुरू कराया गया, लेकिन ये भी अब तक पूरा नहीं हो सका है।

बता दें कि शहर में छोटे-बड़े 789 नालों सहित मुख्य पांच नालों के चैनेलाइजेशन प्रोजेक्ट को भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय ने 26 मई 2006 को मंजूरी दी थी। योजना के तहत संजय नगर, शाहपुरा, स्लाटर हाउस, पातरा व साउथ टीटी नगर के सात हजार 250 मीटर लंबे

मेट्रो और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के चलते खुद गई आम सड़कें

शहर में दो बड़े प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी और मेट्रो रेल चल रहे हैं। शहर को स्मार्ट बनाने के लिए 1,247 करोड़ के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। पूरे काम या तो आधे-अधूरे हैं या फिर गड्ढ़े में हैं। जो प्रोजेक्ट पूरे हो गए हैं वे भी बदहाल हैं। खासकर स्मार्ट सिटी की सड़कों का हाल सबसे अधिक बदहाल है। मुख्यमंत्री निवास से करीब एक किलोमीटर की दूरी पर बने स्मार्ट रोड का हाल देख लीजिए। इस स्मार्ट रोड का उद्घाटन शिवराज सिंह चौहान ने 11 महीने पहले ही किया है। पहली बारिश के मौसम में ही यह सड़क उखड़ने लगी। बारिश की वजह से सड़कें खराब होती हैं लेकिन यह कोई आम सड़क नहीं है। इसके निर्माण पर करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं। भोपाल के डिपो चौराहे से लेकर पॉलिटेक्निक चौराहे तक की दूरी 2.2 किलोमीटर है। यह स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आता है। इसके आसपास मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री तक के आवास हैं। मुख्यमंत्री ने 25 दिसंबर 2016 को इसके निर्माण के लिए भूमिपूजन किया था। सड़क के निर्माण में करीब 43 करोड़ रुपए की लागत आई है। आप सोच रहे होंगे कि इतनी छोटी सड़क के निर्माण पर इतनी राशि कैसे खर्च हो गई है। वहीं मेट्रो प्रोजेक्ट का भी हाल बेहाल है। राजधानी भोपाल में 2023 के अंत तक मेट्रो शुरू करने का वादा पूरा होता नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में मेट्रो रूट का सिविल वर्क ही 2023 तक पूरा हो जाए तो यह बड़ी बात होगी। दरअसल मेट्रो रूट की बाधाएं तो एक अलग बात है, लेकिन इसमें बड़ा मुद्दा बजट के इंतजाम का है। बता दें कि 7 साल पहले 2014 में भोपाल मेट्रो की लागत 6,941 करोड़ आंकी गई थी, लेकिन ये बढ़कर अब 9,000 करोड़ होने का अनुमान जताया जा रहा है। क्योंकि इन 7 सालों में काफी बदलाव हुआ है, यहां तक के इस दौरान कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी महंगा हुआ है। रुपयों के मुकाबले डॉलर भी मजबूत हुआ। अब साल दर साल जिस तेजी से पेट्रोलियम व अन्य चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं, ऐसे में प्रोजेक्ट लागत बढ़ने की आशंका साफ नजर आ रही है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार का बजट और मेट्रो के लोन आदि का गणित बिगड़ना स्वाभाविक है।

नालों का चैनेलाइजेशन 30 करोड़ 57 लाख रुपए की लागत से कराया जाना था। बड़े नालों का चैनेलाइजेशन करने के बाद इनमें छोटे नालों को कनेक्ट किया जाना था। चैनेलाइजेशन के तहत नालों की कांक्रीट लाइनिंग के जरिए डिजाइन इंबेकमेंट निर्माण शुरू हुआ, लेकिन 14 साल बाद भी काम पूरा नहीं हो सका है। अमृत योजना के तहत कुल 225 करोड़ रुपए की लागत से नालों का निर्माण कर उनका चैनेलाइजेशन किया जाना है। निगम ने पहले चरण में विभिन्न कॉलोनियों के 15 से अधिक नाले-नालियों को अमृत योजना में शामिल किया है। ये वह नाले हैं जिनकी वजह से जलभराव की समस्या होती है।

43 करोड़ की स्मार्ट सिटी सड़क

33 प्रतिशत अधिक राजस्व

भोपाल की सड़कों की बदहाली की यह तस्वीर तब है, जब नगर निगम को राजधानी में इस बार 33 प्रतिशत अधिक राजस्व मिला है। एक अप्रैल से लेकर 31 अगस्त तक नगर निगम ने करीब 137.46 करोड़ रुपए संपत्ति कर और जलकर सहित अन्य कर से कमाए हैं। जबकि पिछले साल 2020 में इसी अवधि के दौरान 91.19 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था। इस तरह देखा जाए तो नगर निगम अफसरों ने पिछले साल के मुकाबले 33 प्रतिशत अधिक राजस्व कमाया है। इसमें सबसे ज्यादा राजस्व जोन क्रमांक 9 के जोनल अधिकारी ने दिया है। वहीं दूसरे नंबर पर जोन क्रमांक 13 के जोनल अधिकारी ने सबसे ज्यादा अब तक राजस्व दिया है। जोन क्रमांक 18 के जोनल अधिकारी तीसरे नंबर पर है। इसके अलावा सबसे कम राजस्व जोन क्रमांक तीन का रहा है। इस बार अधिक राजस्व प्राप्त होने के पीछे कारण रहा अधिभार में दी जाने वाली छह फीसदी की छूट। हालांकि अभी वित्तीय वर्ष समाप्त होने में करीब चार माह का वक्त शेष है। तब तक यह आंकड़ा 300 करोड़ के पार होने की संभावना है।

नगर निगम ने नामांतरण के लिए तीन माह की अवधि तय की है। इसके बाद नामांतरण नहीं कराने पर अधिभार वसूला जाएगा। चार महीने के अंदर नामांतरण नहीं कराने पर 10 प्रतिशत और देरी होने पर 15 प्रतिशत का अधिभार लगाया जाएगा। नामांतरण के लिए फीस 2500 रुपए तय है और अब तक कोई समय सीमा नहीं थी। यही कारण है कि 4000 से ज्यादा मामले अब तक नामांतरण के आ चुके हैं। इन सभी मामलों को लेकर अब नामांतरण के लिए नगर निगम विशेष अभियान चला रहा है। बता दें कि हाल ही में शहर के 4000 से अधिक लोगों को नोटिस थमाया गया है, जिसमें स्टांप शुल्क जमा करने की बात कही गई है। बता दें कि सालाना 20 हजार नामांतरण होते हैं। बता दें कि प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने के बाद नगर निगम में संपत्ति कर और जलकर के खाते में नामांतरण की तरफ ज्यादातर लोग ध्यान नहीं देते हैं। बरसों तक संपत्ति कर और पानी के बिल पुराने मालिक के ही नाम आते रहते हैं। कई बार एक ही प्रॉपर्टी तीन से चार बार बिक जाती है और निगम को किसी एक का ही शुल्क मिल पाता है।

सिलेक्टिव विकास पर विवाद

जिन सड़कों से मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायकों की लाखों की कार गुजरती थी, वहां सड़कों के गड्ढों वाले मुंहासे डामर के फेशियल से ढंके जाने लगे और जिन सड़कों से आम आदमी की किश्तों पर खरीदी गई गाड़ियां गुजरती हैं, उन्हें वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया। यानी सड़क बनेगी तो पहले वीआईपी, जैसे आम आदमी को तो धक्का खाना किस्मत में लिखा हो। भोपाल से रायसेन जाने वाली सड़क पर आम आदमी को स्लिप डिस्क हो जाए, गाड़ी गड्ढ़े में गिर जाए,

हाथ टूट जाए, मुंह फूल जाए। गाड़ी का पुर्जा-पुर्जा हिले चाहे आम आदमी की हड्डी का, मुख्यमंत्री के आदेश के बाद भी यहां नजरें इनायत करने अफसर नहीं आते। यदि आपको अपनी कॉलोनी या शहर में अच्छी सड़कें चाहिए तो आपको वीआईपी होना बेहद जरूरी है। यह हम नहीं कह रहे बल्कि प्रदेश में ऐसा ही हो रहा है। इस कड़वी हकीकत को साबित करने वाली एक चर्चित खबर 11 अक्टूबर को सुर्खियां बनी थी, जिसके अनुसार गुना जिले प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को गड्ढ़ों से भरी सड़कों पर झटके लगे तो उनके एक फोन पर गुना में एबी रोड पर आनन-फानन में पेचवर्क शुरू कर दिया गया। इतना ही नहीं पीडब्ल्यूडी के जिम्मेदार अफसरों ने नाराज मंत्रीजी को भरोसा दिलाया कि गुना बायपास के खराब हिस्से को अगले ही दिन दुरुस्त करवा दिया जाएगा। आपको बता दें कि सिस्टम के वीआईपी सिंड्रोम से पीड़ित होने का यह कोई दुर्लभ उदाहरण नहीं है बल्कि यह हर जगह हो रहा है। राजधानी भोपाल भी इससे अछूती नहीं है। यहां भी आम और खास के बीच भेदभाव किया जा रहा है। सरकार को हर सेवा और सुविधा के लिए अपनी जेब से टैक्स अदा करने वाली आम जनता की सड़कों के गड्ढ़े वेस्ट मटेरियल यानी कचरे से भरे जा रहे हैं। जबकि जनता के टैक्स के पैसों से बड़ी सैलरी और मुफ्त सुविधाएं लेने वाले बड़े नेता-अफसरों की सड़कों की सरफेस उखड़ने पर भी उन्हें करोड़ों रुपए खर्च कर नए सिरे से बनाकर चमकाया जा रहा है। राजधानी भोपाल में 6 अक्टूबर से शुरू हुए सड़क के गड्ढ़ों को भरने के काम में खुलेआम ऐसा ही भेदभाव किया जा रहा है।

60 प्रतिशत सड़कें अब भी बदहाल

राजधानी की खूबसूरती पर दाग लगा रही सड़कों की तस्वीरें अभी भी नहीं बदल पाई है। अभी भी 60 प्रतिशत सड़कें खराब हालत में हैं, जबकि 6 से 20 अक्टूबर के बीच में सड़कें 100 प्रतिशत सुधर जानी चाहिए थीं। तत्कालीन कमिश्नर कवींद्र कियावत ने तीनों निर्माण एजेंसी पीडब्ल्यूडी, नगर निगम और सीपीए को हर हाल में रिपेयरिंग करने को कहा था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। कई इलाकों में तो सिर्फ मिट्टी और चूरी डालकर गड्ढ़े भर दिए गए। इस कारण धूल के गुबार उड़ रहे हैं और एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है। गड्ढ़ों और खराब सड़कों के कारण अयोध्या बायपास, कोलार, हमीदिया रोड जैसे भारी ट्रैफिक वाले इलाकों में रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं।

सितंबर में तत्कालीन कमिश्नर कियावत को तीनों एजेंसियों ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इसमें नगर निगम की करीब 288 सड़कें खराब होना बताई गई थी। इनमें से 24 सड़कें गारंटी पीरियड में बताई गई थी। जिनकी मरम्मत का जिम्मा ठेकेदारों पर है। वहीं, अन्य सड़कों की रिपेयरिंग में 70.30 करोड़ रुपए खर्च होने का स्टीमेट तैयार किया गया था। पीडब्ल्यूडी और सीपीए (राजधानी परियोजना प्रशासन) की सड़कें भी खराब हालत में थी। दोनों एजेंसियों ने भी सड़कों की रिपोर्ट दी थी। 6 अक्टूबर से रिपेयरिंग शुरू की गई। पीडब्ल्यूडी ने कोलार और हमीदिया रोड की सड़कों की रिपेयरिंग कराई, लेकिन कई हिस्से छोड़ दिए। इसके पीछे अफसरों का तर्क है कि सीवेज और पानी की लाइन खुदाई के कारण कुछ हिस्सा छोड़ा गया है। निगम के काम की रफ्तार शुरुआत से ही धीमी है। अब तक 40 प्रतिशत तक रिपयेरिंग का काम ही हो सका है। इधर, सीपीए मंत्रालय, चार इमली समेत अपने हिस्से की सड़कें सुधार रहा है, लेकिन 15 दिन में रिपेयरिंग का काम पूरा नहीं हो सका। अभी चार इमली और मंत्रालय के पास वाली सड़क पर डामर की परत बिछाई जा रही है। यह हालात तब है कि जब खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सड़कों में गड्ढ़ों पर नाराजगी जताते हुए तत्काल गड्ढ़ों को भरने के निर्देश दिए थे।

मेंटेनेंस का सालाना बजट है 20 करोड़, कागजों में हो रहा काम

राजधानी में मानसून के महीनों में हरियाली और तालाबों की खूबसूरती तो बढ़ गई, पर सड़कें बद से बदतर हो चली हैं। लावारिस छोड़ दी गईं, इन सड़कों पर पैदल चलना भी दूभर हो रहा है। बारिश के बाद कलेक्टर ने दो बार सड़कों को लेकर बैठक की, इसके बाद भी एजेंसियां जनता को राहत नहीं दे पाईं। अधिकारी निर्देश सुनकर चले जाते हैं, उन पर अमल नहीं करते। यहां तक की पेचवर्क भी शुरू नहीं किया गया। शहर में नगर निगम के पास 3 हजार 879 किलोमीटर की सड़कें हैं। इसी तरह पीडब्ल्यूडी के पास 531 और सीपीए के पास 132 किमी सड़कें हैं। इसमें से निगम की 800 किमी सड़कें खराब हो चुकी हैं। पीडब्ल्यूडी की 50 किमी तो सीपीए की 16 किमी की सड़कें गड्ढ़े में हैं। सड़कों के रखरखाव के लिए नगर निगम ने 12 करोड़, पीडब्ल्यूडी ने 3 करोड़ और सीपीए ने 5 करोड़ का बजट रखा है।

भोपाल विकास प्राधिकरण

विज्ञापन क्रमांक 2610/सम्पदा/भोविप्रा/ 21 भोपाल दिनांक 2/11/21

प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में स्थित सम्पत्ति के ऑफर एवं नियत मूल्य पर ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित

प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में स्थित सम्पत्ति के ऑफर एवं नियत मूल्य दर पर ऑनलाईन आमंत्रित रिक्त सम्पत्ति जैसे :- भूखण्ड/प्रकोष्ठ/डूप्लेक्स/हॉल/पी.एस.पी भूखण्ड/दुकानें, जो कि निम्न तालिका में वर्णित होकर ऑन लाईन ऑफर वेबसाइट https://vikaspradhikaran.mponline.gov.in के माध्यम से नियत दर/प्रस्ताव दिनांक 03/11/2021 से दिनांक 21/11/2021 तक आमंत्रित किये जाते हैं। निर्धारित अवधि में प्राप्त ऑफर/आवेदन पत्र दिनांक 22/11/2021 को खोले जावेंगे।

निम्न सम्पत्तियों का विस्तृत विज्ञापन प्राधिकरण की वेबसाइट www.bda.org.in पर देखे जा सकते है।

क्र.	योजना का नाम	ऑफर /नियत दर	सम्पत्ति का विवरण	सम्पत्ति की संख्या	रिमार्क
1	नबी बाग व्यवसायिक भूखण्ड	ऑफर	भूखण्ड व्यवसायिक	12	रेरा पंजीयन क्र. पी-बी. पी.एल. -17-837
2	स्वामी विवेकानन्द परिसर, कटारा हिल्स	ऑफर	भूखण्ड	04	वर्ष 2017 के पूर्व निर्मित
3	मिसरोद फेस-1	ऑफर	भूखण्ड	09	रेरा पंजीयन क्र. पी-बी. पी.एल. -20-2629
4	सरदार वल्लभ भाई पटेल मिसरोद-2	ऑफर	भूखण्ड	10	रेरा पंजीयन क्र. पी-बी. पी.एल. -17-1018
5	सरदार वल्लभ भाई पटेल मिसरोद-2	ऑफर	नर्सरी एवं प्राईमरी स्कूल	03	रेरा पंजीयन क्र. पी-बी. पी.एल. -17-1018
6	गुरू रविन्द्रनाथ टैगौर, साकेत नगर	ऑफर	प्रकोष्ठ	02	वर्ष 2017 के पूर्व निर्मित
7	अन्नपूर्णा कॉम्प्लेक्स	ऑफर	हॉल	02	वर्ष 2017 के पूर्व निर्मित
8	इन्द्रपुरी सैक्टर-सी	ऑफर	भूखण्ड	01	वर्ष 2017 के पूर्व निर्मित
9	सोनिया गॉधी परिसर	ऑफर	प्रकोष्ठ	01	वर्ष 2017 के पूर्व निर्मित
10	अन्नपूर्णा कॉम्प्लेक्स	ऑफर	प्रकोष्ठ	01	वर्ष 2017 के पूर्व निर्मित
11	विद्या नगर	ऑफर	प्रकोष्ठ	01	वर्ष 2017 के पूर्व निर्मित
12	एम.जी.रूसिया नगर, पीपलनेर	ऑफर	डूप्लेक्स	04	वर्ष 2017 के पूर्व निर्मित
13	अजन्ता कॉम्पलेक्स	ऑफर	प्रकोष्ठ	02	वर्ष 2017 के पूर्व निर्मित
14	कटारा हिल्स सैक्टर-ए एवं सी	ऑफर	दुकानें	31	वर्ष 2017 के पूर्व निर्मित
15	आई.एस.बी.टी	ऑफर	दुकानें	01	वर्ष 2017 के पूर्व निर्मित
16	गुरू रविन्द्रनाथ टैगौर परिसर	ऑफर	दुकानें	03	वर्ष 2017 के पूर्व निर्मित
17	अन्नपूर्णा कॉम्पलेक्स	ऑफर	दुकान	01	वर्ष 2017 के पूर्व निर्मित
18	पंचशील नगर	ऑफर	दुकानें	05	वर्ष 2017 के पूर्व निर्मित
19	महर्षि पतंजलि	ऑफर	दुकानें	35	वर्ष 2017 के पूर्व निर्मित
20	पंडित भीमसेन जोशी परिसर, साकेत नगर	ऑफर	दुकानें	03	वर्ष 2017 के पूर्व निर्मित
21	माता मंदिर	ऑफर	दुकानें	06	वर्ष 2017 के पूर्व निर्मित
22	आमेर कॉम्प्लेक्स नाले के ऊपर जोन-2, एम.पी. नगर	ऑफर	दुकान	01	वर्ष 2017 के पूर्व निर्मित
23	बस स्टाप नं.-7	ऑफर	दुकान	01	वर्ष 2017 के पूर्व निर्मित
24	वेदवती योजना	ऑफर	भवन	01	वर्ष 2017 के पूर्व निर्मित
25	स्वामी विवेकानन्द परिसर कटारा हिल्स, (भवन)	ऑफर	भवन	32	रेरा पंजीयन क्र. पी-बी. पी.एल. -21-2845
26	अमरावद खुर्द योजना	ऑफर	शाला भूखण्ड	02	वर्ष 2017 के पूर्व निर्मित
27	स्वामी विवेकानन्द परिसर, कटारा हिल्स	ऑफर	प्रकोष्ठ	45	वर्ष 2017 के पूर्व निर्मित
28	महालक्ष्मी आवासीय परिसर योजना	ऑफर	3बीएचके प्रकोष्ठ	13	रेरा पंजीयन क्र. पी-बी. पी.एल. -17-306
29	महर्षि पातंजलि, गोदरमउ	नियत दर	प्रकोष्ठ	22	वर्ष 2017 के पूर्व निर्मित
30	अमरावद खुर्द	नियत दर	एल.आई.जी डूप्लेक्स	21	वर्ष 2017 के पूर्व निर्मित
31	विनायक नगर गौंदरमऊ	नियत दर	ई.डब्लू.एस.	02	वर्ष 2017 के पूर्व निर्मित
32	नवीबाग योजना	नियत दर	2बीएचके प्रकोष्ठ 1बीएचके प्रकोष्ठ	21 04	रेरा पंजीयन क्र. पी-बी. पी.एल. -17-837

नोटः- बेवसाईट पर दिये गये लिंक को ओपन करने के पश्चात् आपको योजना की सम्पूर्ण जानकारी प्रदर्शित होगी, जिसमें सेम्पल फार्म, योजना के मानचित्र तथा भूखण्ड/प्रकोष्ठ/दुकान/ हॉल के मानचित्र व अपलोड करने हेतु विभिन्न आवश्यक अभिलेखों की जानकारी देखी जा सकती है। ऑनलाईन फॉर्म भरने हेतु प्राधिकरण की आई.टी. सेल से सम्पर्क किया जा सकता है।

सम्पदा अधिकारी
भोपाल विकास प्राधिकरण भोपाल

आवश्यकतानुसार जानकारी हेतु सम्पर्कः-
1- श्री रवि सिंह मो.-8770234380

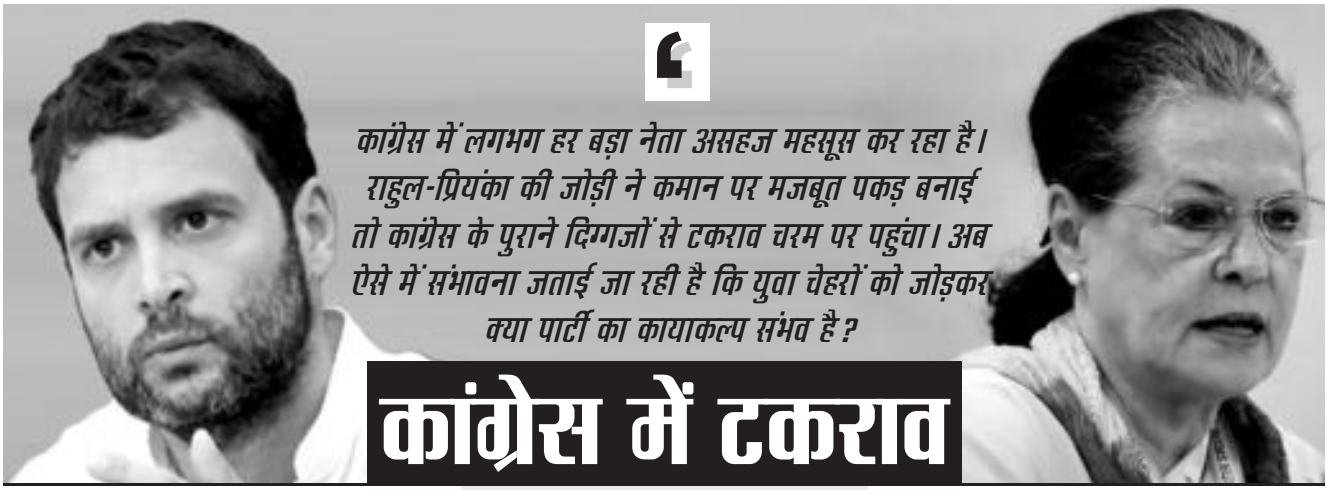

कांग्रेस में लगभग हर बड़ा नेता असहज महसूस कर रहा है। राहुल-प्रियंका की जोड़ी ने कमान पर मजबूत पकड़ बनाई तो कांग्रेस के पुराने दिग्गजों से टकराव चरम पर पहुंचा। अब ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि युवा चेहरों को जोड़कर क्या पार्टी का कायाकल्प संभव है?

कांग्रेस में टकराव

यह कोरा संयोग हो सकता है। सितंबर के आखिरी दिनों में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तथा वर्तमान अनौपचारिक कमानधारी राहुल गांधी युवा चेहरों जेएनयू छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार और दलित एक्टीविस्ट जिग्नेश मेवाणी को पार्टी में शामिल कराने के लिए कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे थे। उनके साथ गुजरात इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल भी थे। इस तिकड़ी के जरिए पार्टी की छवि युवा तुर्क जैसी बनाने का संकेत दिया जा रहा था। ऐन उसी दिन पंजाब के कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तीफा आ धमका, जो महज 72 दिन पहले ही नियुक्त किए गए थे। इतना ही नहीं, हाल ही में बड़ी 'बेमुरव्वती' के साथ रुखसत किए गए पंजाब के बुजुर्ग दिग्गज पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के दिल्ली पहुंचने की सुर्खियां चीखने लगीं। लेकिन राजनीति और खासकर दांव-प्रतिदांव के मौजूदा दौर में संयोग भी खास मायने रखता है। फिर, संयोग और मौके को लपक लेने की तेजी भी खास अहमियत रखती है। जैसा कि पर्वतराज हिमालय की तराई में स्थित उप्र के लखीमपुर खीरी में किसान प्रदर्शनकारियों को कुचल डालने की बेहद घृणित घटना के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा ने **यकीनन वाजिब** सक्रियता दिखाई, जिसमें चार किसान, एक पत्रकार और तीन अन्य लोगों की मौत हुई और कई लोग जख्मी हो गए। प्रियंका को तीन दिनों तक 'गैर-कानूनी' हिरासत में रखा गया। बाद में उनके भाई राहुल गांधी भी अपने दो-दो मुख्यमंत्रियों के साथ वहां पहुंचे और सुर्खियों के हकदार बने। लेकिन महज सुर्खियां बटोरने और खास मौकों पर सक्रियता दिखाने भर से ही राजनीति का वास्ता नहीं होता है।

बेशक, भाई-बहन की इस जोड़ी को कांग्रेस की जो कमान विरासत से अनायास हासिल है, चाहे वह 'जहर' ही क्यों न हो, उसके पीछे तकरीबन सवा सौ बरस से ज्यादा का इतिहास और अनगिनत विराट शख्सियतों का पराक्रम है (2013 में जयपुर कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस उपाध्यक्ष बनाए जाने के वक्त राहुल गांधी ने सत्ता सियासत को 'जहर' ही कहा था)। लाजिमी है कि इतनी लंबी विरासत का बोझ भी बड़ा होगा और उसे सिर्फ मजबूत कंधे ही नहीं, साफ-सुथरा और संतुलित दिमाग भी चाहिए। लेकिन 2014 के आम चुनावों में सबसे बुरी हार और खासकर 2019 में दोबारा कमोवेश वैसे ही प्रदर्शन के बाद राहुल अपनी पार्टी के पुराने नेताओं से ही तालमेल नहीं बिठा पाए हैं, न ही पार्टी महासचिव और उप्र की प्रभारी प्रियंका ऐसा कर पाई हैं। यूं तो पुराने नेताओं से यह जुंबिश लंबे अरसे से जारी है, मगर अस्सी साल के करीब पहुंच रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह से पंजाब की गद्दी चुनाव के महज चार महीने पहले लगभग छीन लेने से टकराहट एक मायने में चोटी पर पहुंच गई।

इसे न सिर्फ कैप्टन ने अपना 'अपमान और जलालत' माना, बल्कि कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी, गुलाम नबी आजाद जैसे नेताओं ने इस पर गहरी नाखुशी जाहिर की, जिन्हें 2020 में पार्टी संगठन के चुनाव कराने और औपचारिक नेतृत्व कायम करने के लिए अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखने के कारण जी-23 समूह कहा जाता है। कपिल सिब्बल ने कहा, 'न जाने पार्टी में कौन फैसले ले रहा है' तो उनके घर पर युवा कांग्रेसियों ने टमाटर और अंडे फेंके। इससे पूर्व वित्त तथा गृहमंत्री पी. चिदंबरम भी इतने आहत हुए कि उन्होंने ट्वीट किया, 'इस दौर में मौन रहना ही वक्त का तकाजा है,' जो अमूमन पार्टी के विवादों से दूर रहते हैं और जी-23 समूह में भी नहीं गिने जाते। जी-23 समूह और सभी पुराने नेता राहुल और प्रियंका के पिता पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और उनसे भी पहले उनकी दादी इंदिरा गांधी के नेतृत्व में आगे बढ़े हैं। कैप्टन तो राजीव गांधी के स्कूल के सहपाठी रहे हैं। सूत्रों की मानें तो कैप्टन को हटाए जाने के मौके पर सोनिया गांधी का (बकौल कैप्टन) 'सॉरी अमरिंदर' कहना उनकी भी असहायता का

मध्य वामपंथ की राह पर

राहुल की योजना युवा चेहरों को नए सिरे से जोड़कर पार्टी को मध्य वामपंथ की राह पर ले जाने की है। कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवाणी इसका संकेत खुलकर देते भी हैं। राहुल भी एकाधिक बार कह चुके हैं, उदारीकरण की नीतियां नब्बे के दशक में भले जरूरी रही हों लेकिन यूपीए के कार्यकाल में ही उसकी खामियां उजागर हो गई थीं। इसलिए आगे की राह उससे अलग करने की दरकार है। इसी के मद्देनजर 2019 के आम चुनावों के दौरान कांग्रेस के घोषणा-पत्र में न्याय योजना के साथ कल्याणकारी राजकाज की ओर ले जाने वाले कार्यक्रम थे और आर्थिक सुधारों की बात लगभग नदारद थी। कांग्रेस के ज्यादातर पुराने नेता उदारीकरण के पक्षधर रहे हैं, जो राजीव गांधी के तहत आगे बढ़े हैं। दरअसल नई आर्थिक नीतियों और नई टेक्नोलॉजी की ओर कदम सबसे पहले बढ़ाने वाले राजीव गांधी ही थे। संभव है, नजरिए का यह फर्क भी आड़े आ रहा हो। इसके अलावा राहुल के करीबी सूत्रों का यह भी कहना है कि उन्हें इस बात का काफी गुरेज है कि कोई दूसरा कांग्रेस नेता भाजपा, संघ परिवार या मोदी सरकार के खिलाफ बोलने से परहेज करता है। लेकिन गौरतलब यह भी है कि इंदिरा गांधी ने जब पार्टी को मध्य वामपंथ की ओर ले जाने और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं एस. निजलिंगप्पा, मोरारजी देसाई, कामराज, नीलम संजीव रेड्डी से अलग राह पकड़ने का फैसला किया था, तब कांग्रेस का आधार व्यापक था और जनाधार वाले युवा तुर्क नेताओं की बड़ी फौज थी। आज न कांग्रेस का वैसा जनाधार बचा है, न उतने जनाधार वाले नेता हैं और न राहुल-प्रियंका का लोगों में वह भरोसा है। इसी वजह से नीरजा चौधरी कहती हैं, राहुल के लिए सबसे अच्छा यह होता कि वे पार्टी के नैतिक पहरुए की भूमिका निभाते और संगठन बनाने पर काम करते। अध्यक्ष की भूमिका काफी व्यापक और पेचीदी होती है। फिलहाल तो यह नहीं लगता कि गांधी परिवार नेतृत्व किसी और नेता को देना चाहता है। वैसे यह सवाल भी अपनी जगह है कि ऐसा कौन नेता है, जिसकी छवि देशव्यापी और सर्वमान्य हो, जो कांग्रेस के लिए धुरी का काम करे।

ही संकेत देता है। अटकलें हैं कि सोनिया गांधी ने कुछ नेताओं से कहा कि उनकी भी अनसुनी हो रही है।

हालांकि यह कोई छुपी बात नहीं है कि पार्टी के फैसले सोनिया गांधी से ज्यादा राहुल-प्रियंका की जोड़ी ही कर रही है। कहा तो यह जाता है कि प्रियंका के ही कारण सिद्धू को पंजाब पार्टी की कमान मिली, जिसके लिए तब कैप्टन तैयार नहीं थे। कैप्टन से युवा गांधियों की नाराजगी की एक वजह यह भी बताई जाती है कि उनसे 2017 के चुनावों से पहले राहुल ने पूछा कि क्या यह सही है कि नेता पद के लिए आपके नाम का ऐलान नहीं हुआ तो आप अलग पार्टी बना लेंगे। कैप्टन का जवाब था कि यह सही है। पहले सोनिया के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल पार्टी के तमाम नेताओं और बाहर की राजनीतिक बिरादरी में व्यापक रसूख के कारण हर फैसले की जमीन तैयार कर देते थे और नाराजगी दूर करने के उपाय निकाल लेते थे। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर में उनकी मौत के बाद ऐसा कोई सूत्रधार बचा नहीं है। तो, सवाल उठता है कि राहुल औपचारिक तौर पर अध्यक्ष की कुर्सी क्यों नहीं संभाल लेते? वे 2018 में गुजरात में पार्टी की बंपर कामयाबी, जब महज 12 सीटों से वहां सत्ता चूक गई थी, और मप्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के चुनावों में जीत के दौर में बड़े धूम-धड़ाके के साथ अध्यक्ष बने थे। लेकिन 2019 में हार की जिम्मेदारी लेकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था। तबसे पार्टी में अध्यक्ष, संगठन के अन्य पदों और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के चुनाव का मामला लटका हुआ है। औपचारिक वजह कोरोना महामारी को बताया गया है। अब 16 अक्टूबर को कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है, जिसमें सूत्रों की मानें तो पार्टी अध्यक्ष पर बात होने की संभावना है। राहुल ने इस्तीफा देते वक्त यह भी कहा था कि गांधी परिवार से कोई सर्वोच्च कमान नहीं संभालेगा। लेकिन अब पार्टी के आला स्तर पर हुए फैसलों से लगता है कि पकड़ मजबूत बनाने और कोई ढिलाई न बरतने का मन बना लिया गया है। अरसे से कांग्रेस पर बारीक नजर रखने वालीं नीरजा चौधरी कहती हैं, लगता है कि गांधी परिवार ने अब पार्टी कमान पर मुकम्मल पकड़ बनाए रखने का तय कर लिया है। बेशक, सोनिया पीछे हैं, मगर फैसले राहुल और प्रियंका ही ले रहे हैं।

यह नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने और फिर कैप्टन से कुर्सी छीनने की घटना में दिखा भी। सिद्धू के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के साथ खटकने और सिद्धू के इस्तीफा फेंक देने पर यह रुख अपनाने में भी दिखा कि यह राज्य का मामला है। मतलब यह कि सिद्धू या किसी नेता को एक हद से ज्यादा तवज्जो नहीं देना है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस कड़े रुख से पार्टी के मामलों को संभालने की सलाहियत राहुल और प्रियंका में है? सोनिया गांधी ने भले 1999 में कुछ कड़े तेवर के साथ तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी से अध्यक्ष पद हासिल किया हो, मगर बाद में उन्होंने सबको साथ लेकर चलने की ऐसी सलाहियत दिखाई कि एक वक्त धुर विरोधियों से भी उनके रिश्ते सहज हो गए। इसकी मिसाल समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव हैं, जिनके असली मौके पर पीछे हटने से सोनिया के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार नहीं बन सकी थी। इसके अलावा राकांपा प्रमुख शरद पवार, ममता बनर्जी जैसे **तमाम विपक्षी** नेताओं का भी उदाहरण है। ये सभी बाद में यूपीए में शामिल हुए या उसे समर्थन देने लगे। यही नहीं, वे कांग्रेस के तमाम ऐसे नेताओं को साथ लाईं, जो किसी न किसी कारण अलग हो गए थे। विरोधियों का मन जीतने का उनका कौशल भाजपा नेता सुषमा स्वराज के साथ भी दिखा था। स्वराज ने 2004 में उनके विदेशी मूल का मुद्दा तीखे ढंग से उठाया था और कहा था कि वे प्रधानमंत्री बनती हैं तो मैं अपना सिर मुड़ा लूंगी। लेकिन बाद में दोनों संसद में प्रेम से बतियाती दिखती थीं। लेकिन राहुल के दौर में पार्टी नेताओं से ही नहीं, विपक्ष से तालमेल में भी दिक्कतें दिखने लगी हैं।

यह हाल में चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर के ट्वीट में भी दिखा। उन्होंने ट्वीट किया, लखीमपुरखीरी जैसी घटनाओं के दौरान सक्रियता तो सही मगर कांग्रेस में जान तभी आएगी जब संगठन मजबूत होगा। इसके बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल ने जवाबी ट्वीट किया तो तृणमूल के सांसदों ने तीखी प्रतिक्रिया दी। प्रशांत के भी कांग्रेस में शामिल होने की चर्चा थी और कहा जा रहा था कि उनका सर्वे ही कैप्टन को हटाने का आधार बना, जिसमें सरकार की लोकप्रियता घटती दिखी थी। पर ऐसे कयास भी हैं कि पंजाब में सुलह कराने के लिए बनाई गई वरिष्ठ सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे की समिति की विधायकों से बातचीत के बाद तैयार रिपोर्ट मुख्यमंत्री बदलने का आधार बनी।

● रजनीकांत पारे

कांग्रेस भ्रम की स्थिति में

कांग्रेस का दावा यह है कि उसके बिना विपक्षी एकता संभव नहीं है। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव बल्लभ कहते हैं, पिछले लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस को 12 करोड़ वोट मिले थे और कई अहम राज्यों में उसका भाजपा से सीधा मुकाबला है। इसलिए कांग्रेस को छोड़कर ऐसा कोई गठजोड़ नहीं बन सकता। गणित यह भी है कि गुजरात, मप्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और कुछ हद तक कर्नाटक और महाराष्ट्र की लगभग 200 सीटों पर कांग्रेस का भाजपा से सीधा मुकाबला है। लेकिन इस तमाम गणित के बावजूद कांग्रेस का प्रदर्शन और नेतृत्व का सबको साथ लेकर चल पाने का लचीला रवैया ही नेता पद पर दावे के लिए अहम होगा, जो फिलहाल दिख नहीं रहा है। बेशक, कुछ राज्यों में विभिन्न वजहों और सत्ता विरोधी रुझान की वजह से कांग्रेस की हालत सुधरी है। जैसा कि हाल में कांग्रेस के साथ आए मेवाणी कहते हैं, गुजरात में पिछली बार की कमी भी भर देंगे और इस बार जीत पक्की करेंगे। वे यह भी कहते हैं कि आम आदमी पार्टी का असर हवा-हवाई है, उससे कांग्रेस को खास फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह मप्र में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ काफी सक्रिय हैं और दमोह उपचुनाव में जीत से संकेत मिलता है कि कांग्रेस मजबूत हुई है। लेकिन जोबट और पृथ्वीपुर की हार ने उसे धरातल पर ला दिया है।

मौजूदा माहौल में यह साफ है कि राजनीति के अपराधीकरण पर रोक के लिए उच्चतम न्यायालय को ही आगे आना होगा क्योंकि देश में कानून का राज स्थापित करना उसी की नैतिक जिम्मेदारी है। संविधान ने उसे इसीलिए इतना शक्तिशाली बनाया है। गौरतलब है कि राजनीति में दिन पर दिन अपराधीकरण बढ़ता जा रहा है। सरकार और पार्टियों के लाख दावों के बाद भी चुनावों में अपराधी किस्म के नेताओं पर दांव लगाया जाता है।

बेलगाम राजनीति

आज देश की राजनीति किन रोगों से ग्रस्त हो गई है, उनसे कोई अपरिचित नहीं है। जिस देश की संविधान सभा की अध्यक्षता डॉ. राजेंद्र प्रसाद जैसे मनीषी ने की हो, जिसके स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया हो, उसमें यह कल्पनातीत होना चाहिए कि उसके अधिकांश चयनित प्रतिनिधि अपने मूल उत्तरदायित्व भुला चुके होंगे। उनका सारा ध्यान अपने-अपने परिवार, अगले चुनाव जीतने पर केंद्रित हो जाएगा। सिद्धांतों और नैतिकता पर चर्चा करने तक का समय उनके पास नहीं होगा। क्या यह उचित नहीं होता कि देश की संसद और विधानसभाएं 'सत्याग्रह तथा नैतिकता' जैसे विषयों पर गहन संवाद करतीं, 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' का आशय समझने का प्रयास करतीं।

देश के विभिन्न हिस्सों से रह-रहकर ऐसे समाचार आते ही रहते हैं कि किसी आपराधिक मामले में किसी सांसद या विधायक अथवा अन्य किसी जनप्रतिनिधि को गिरफ्तार किया गया या फिर उनकी तलाश में छापेमारी की गई। पिछले दिनों ही महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को 100 करोड़ रुपए की अवैध उगाही में गिरफ्तार किया गया। इसी तरह घोसी, उप्र के बसपा सांसद अतुल राय गैंगस्टर एक्ट में रिमांड पर भेजे गए। उन पर एक युवती ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था और कोई सुनवाई न होने पर उसने आत्मदाह कर लिया था।

यह किसी से छिपा नहीं कि देश में तमाम ऐसे जनप्रतिनिधि हैं, जिन पर गंभीर अपराधों में लिप्त होने के आरोप हैं। इनमें से कई बाहुबली छवि वाले हैं। आमतौर पर अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति पहले अपराध कर अपनी 'हनक' बनाते हैं। फिर अवैध उगाही, फिरौती इत्यादि हर प्रकार के गलत धंधे कर बाहुबली से 'धनपशु' बनते हैं। इसके बाद वे राजनीति में आकर जनप्रतिनिधि बनते हैं, ताकि समाज में वे 'माननीय' कहे जाएं। फिर वे अपने सारे केस साम, दाम, दंड, भेद से खत्म कराते हैं। ऐसे बाहुबली अपना एक आपराधिक निजी तंत्र खड़ाकर चुनाव जीतते रहते हैं। देश में पहले यह समस्या नहीं थी, क्योंकि अधिकतर अपराधियों को सजा हो जाती थी या वे एनकाउंटर में मारे जाते थे। गवाह तोड़ना आसान नहीं था। सामाजिक मान्यताएं कुछ अन्य थीं। पुलिस की 'हनक' उनकी 'हनक' पर भारी पड़ती थी। राजनीतिक पार्टियां भी अपराधियों से दूर रहती थीं।

वास्तव में पिछली सदी के नौंवे दशक से राजनीति की गरिमा में गिरावट प्रारंभ हुई। उसके बाद से यह सिलसिला बना हुआ है। आज देश में 43 प्रतिशत से अधिक सांसद-विधायक ऐसे हैं, जिन पर आपराधिक मामले चल रहे हैं। आज ऐसे लोग भी सांसद-विधायक हैं जिन्होंने अपने हलफनामे में स्वयं स्वीकार किया है कि वे दुष्कर्म, हत्या, लूट के मामले में आरोपी हैं और न्यायालय में केस चल रहा है। जब तक इस प्रकार के अपराध करने वालों का संसद और विधानसभाओं में पहुंचने पर अंकुश नहीं लगेगा, तब तक यह संख्या बढ़ती ही रहेगी।

उच्चतम न्यायालय को ही लगाना पड़ेगा अंकुश

राजनीति के अपराधीकरण पर अंकुश अंततः उच्चतम न्यायालय को ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि देश में कानून का राज स्थापित करना उसी की नैतिक जिम्मेदारी है। संविधान ने उसे इसीलिए इतना शक्तिशाली बनाया है। नए मुख्य न्यायाधीश महोदय के बेबाक और साहसिक बयानों ने एक आशा की किरण सी दिखाई है। हाल में उन्होंने स्पष्ट कहा कि 'न्यायपालिका को आम लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए अत्याचारी समूहों की सामूहिक शक्ति से निडर होकर लड़ने के लिए तैयार रहना होगा।' जस्टिस जेएस वर्मा ने भी अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा था कि 'संसद में जब तक दागी लोग बैठेंगे, तब तक देश को कानून बनाने की शैली और तौर-तरीके पर विश्वास करना संभव नहीं होगा।' समय आ गया है कि संगीन आरोपों से घिरे विधायकों और सांसदों के गलत कामों का संज्ञान संसद और विधानसभाओं के पीठासीन अधिकारी भी लें।

दिल्ली में हुए निर्भया कांड के बाद उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश जेएस वर्मा की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति बनाई गई थी। उन्हें देश के आपराधिक कानूनों की समीक्षा कर सुझाव देने को कहा गया था कि उनमें क्या सुधार किए जाएं कि दुष्कर्म जैसे अपराधों में त्वरित कार्रवाई कर कठोर सजा दी जा सके। जेएस वर्मा ने अपनी रिपोर्ट में चुनावी सुधारों के संबंध में एक अलग अध्याय भी लिखा था, जो विशेष रूप से उल्लेखनीय था, परंतु उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसके दुष्परिणाम सबके सामने हैं। उन्होंने देश का ध्यान इस पर भी आकर्षित किया था कि आजादी के 50 साल पूरा होने के बाद 1997 में संसद ने स्वयं राजनीति के अपराधीकरण के विरुद्ध सर्वसम्मति से जो प्रस्ताव पारित किया था, उसे प्रभावी रूप दिया जाए। यह बात जब एक जनहित याचिका के माध्यम से उच्चतम न्यायालय में उठाई गई तो न्यायालय ने कहा कि कानून बनाना संसद का कार्य है। हम केवल अनुरोध कर सकते हैं। उसने अनुरोध किया भी कि ऐसे कानून की आज देश और समाज हित में घोर आवश्यकता है।

केंद्रीय चुनाव आयोग के पास कम से कम इतना अधिकार तो होना ही चाहिए कि वह किसी सांसद-विधायक के आपराधिक इतिहास की अपनी मर्जी से छानबीन कर सके और यह पता लगा सके कि उसे चुनाव लड़ने के लिए पार्टी से टिकट कैसे मिला? क्या पार्टी में उनकी इतनी वरिष्ठता थी या कोई असाधारण योगदान था? अगर मात्र पैसे के आधार पर टिकट दिया गया जाए तो चुनाव आयोग संबंधित पार्टी का 'सिंबल' कुछ वर्षों के लिए निलंबित कर सके या अन्य कोई कार्रवाई कर सके। इसमें दो राय नहीं कि पैसा देकर टिकट हासिल करने वाले और पैसे के दम पर चुनाव जीतने वाले जनप्रतिनिधि ही समाज में सारी गंदगी ऊपर से नीचे तक फैलाते हैं। वही कार्यपालिका में भी भ्रष्टाचार को पनपाते हैं और राजनीति के अपराधीकरण का सिलसिला कायम रखते हैं। आखिर समाज की शुचिता बनाए रखना और सोच को सही दिशा देना भी सरकार व चुनाव आयोग की ही नैतिक जिम्मेदारी है।

बिहार विधानसभा चुनावों में प्रत्याशियों का आपराधिक इतिहास न प्रकाशित करने या आयोग को सूचना न देने पर सुनवाई करते हुए कुछ समय पहले उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा था कि 'अपराधीकरण रोकने के लिए सरकार ने न कुछ किया और न कुछ करेगी।' बाद में उसने इस प्रकार की पार्टियों पर पांच-पांच लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगा दिया था। इसके बाद भी राजनीतिक दलों का हाल यह है कि उप्र के चुनाव को लेकर एक पार्टी फूलन देवी की मूर्ति हर जनपद में लगाने की बात कर रही है, जबकि उसके द्वारा किए गए बेहमई कत्लेआम को कौन नहीं जानता, जिसमें एक जाति विशेष के 24 लोगों को लाइन में खड़ा कर मौत के घाट उतार दिया गया था। एक और पार्टी ब्राह्मणों के साथ हो रहे कथित अत्याचार के नाम पर कानपुर के बिकरू कांड के मुख्य आरोपित विकास दुबे को 'हीरो' बना रही है, जबकि सभी जानते हैं कि उसे पकड़ने गई पुलिस के डिप्टी एसपी समेत चार-पांच पुलिसकर्मी और मारे गए थे, जिसमें आधे ब्राह्मण थे।

निष्पक्षता केवल दिखावा

राजनीति प्रेरित पंथनिरपेक्षता के नाम पर भावी पीढ़ियों को तथ्यात्मक इतिहास से वंचित करना अब बंद होना ही चाहिए। जनतंत्र की शक्ति तो विद्वत वर्ग की वैचारिक पवित्रता में निहित होती है। यह उन्हीं का उत्तरदायित्व है कि वे जनतंत्र की जड़ें मजबूत करें। ऐसा वे लोग कतई नहीं कर सकेंगे, जो सत्ता के निकट पहुंचने के लिए लगातार प्रयत्नशील बने रहे, उसके कृपापात्र बने रहे और अपनी निष्पक्षता का उत्तरदायित्व भूल गए। दुर्भाग्य से भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रारंभ से ही एक बड़ा वर्ग इसी में लिप्त रहा। जिस नैतिकता को भारत के प्रजातंत्र की आधारशिला बनाना था, वह धीरे-धीरे कमजोर होती गई। आज यदि देश में दो स्थानों पर एक ही जैसी हत्याएं होती हैं, तो उन पर प्रतिक्रिया भी चुनावों पर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखकर दी जाती है। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने सभा में 26 नवंबर, 1949 को एक ऐतिहासिक भाषण दिया था। इसमें उन्होंने यह कहा था कि संविधान में जो भी व्यवस्था की गई हो, उसका क्रियान्वयन तो उसे लागू करने वाले लोगों पर निर्भर करेगा। यदि चयनित प्रतिनिधि योग्य, चरित्रवान तथा ईमानदार होंगे तो वे एक त्रुटिपूर्ण संविधान का भी सर्वोत्तम उपयोग कर सकेंगे, लेकिन यदि उनमें इन तीनों गुणों की कमी होगी तो संविधान भी कोई मदद नहीं कर सकेगा। अब इस कार्य को पूरा करने का दायित्व नई पीढ़ी को ही उठाना पड़ेगा।

राजनीतिक पार्टियों का एकमात्र मकसद होता है चुनाव जीतना। इसके लिए किसको टिकट देना है, किसको नहीं, इस बारे में तनिक भी नहीं सोचा जाता है। गांधी जी के अनुसार, 'अनुशासन और विवेकयुक्त जनतंत्र दुनिया की सबसे सुंदर वस्तु है, लेकिन राग-द्वेष, अज्ञान और अंधविश्वास आदि दुगरुणों से ग्रस्त जनतंत्र अराजकता के गड्ढे में गिरता है और अपना नाश खुद कर लेता है।' जाहिर है यह समय चेत जाने का है। राष्ट्र की कितनी ही ऊर्जा केवल अपनी-अपनी दलगत राजनीति को चमकाने और चुनाव जीतने में व्यय हो रही है। इसका एक चौथाई भाग भी यदि सभी राजनेता और राजनीतिक दल जनसेवा में लगाएं तो जनतंत्र जागृत होगा, जनजीवन में नैतिकता भी स्वत: ही अपना स्थान पा सकेगी। अनेक अवसरों पर विद्वत-वर्ग इस विषय पर चर्चा करते हैं कि सबसे प्राचीन गणतंत्र भारत में ही था। उनमें वैशाली और लिच्छवी जैसे गणतंत्र का नाम आवश्यक रूप से लिया जाता है। पिछले दिनों संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत जनतंत्र की जननी है। हालांकि, देश में जनतंत्र का जो स्वरूप आज व्यावहारिक स्तर पर उभरा है, वह उस कल्पना से तो निश्चित ही मेल नहीं खाता, जिसकी संकल्पना स्वतंत्रता सेनानियों ने की थी, जिसके लिए अनगिनत लोगों ने त्याग और बलिदान दिए थे।

आज भारत एक जागृत जनतंत्र है, जिसकी अनेक उपलब्धियां हैं, मगर यह भी सत्य है कि आज के युवाओं के समक्ष जो स्थितियां उभरी हैं, वे आजादी के दीवानों की अपेक्षाओं से मेल नहीं खाती हैं। उन्हें इसे समझना और सुधारना है। 1947 में देश ने स्वतंत्रता पाने का समारोह मनाया, मगर जो विस्थापन और हिंसा उस समय लाखों परिवारों ने झेली, वह इतिहास का एक ऐसा सबक है जिसे भारत की हर पीढ़ी को जानना चाहिए। उसे इस तथ्य को भी पहचानना, समझना और स्वीकार करना आवश्यक है कि भारत का वास्तविक इतिहास केवल स्वतंत्रता के पहले के शासकों द्वारा ही विकृत नहीं किया गया, बल्कि स्वतंत्रता के बाद भी और आज तक वह वामपंथी मानसिकता का बंधक बना है।

● **इन्द्र कुमार**

अंधविश्वास को मिलेगा बल

बैगा गुनिया की पौ बारह

छत्तीसगढ़ में टोनही अधिनियम सख्ती से लागू है। आदिवासी प्रदेश होने के कारण ग्रामीण अंचल में महिलाओं को टोनही कहकर प्रताड़ित किया जाता है। जाने कितनी महिलाएं प्रतिवर्ष क्रूरता की शिकार होती है। यहां बैगा गुनिया भी ग्रामीण अंचल में लोगों का इलाज करते हैं और खतरनाक ढंग से इलाज करते-करते भोले-भाले लोगों पर क्रूरता करने लगते हैं। ऐसे जाने कितने प्रकरण सामने आते रहते हैं। ऐसे में जब प्रदेश का मुखिया मुख्यमंत्री बैगा गुनिया के हाथों स्वयं को हंसते-हंसते चाबुक पड़वाएगा, चाहे वह प्रतीकात्मक ही क्यों न हो, तो इसका असर दूर अंचल में क्या हो सकता है, इसकी कल्पना सहज ही लगाई जा सकती है। मुख्यमंत्री को तो बैगा ने प्रतीकात्मक चाबुक मारा, मगर जब दूरदराज इलाको में बैगाओं की चल पड़ेगी तब लोगों को मार-मार कर लाल कर देंगे। तब उसका जिम्मेदार कौन होगा? अंधविश्वास व्यवस्था के नाम पर छत्तीसगढ़ में तेजी से फैलता ढोंग घतूरा चिंता का बड़ा सबब है।

भारत आस्थाओं और मान्यताओं का देश है। जहां अंधविश्वासों की भरमार है। कई बार हम ऐसा बहुत कुछ देखते-सुनते हैं जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता। जो व्यक्ति को अचरज में डालता है साथ ही जो इस बात की तस्दीख भी कर देता है कि भले ही आज हम विज्ञान और आधुनिक होने की बड़ी-बड़ी बातें क्यों न कर रहे हों लेकिन अंदर से आज भी हम पहले जैसे ही हैं। प्राय: ऐसे विचार मन में आते रहते हैं मगर इनको बल तब मिलता है जब हम किसी बड़े आदमी को, जानी-मानी हस्ती को, जनसेवक को या फिर किसी राज्य के मुख्यमंत्री को सिर्फ इसलिए कोड़े खाते देखते हैं क्योंकि उसे एक पुरानी मान्यता का पालन करना है। इस बात को जानकर हैरत में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा सीधा इशारा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ है जिनका दिवाली के मद्देनजर एक वीडियो वायरल हुआ है और यदि उस वीडियो का अवलोकन किया जाए तो ये कहना कहीं से भी गलत न होगा कि भूपेश बघेल न केवल अंधविश्वास को अंजाम दे रहे हैं बल्कि अपनी गतिविधियों से इसे दूसरों के बीच प्रचारित और प्रसारित भी करते नजर आ रहे हैं।

दरअसल बात कुछ यूं है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हर साल प्रदेश की सुख, समृद्धि, मंगल कामना और विघ्नों के नाश के लिए कुश से बने सोटे का प्रहार सहते हैं। अभी बीते दिन ही उन्होंने दुर्ग के जंजगिरी में यह परंपरा निभाई। वीडियो इंटरनेट पर वायरल है और इस वीडियो के तहत बताया यही जा रहा है कि यहां के एक ग्रामीण बीरेंद्र ठाकुर ने उन पर सोटे का प्रहार किया। बीरेंद्र से कोड़े खाने के बाद ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोवर्धन और गोवंश की पूजा की। कोड़े से पिटाई के बाद मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों के सामने अपनी बात रखी और कहा कि प्रत्येक वर्ष गांव के भरोसा ठाकुर नाम के व्यक्ति इस परंपरा का पालन करते थे और उन पर प्रहार करते थे। अब यह परंपरा उनके पुत्र बीरेंद्र ठाकुर द्वारा निभाई जा रही है। वहीं गोवंश की पूजा पर भी भूपेश बघेल ने अपने मन की बात की है। ग्रामीणों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि गोवर्धन पूजा गोवंश की समृद्धि की परंपरा की पूजा है।

बघेल का मानना है कि जितना समृद्ध गोवंश होगा उतनी ही हमारी तरक्की होगी। इसी वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में गोवर्धन पूजा इतनी लोकप्रिय होती है। लोग सालभर इसकी प्रतीक्षा करते हैं। गोवर्धन और गोवंश पूजा पर भूपेश बघेल ने कहा कि एक तरह से यह पूजा गोवंश के प्रति हमारी कृतज्ञता का प्रतीक भी है। वहीं संस्कृति की दुहाई देते हुए बघेल ने ये भी कहा कि गोवर्धन पूजा लोक के उत्सव की परंपरा है। हमारे पूर्वजों ने बहुत सुंदर छोटी-छोटी परंपराओं का सृजन किया और इन परंपराओं के माध्यम से हमारे जीवन में उल्लास भरता है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि अपनी माटी की अस्मिता को सहेजना उसका संवर्धन करना हम सब का कर्तव्य है। इसके बाद भूपेश बघेल ने परंपराओं का जिक्र किया और कहा कि इन्हें सहेजना हमारा परम कर्तव्य है। भूपेश बघेल का मानना है कि हमें अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को अपनी व्यवस्था में शीर्षस्थ स्थान देना होगा क्योंकि परंपरा से हमारा अस्तित्व भी है, परंपरा से हमारे मूल्य भी हैं।

बेशक एक मुख्यमंत्री के रूप में भूपेश बघेल ने बहुत अच्छी बातें की हैं मगर जिस तरह उन्होंने कोड़े खाए हैं सवाल ये है कि आखिर कैसे ये किसी राज्य की उन्नति और विकास को, वहां की कृषि व्यवस्था को प्रभावित करता है। अच्छी बात है कि मुख्यमंत्री राज्य के लोगों के लिए, वहां की संस्कृति और उसके संरक्षण के लिए गंभीर है मगर खुद को कोड़े मरवाना फिर उस व्यक्ति को जिसने पूरी ताकत से कोड़े जड़े गले लगाना, हंसना-मुस्कुराना सोच और कल्पना दोनों के ही परे है।

कहना गलत नहीं है कि भावों में बहकर भूपेश बघेल एक ऐसी परंपरा का पालन कर रहे हैं जिसका आज के समय में शायद ही कोई औचित्य हो। यानी वो सीधे-सीधे अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं। हम फिर इस बात को कह रहे हैं कि संस्कृति का संरक्षण कर भूपेश बघेल ने एक नेता से पहले एक आदर्श नागरिक होने का परिचय दिया है लेकिन जिस तरह उन्होंने कोड़े खाए हैं उसकी आलोचना इसलिए भी होनी चाहिए क्योंकि वैज्ञानिक रूप से इसे कहीं से भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है।

ध्यान रहे भारत, नए भारत की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में चाहे वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हों या कोई और। जो कोई भी ऐसी गतिविधियों को ऐसे अंधविश्वासों को बढ़ावा दे रहा है वो प्रत्यक्ष या परोसख रूप से देश को 10 साल पीछे ले जा रहा है। अंत में बस इतना ही कि संस्कृति के संरक्षण के तहत भूपेश बघेल के इरादे तो नेक हैं लेकिन उनका तरीका गलत है और यदि विरोध हो रहा है तो वो उनके इरादे का नहीं बल्कि तरीके का हो रहा है।

● **रायपुर से टीपी सिंह**

पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त...

आर्यन खान की जमानत बॉम्बे हाईकोर्ट से मंजूर होने के बाद एनसीपी प्रवक्ता नवाब मलिक ने शाहरुख खान की ही फिल्म ओम शांति ओम के एक डायलॉग कहा था, 'पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।' ये विवाद बढ़ते-बढ़ते नवाब मलिक और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच तकरार शुरू हो गई है। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पर आरोप तो सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच के वक्त भी लगाए गए थे और रिया चक्रवर्ती को जेल भेजे जाने के बाद तो कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी 'बंगाली ब्राह्मण महिला' बताते हुए बचाव में खड़े हो गए थे। जैसे तब कांग्रेस नेता रिया चक्रवर्ती को राजनीतिक वजहों से फंसाए जाने की बात कर रहे थे, आर्यन खान के केस में भी वैसी ही बातें कही जा रही हैं।

नवाब मलिक को ज्यादा मुखर तब देखा गया जब उनके दामाद को ड्रग्स केस में जमानत मिल गई क्योंकि कोर्ट में एनसीबी अफसरों की दलीलें नहीं टिक पाई थीं। हालांकि, एनसीबी की तरफ से नए सिरे से जमानत रद्द कराने के लिए कोर्ट में अर्जी देने की तैयारी हो रही है। नवाब मलिक पहले तो एनसीबी के मुंबई जोन के डायरेक्टर समीर वानखेड़े के पीछे पड़े थे, लेकिन अब अपनी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए वे भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस को घेरने में लगे हैं। देवेंद्र फडणवीस भी नवाब मलिक पर अंडरवर्ल्ड के साथ रिश्तों का इल्जाम लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने तो एनसीबी के जरिए भाजपा पर महाराष्ट्र को बदनाम करने का ही आरोप जड़ दिया था और गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर बरामद ड्रग्स का जिक्र कर भाजपा नेतृत्व तक को घेरने की कोशिश की थी। कहने को तो आर्यन खान का केस एनसीबी दफ्तर से होते हुए अदालत में चल रहा है, लेकिन वो महज केस का आपराधिक पक्ष है, क्योंकि राजनीतिक लड़ाई तो अलग ही लड़ी जा रही है। आर्यन खान केस को लेकर राजनीतिक बंटवारा साफ-साफ दो हिस्सों में देखा जा सकता है।

जैसे केंद्रीय जांच एजेंसियों के एक्शन होते ही केंद्र की मोदी सरकार निशाने पर आ जाती है, ड्रग्स केस में आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद भी महाराष्ट्र भाजपा के नेताओं को जवाब देना पड़ रहा है और महाराष्ट्र में सत्ताधारी गठबंधन के नेता हमलावर हैं। न तो सुशांत सिंह राजपूत केस बिहार चुनाव में मुद्दा बन सका, न रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी बंगाल चुनाव में। बिहार में चुनाव प्रभारी रहते हुए भी देवेंद्र फडणवीस को सुशांत केस पर कुछ खास नहीं करना पड़ा था, लेकिन आर्यन खान केस के राजनीतिक राह पर आगे बढ़ने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री को मोर्चा संभालना पड़ा है, खासकर समीर वानखेड़े को जांच के काम से हटाए जाने के बाद, और ये सब इतना जल्दी खत्म होता नहीं दिख रहा है।

शिवसेना की दशहरा रैली में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एनसीबी की कार्रवाई पर बिफरे हुए नजर आए थे, ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे तुलसी की जगह गांजा लगाया जा रहा है। ऐसा जानबूझ कर क्यों कर रहे हो? ऐसा नहीं है कि सिर्फ महाराष्ट्र में मिला है। मुंद्रा बंदरगाह पर करोड़ों का ड्रग्स मिला। कहां है मुंद्रा? गुजरात... आप यहां चिमटी भर गांजा सूंघ रहे हैं। उद्धव ठाकरे के इतना कहने भर से ही एनसीपी नेता नवाब मलिक का जोश बढ़ गया और वो हर रोज कोई न कोई नया दावा करते और किसी न किसी की तस्वीर ट्विटर पर शेयर करने लगे। समीर वानखेड़े के परिवारवालों की कई तस्वीरें तो ट्विटर पर शेयर किए ही, एक दिन देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस की भी शेयर कर डाली।

जब नवाब मलिक देवेंद्र फडणवीस के ड्रग कारोबारियों से गहरे रिश्तों का दावा कर बैठे तो विवाद बढ़ना ही था। देवेंद्र फडणवीस को खुल कर मोर्चा संभालना पड़ा। नवाब मलिक ने फडणवीस के अलावा और भी भाजपा नेताओं के ड्रग्स का कारोबार करने वालों से संबंध होने का भी आरोप लगाया। नवाब मलिक ने प्रेस कांफ्रेंस में एक एल्बम के निर्माण को लेकर जेल में एक व्यक्ति के बहाने भाजपा नेताओं को कठघरे में खड़ा करने की कोशिश की। नवाब मलिक ने कहा कि जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे तब उनकी पत्नी ने एक रिवर सॉन्ग चल-चल मुंबई बनाया था। वो गीत सोनू निगम और अमृता फडणवीस ने मिलकर गाया था और देवेंद्र फडणवीस और उनके कैबिनेट साथी सुधीर मुनगंटीवार ने एल्बम में अभिनय किया था।

जिस व्यक्ति के बहाने नवाब मलिक भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस पर आरोप लगा रहे हैं उसका नाम जयदीप राणा है और वो दिल्ली के 2020 के एक ड्रग तस्करी केस में जेल में बंद है। नवाब मलिक ने ये इल्जाम भी लगाया कि मुंबई, महाराष्ट्र और गोवा में ड्रग्स का कारोबार देवेंद्र फडणवीस के संरक्षण में किया जा रहा है और आने वाले दिनों में जांच कराए जाने की भी बात कही। नवाब मलिक के आरोपों को खारिज करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने एनसीपी नेता पर ही अंडरवर्ल्ड के साथ संबंधों के आरोप लगा डाला है। फडणवीस ने ऐलान किया था कि वो दिवाली के बाद बम फोड़ेंगे और एनसीपी नेता शरद पवार को भी अपडेट करेंगे। देवेंद्र फडणवीस ने ये तो माना है कि रिवर एनथम की पूरी टीम उनसे मिली और फोटो भी खींचे गए, लेकिन वो ये कहकर बचाव कर रहे हैं कि जिस व्यक्ति का नाम नवाब मलिक ले रहे हैं उसे चार साल बाद एनसीबी ने गिरफ्तार किया है।

● **बिन्दु माथुर**

नवाब मलिक लगातार हमलावर

दिवाली के बाद भी नवाब मलिक ने देवेंद्र फडणवीस का इंतजार नहीं किया और अब समीर वानखेड़े पर आर्यन खान को किडनैप करने कर फिरौती मांगने का इल्जाम लगाया है। केस के एक गवाह ने भी समीर वानखेड़े पर पैसे मांगने का आरोप लगाया था और बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। नवाब मलिक का कहना है कि मामले की जांच के लिए वो एसआईटी गठित करने की मांग किए थे, लेकिन अब दो स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम बनाई गई हैं। एक टीम केंद्र सरकार की तरफ से बनाई गई है और दूसरी महाराष्ट्र सरकार की ओर से। एनसीबी में एक नई बात हुई है कि समीर वानखेड़े को जिन छह मामलों की जांच से हटाया गया है, उनमें आर्यन खान केस के अलावा नवाब मलिक के दामाद का केस भी शामिल है। समीर वानखेड़े का दावा है कि उनको केस से हटाया नहीं गया है बल्कि वो खुद ऐसा करने के लिए एप्लीकेशन दिए थे। समीर वानखेड़े केस की जांच के काम से जरूर हटा दिए गए हैं, लेकिन एनसीबी के मुंबई जोन के डायरेक्टर अभी वही हैं।

मोदी कार्ड पड़ न जाए भारी

अब मतदाताओं का बदल रहा मूड

इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि मोदी भाजपा के 'यूएसपी' हैं। लेकिन अब वे ऐसे नेता नहीं रहे हैं जो अपने दम पर राज्यों में चुनाव नतीजों को बदलवा सकें। जब वे विपक्षी दलों के राज की गड़बड़ियों का इलाज करने वाली उम्मीद की एक किरण बनकर राष्ट्रीय राजनीति के मंच पर आए तब विधानसभा चुनावों में भाजपा उनके नाम पर वोट खींचती रही। इसलिए, नवंबर-दिसंबर 2013 में राजस्थान, मप्र, और छत्तीसगढ़ से शुरू करके भाजपा ने कई राज्यों में विपक्ष को सत्ता से बाहर कर दिया। मतदाताओं को मोदी पर भरोसा था कि वे अच्छा शासन दिलाएंगे, चाहे वे मुख्यमंत्री किसी को भी बनाएं। लेकिन पांच साल का चक्र पूरा होते ही लोगों ने मोदी और उनके मुख्यमंत्रियों के बीच भेद करना शुरू कर दिया। यह नवंबर-दिसंबर 2018 में हुए विधानसभा चुनावों से स्पष्ट रूप से सामने आने लगा, जब भाजपा को तीन राज्यों में हार का मुंह देखना पड़ा। वैसे, नवीन पटनायक (ओड़ीशा), के चंद्रशेखर राव (तेलंगाना), ममता बनर्जी (प. बंगाल), और अरविंद केजरीवाल (दिल्ली) सरीखे कई क्षेत्रीय नेता मोदी लहर में भी अपना खूंटा बचाए रहे।

लखनऊ में पिछले दिनों भाजपा के सदस्यता अभियान का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि वे उप्र के लोगों को यह कहने आए हैं कि 'मोदी जी को फिर एक बार 2024 में प्रधानमंत्री बनना है तो 2022 में फिर एक बार योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा।' दिल्ली और लखनऊ में पार्टी के लिए मीडिया का मोर्चा संभालने वाले जानते थे कि शाह गलत बोल रहे थे, वे अखबारों और टीवी चैनलों में भाजपा के बीट रिपोर्टरों को फोन करके कह रहे थे कि शाह के इस बयान की अनदेखी कर दें या गौण रूप से जारी करें। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि 80 सीटों वाला उप्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की कुंजी है। यह भी एक तथ्य है कि उप्र विधानसभा के नतीजे 2024 के आम चुनाव के लिए सत्ता दल और विपक्ष, दोनों के चुनाव अभियान को गति प्रदान कर सकते हैं। तो भाजपा के नेताओं की नींद अपने पूर्व पार्टी अध्यक्ष के बयान के कारण क्यों उड़ी हुई है?

इसकी वजह शायद यह है कि इसने यह आभास दिया कि प्रधानमंत्री मोदी का दोबारा चुना जाना किसी नेता, या उप्र अथवा और कहीं भाजपा के प्रदर्शन पर निर्भर करता है। यह सच भले न हो, उनसे सहमत हुआ जा सकता है। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह जब यह कहते हैं कि मोदी को एक व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि एक 'विचार', एक 'दर्शन' के रूप में देखा जाना चाहिए, तब यह 'मोदीनामा' के पाठ जैसा लग सकता है। और उनका यह कहना भी ऐसा ही लग सकता है कि महात्मा गांधी के बाद मोदी ही एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्हें भारतीय समाज और उसके मन की गहरी समझ है। अब कोई चाहे तो रक्षामंत्री को बड़बोला कह सकता है या उन पर जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल सरीखे नेताओं की अनदेखी करने का आरोप लगा सकता है, जो जनता को दिशा देने की क्षमता रखते थे। अगर बहुत मीन-मेख न निकालें तो कहा जा सकता है कि रक्षामंत्री की बातों में एक मुद्दा है। ध्यान दीजिए कि प्रशांत किशोर ने पिछले सप्ताह गोवा में एक बयान देते हुए क्या संकेत किया। किशोर ने कहा मोदी सरकार पेट्रोल-डीजल की कीमत बढ़ाती जा रही है और 'मोदी के खिलाफ कोई असंतोष नहीं दिख रहा है।' वे कोई नासमझ नहीं हैं कि वहां दखल दे रहे हैं जहां राहुल गांधी जैसे देवदूत (पोप माफ करें) दखल देने से डरते हैं। वे एक सफल चुनाव रणनीतिज्ञ इसलिए हैं क्योंकि वे अपने ग्राहकों से खरी बात करते हैं। वे केवल इसलिए चिकनी-चुपड़ी बातें करने से परहेज नहीं करते कि किसी (राहुल गांधी) के सपने न टूटें। याद कीजिए, नोटबंदी के बाद विपक्षी नेता और कई राजनीतिक विशेषज्ञ किस तरह भविष्यवाणी कर रहे थे कि 2017 के उप्र विधानसभा के चुनाव में भाजपा का सफाया हो जाएगा। लेकिन मोदी का जलवा ही चला। राजनाथ सिंह ठीक कह रहे हैं कि मोदी भारतीय समाज और उसके मन को कई लोगों से बेहतर समझते हैं।

जहां तक उप्र के चुनाव नतीजों से 2024 के आम चुनाव के अभियान को गति मिलने का सवाल है, हम यह न भूलें कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा राजस्थान, मप्र और छत्तीसगढ़ विधानसभाओं के चुनाव हारी थी। उसके बाद जो हुआ वह सब इतिहास है। 2019 में भाजपा ने उप्र में लगभग 50 फीसदी वोट हासिल किए थे, जो 2017 के विधानसभा चुनाव में हासिल वोट से 10 प्रतिशत-अंक से ज्यादा और 2014 के लोकसभा चुनाव में हासिल वोट से 7 प्रतिशत-अंक से ज्यादा थे। कहने की जरूरत नहीं कि भाजपा ने 2017 के चुनाव में मोदी की बदौलत करीब 40 प्रतिशत वोट हासिल किए थे, जबकि 2012 में उसे 15 फीसदी वोट ही हासिल हुए थे। 2017 में योगी आदित्यनाथ का असर केवल गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों तक ही सीमित था।

अमित शाह के उपरोक्त बयान से उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाखुश होने की वजहें भी हो सकती हैं। योगी आदित्यनाथ उन मुख्यमंत्रियों में से नहीं हैं जिन्हें वोट पाने के लिए मोदी के नाम की जरूरत हो। एक नेता और प्रशासक के तौर पर उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई है। 2017 से वे बहुत आगे निकल आए हैं। राजनीति और शासन चलाने की उनकी शैली से कोई सहमत हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन यह एक तथ्य है कि आज पूरे उप्र पर उनकी एक पकड़ है, भले ही वह अलग तरह से हो।

योगी आदित्यनाथ ने खुद को मोदी के उस रूप में सफलता से पेश कर लिया है जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। एक ताकतवर नेता, हिंदू हृदयसम्राट के रूप में (ध्रुवीकरण वाली उनकी राजनीति, माफिया से निबटने के उनके तौर-तरीके, नागरिकता कानून का विरोध करने वालों के प्रति उनके व्यवहार से उनके विरोधी सहमत हों या नहीं); एक विकासपुरुष (विकास के उनके दावे पर भले ही सवाल खड़े किए जाते हों) के रूप में; भ्रष्टाचार-मुक्त नेता के रूप में, जो अपने पिता का अंतिम संस्कार करने के लिए भी नहीं गया ताकि महामारी के दौरान जनता की सेवा कर सके (जैसा कि उन्होंने अपनी माताजी को लिखा)। वे कभी आरएसएस के सदस्य नहीं रहे मगर उसने उन्हें अपना मान लिया है। उनकी कार्यशैली को लेकर भाजपा में जब असंतोष उभरने लगा तो आरएसएस के बड़े पदाधिकारी (महासचिव दत्तात्रेय होसबले से लेकर संयुक्त सचिव कृष्ण गोपाल और भाजपा में तैनात आरएसएस के शख्स बीएल संतोष तक और भी लोग) लखनऊ पहुंच गए।

● **लखनऊ से मधु आलोक निगम**

PRISM®
CEMENT

प्रिज़्म® चैम्पियन प्लस

ज़िम्मेदारी मज़बूत और टिकाऊ निर्माण की.

Toll free: 1800-3000-1444
Email: ceneet.customerservice@prismjohnson.in

दूर की सोच®

लकी-चार्म नीतीश कुमार

बिहार उपचुनाव के नतीजों ने बहुत कुछ साफ कर दिया है। चुनावी जीत के लकी-चार्म नीतीश कुमार ही हैं, लालू यादव नहीं। बिहार में इस हिसाब से साफ-साफ बंटवारा हो गया है। जिधर नीतीश कुमार उधर जीत पक्की, जिधर लालू यादव उधर हार तय। लालू यादव और नीतीश कुमार साथ-साथ हों तो भाजपा हार जाती है, नीतीश कुमार भाजपा के साथ होते ही लालू यादव हार जाते हैं। बिहार में दो सीटों पर हुए उपचुनाव हर किसी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बने हुए थे- तारापुर और कुशेश्वर स्थान। नीतीश कुमार के लिए तो ये चुनाव चैलेंज थे ही, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहे जेल से जमानत पर छूटने के बाद पहली बार बिहार पहुंचे लालू यादव के लिए, और नए नवेले कांग्रेस नेता बने कन्हैया कुमार के लिए भी।

कन्हैया कुमार तो बिहार उपचुनाव के नतीजे आने के बाद लगभग वैसा ही महसूस कर रहे होंगे, जैसा 2019 का आम चुनाव प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए रहा। जैसे प्रियंका गांधी को आम चुनाव से पहले कांग्रेस में औपचारिक एंट्री दी गई थी, कन्हैया कुमार भी वैसे ही बिहार उपचुनावों से पहले कांग्रेस ज्वाइन किए थे। कन्हैया कुमार को भी उपचुनावों में हुई कांग्रेस की हार वैसी ही लगी होगी, जैसी अमेठी की हार प्रियंका गांधी वाड्रा को। चूंकि अमेठी में उम्मीदवार राहुल गांधी ही थे, लिहाजा कन्हैया कुमार को तारापुर और कुशेश्वर स्थान में कांग्रेस की जमानत जब्त हो जाने पर भी शायद उतनी तकलीफ न हुई हो। कन्हैया कुमार के लिए ये बेगूसराय **की हार** का लालू परिवार के साथ-साथ भाजपा से भी बदला लेने का बहुत बड़ा मौका रहा, लेकिन लगता है अभी उनको और इंतजार करना होगा।

ताज्जुब की बात तो ये है कि लालू यादव की मौजूदगी पूरी तरह बेकार चली गई। उपचुनाव पर लालू यादव अपनी कोई भी छाप छोड़ पाने में नाकाम साबित हुए। सिर्फ तेजस्वी यादव की कौन कहे, लालू यादव के इस कदर बेअसर हो जाने से राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं और कार्यकर्ताओं को जो झटका लगा है, उससे उबरने में भी लंबा वक्त लगेगा। लालू यादव के रांची जेल में रहते दो चुनाव हुए - पहला, 2019 का आम चुनाव और दूसरा, बिहार विधानसभा चुनाव 2020। आम चुनाव में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी को जीरो बैलेंस हासिल हुआ, जबकि गठबंधन पार्टनर कांग्रेस ने एक सीट जीत भी ली और लाल रंग उतारकर कांग्रेस का चोला धारण करने के बाद पटना पहुंचते ही कन्हैया कुमार ने लालू परिवार को इस बात के लिए ताना भी मारा था। कन्हैया कुमार मानते होंगे कि बेगूसराय संसदीय सीट पर उनकी हार में सबसे घातक आरजेडी की ही भूमिका रही। हालांकि, आंकड़े तो यही बताते हैं कि तब भी उपचुनावों जैसा ही हाल हुआ होता। केंद्रीय मंत्री और तब भाजपा उम्मीदवार रहे गिरिराज सिंह, कन्हैया कुमार और आरजेडी उम्मीदवार दोनों को मिले वोटों से काफी ज्यादा वोट पाए थे। तारापुर तो नहीं लेकिन कुशेश्वर स्थान का रिजल्ट भी यही कहानी कह रहा है।

बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव आरजेडी को सत्ता भले न दिला पाए हों, लेकिन नंबर 1 पार्टी तो बना ही दिया। एक सीट से पिछड़ कर ही सही, भाजपा भी दूसरे नंबर पर ही रह गई, लेकिन जेल से लौटने के के लालू यादव ने कुशेश्वर स्थान और तारापुर पहुंचकर पूरी ताकत लगाकर चुनाव प्रचार करने पर भी आरजेडी को हार का ही मुंह देखना पड़े, फिर तो तेजस्वी यादव के लिए भी ये नए सिरे से सोचने वाली बातें हैं। कहां लालू यादव बिहार की दो सीटों के उपचुनाव के नतीजे आने के बाद नीतीश कुमार की सरकार तक बदल डालने की बातें करने लगे थे, कहां एक भी सीट पर आरजेडी के लिए जीत सुनिश्चित नहीं कर पाए, ये तो बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए न सिर्फ हतोस्ताहित करने वाला है, बल्कि बहुत बड़ा सदमा भी है।

2014 के बाद से देश में भाजपा को चुनावी मशीन माना जाता है, लेकिन बिहार में हुए दो उपचुनावों में तो ऐसा लगा जैसे हर राजनीतिक दल भाजपा से ही प्रेरणा लेकर चुनाव मैदान में एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हो, सत्ताधारी एनडीए गठबंधन के नेता जहां लगातार इलाके में कैंप करते रहे, तेजस्वी यादव खुद तो डेरा डाले ही रहे, हर पंचायत में एक-एक विधायक को मोर्चे पर उतार डाले थे। वोटिंग से थोड़े ही पहले तेजस्वी यादव ने अपने पिता लालू यादव को भी प्रचार के लिए इलाके में बुला लिया था। एक ही दिन के लिए सही लालू यादव चुनाव प्रचार करने गए और बीमारी की हालत में भी लगा जैसे पूरी ताकत झोंक दी हो, चुनाव क्षेत्र में तो जो बोले वो बोले ही, दिल्ली से रवाना होते वक्त और पटना पहुंचते ही लालू यादव ने अपनी बातों से ऐसा माहौल तो बना ही दिया था जिससे उनकी मजबूत मौजूदगी महसूस की जाने लगी थी। लेकिन हर किसी पर वैसा असर भी नहीं लगा, जेडीयू नेता संजय झा ने तो लालू यादव की हिस्सेदारी पर वैसे ही रिएक्ट किया जैसे भाजपा नेता चुनावों में राहुल गांधी को लेकर अक्सर टिप्पणी करते रहते हैं।

● **विनोद बक्सरी**

लालू का जादू कहीं नहीं चला

दोनों चुनावों से अलग, तेजस्वी यादव ने न सिर्फ लालू यादव की मौजूदगी दर्ज कराई बल्कि चुनाव प्रचार के लिए भी इलाके में ले गए। लालू यादव ने दोनों ही चुनाव क्षेत्रों में रैली की और नतीजे आने पर नीतीश कुमार की सरकार तक गिर जाने का दावा कर डाला था। लालू यादव ने भी बढ़-चढ़कर दावे किए थे। बोले कि राजनीतिक विरोधियों को ठिकाने तो तेजस्वी यादव ने ही लगा दिए, वो तो सिर्फ विसर्जन के लिए पहुंचे हैं। नीतीश कुमार ने भी दो कदम आगे बढ़कर ही रिएक्ट किया, वो तो गोली भी मरवा सकते हैं। नीतीश कुमार के रिएक्शन के बाद लालू यादव बचाव की मुद्रा में आ गए थे। विसर्जन वाली बात पर कई बार सफाई देते भी देखे गए। इन बातों का लोगों पर कितना असर हुआ, ये अलग बात है लेकिन सबसे बड़ा सच तो यही है कि नतीजे लालू यादव के खिलाफ ही गए हैं।

जनता कार्ड

प्रदेश में कांग्रेस हो या भाजपा दोनों ही पार्टियों के सबसे बड़े दिग्गजों ने कमान संभाल लेने के संकेत दिए हैं, दोनों ही पार्टियों के दिग्गजों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और मैडम वसुंधरा राजे ने जनता को माई-बाप बताया है।

राजस्थान में विधानसभा चुनाव को अभी दो साल से ज्यादा का समय है। लेकिन हाल के दो घटनाक्रमों से लग रहा है कि चुनावी घमासान का आगाज सा हो गया है। प्रदेश में कांग्रेस हो या भाजपा दोनों ही पार्टियों के सबसे बड़े दिग्गजों ने कमान संभाल लेने के संकेत दे दिए हैं। सबसे मजे की बात यह है कि दोनों ही प्रमुख राजनीतिक पार्टियों में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर मचने वाली संभावित खींचतान के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने जनता को माई-बाप बताते हुए जनता कार्ड खेल दिया है।

हाल ही में जहां मुख्यमंत्री गहलोत ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि, 'आपने तीन बार मुख्यमंत्री बनाया है, चौथी बार का तो पता नहीं आप माई-बाप हो', तो वहीं मैडम राजे ने अपने जोधपुर दौरे के दौड़ना कहा था कि, 'किसी के चाहने से मुख्यमंत्री नहीं बनता, मुख्यमंत्री का फैसला तो जनता करेगी। जिसे 36 कौम का प्यार मिलेगा, वही मुख्यमंत्री बनेगा।' इन दोनों दिग्गजों द्वारा खेले जाने वाला यह 'जनता कार्ड' सियासी गलियारों में खासा चर्चा का विषय बना हुआ है। राजस्थान की राजनीति को जानने वालों का कहना है कि दोनों ही दिग्गजों ने विरोधियों को संकेत दिया है कि 'हमें जनता ने चुना है आप चाहे जिनती भी कोशिश कर लें होगा वहीं जो जनता चाहेगी।'

गौरतलब है कि राजस्थान की राजनीति में सियासी **घमासान चरम** पर है। सियासी कलह को करीब एक साल से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी कांग्रेस में अब तक 'तनावपूर्ण' शांति बनी हुई है। मुख्यमंत्री पद को लेकर कांग्रेस में चल रही खींचतान का दर्द गत दिनों अशोक गहलोत के भाषण में भी उस वक्त नजर आया जब वे बीते दिनों प्रशासन गांवों के संग अभियान के निरीक्षण के लिए बीकानेर के लाखासर गए थे। यहां आयोजित सभा में अपने तीन साल के कार्यकाल की चर्चा कर रहे थे। तभी भीड़ में से किसी ने कहा कि, 'चौथी बार आप ही मुख्यमंत्री बनेंगे।' इस पर मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि, 'चौथी बार कौन मुख्यमंत्री बनेगा, ये तो आप माई-बाप ही जानते हो, ये अलग बात है कि चौथी बार सरकार कांग्रेस की बननी चाहिए।'

मुख्यमंत्री गहलोत ने सियासी संदेश देते हुए कहा कि, 'बार-बार सरकार बदलती है, तो मजा नहीं आता। सरकार बदलते ही योजनाएं ठप हो जाती हैं, हम चाहते हैं कि सरकार वापस कांग्रेस की आए, ताकि हम योजनाओं पर काम कर सकें।' सियासी गलियारों में चर्चा है कि 'मुख्यमंत्री गहलोत ने अपनी पार्टी में मुख्यमंत्री फेस को लेकर घमासान पर विराम लगाते हुए जनता को माई-बाप बताकर अपने सियासी विरोधियों को जता दिया है कि जिसको जनता चाहती है उसी को मुख्यमंत्री बनाती है। वहीं कुछ सियासी जानकारों की राय इस बयान को लेकर अलग है। इनका कहना है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अगले चुनाव में कांग्रेस को जीताने की बात कह रहे हैं। जबकि 2 अक्टूबर को प्रशासन शहरों के संग अभियान के लॉन्चिंग कार्यक्रम में मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा था कि, 'अगली बार में शांति धारीवाल को ही स्वायत्त शासन मंत्री बनाऊंगा।' राजनीति के जानकारों का कहना है कि दिल्ली दौरे के बाद हुए बीकानेर के लखासर दौरे में पहले सरकार बनाने की अपील करने वाला बयान देकर मुख्यमंत्री गहलोत ने जो यूटर्न लिया है वो बहुत ही चौंकाने वाला है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शाहपुरा की सभा में ये भी कहा कि 'सियासी संकट के दौरान उनका तो इस्तीफा हो ही जाता अगर निर्दलीय विधायक और बसपा के विधायकों ने उनका साथ नहीं दिया होता। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा था कि, 'वो तो मैं जादूगर था तो मैजिक नंबर मेरे पास था।'

दूसरी तरफ बात की जाए प्रदेश भाजपा की तो यहां तो मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर एक फौज सी नजर आती है। कांग्रेस तो हर बार आरोप ही ये लगाती है कि भाजपा में मुख्यमंत्री के 8 से 10 फेस हैं। लेकिन भाजपा के एक बड़े वर्ग का मानना है कि नंबर वन पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हैं। भाजपा के साथ कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा भी मैडम राजे को सबसे बड़ा नेता मानते है। वहीं मैडम राजे ने हाल ही में जोधपुर दौरे के दौरान कहा था कि, 'सिर्फ किसी के चाहने से मुख्यमंत्री नहीं बनते, मुख्यमंत्री का फैसला तो जनता करेगी। जिसे 36 कौम का प्यार मिलेगा, वही मुख्यमंत्री बनेगा।'

● **जयपुर से आर.के. बिन्नानी**

महारानी ने भील परिवार के झोंपड़े में राब का स्वाद चखा

आपको याद दिला दें, जोधपुर दौरे के पहले दिन मैडम राजे ने ओसियां के एक भील परिवार की मनुहार पर उनके झोंपड़े में जाकर राब का स्वाद भी चखा था। वहीं मैडम राजे के जनता द्वारा मुख्यमंत्री चुने जाने के बयान के कुछ दिन बाद ही उसी जोधपुर में भाजपा में दूसरे दावेदार सतीश पूनिया के समर्थन मुख्यमंत्री पद को लेकर जबरदस्त नारेबाजी भी हुई। यही नहीं पूनिया ने भी ओसियां में एक खेत में किसानों के साथ बाजरा निकलवाया और खेत पर ही उनके साथ चाय पर चर्चा की। लेकिन हाल ही में आए वल्लभनगर और धरियावद विधानसभा उपचुनाव के परिणाम ने सतीश पूनिया की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया है और अब यह माना जाने लगा है कि प्रदेश भाजपा में मुख्यमंत्री गहलोत को टक्कर देने वाला कोई चेहरा है तो वो मैडम राजे हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि उपचुनाव में भाजपा की करारी हार वाले परिणाम से प्रदेश भाजपा में सियासी कलह और ज्यादा बढ़ेगी। वहीं दूसरी ओर मैडम वसुंधरा राजे ने खुलकर सियासी रण में उतरने के संकेत देकर चर्चाओं का बाजार पहले ही गरम कर दिया है।

ANU SALES CORPORATION

We Deal in Pathology & Medical Equipment

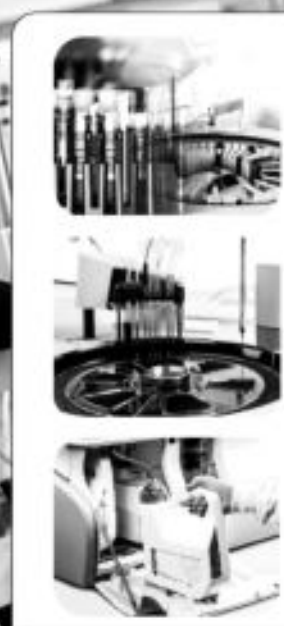

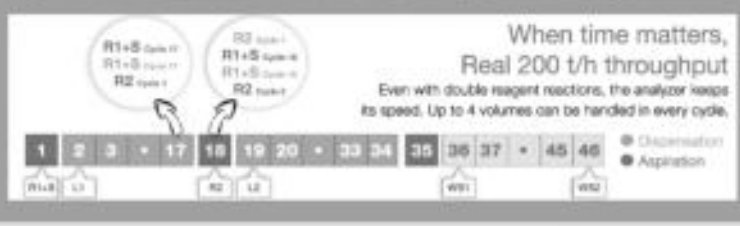

Add : Ground Floor, 17/1, Shanti Niketan, Near Chetak Bridge, Bhopal-462023

9329556524, 9329556530 Email : ascbhopal@gmail.com

अफगानिस्तान बना तस्करी का केंद्र

दुनियाभर में हेरोइन की सप्लाई का 80 फीसदी हिस्सा अफगानिस्तान से जाता है। अफीम के निर्यात से अफगानिस्तान की 2 अरब डॉलर से ज्यादा की सालाना कमाई होती है जो उसकी जीडीपी का 11 फीसदी है। ऐसे में तालिबान अफीम की पैदावार पर रोक लगाएगा और मादक पदार्थों के कारोबार को खत्म करेगा, यह सोचना भी हास्यास्पद है। इसके लिए सभी देशों को मिलकर ड्रग्स कारोबार और उससे जुड़े गंभीर अपराधों का मुकाबला करने की रणनीति बनानी होगी। क्योंकि इस समय तालिबान ड्रग्स की तस्करी का केंद्र बन गया है। गत दिनों गुजरात के मुंद्रा पोर्ट से 3 हजार किलो हेरोइन पकड़ी गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी कीमत 21 हजार करोड़ रुपए है। गौरतलब है कि मुंद्रा पोर्ट को उद्योगपति गौतम अडानी चलाते हैं। पकड़ी गई ड्रग्स (हेरोइन) को 2 कंटेनरों में रखा गया था, जिनके ऊपर पाउडर रखे होने की बात लिखी गई थी। ये दोनों कंटेनर ईरान से आए थे। एक कंटेनर में 2 हजार किलो और दूसरे कंटेनर में एक हजार किलो हेरोइन थी।

अफगानिस्तान में तैयार इस हेरोइन को गुजरात बंदरगाह पर भेजा गया था, जहां से यह मुंबई से लेकर पंजाब तक पहुंचाई जानी थी। इतनी भारी तादाद में अतिपरिष्कृत नशीले पदार्थ का पकड़ा जाना एके-47 बंदूकों के पकड़े जाने से ज्यादा चिंताजनक है। यह हिंदुस्तान के युवाओं को अफीमची बनाकर असमय मौत की ओर धकेलने का खतरनाक षड्यंत्र है। सामाजिक कार्यकर्ता और श्रमिक संगठन 'सीटू' के राज्य सचिव शैलेंद्र सिंह ठाकुर कहते हैं, 'ये हेरोइन, स्मैक और ब्राउन शुगर सब चलताऊ नाम हैं। असली नाम है मार्फीन, जो अफीम को प्रोसेस करने के बाद पहले एल्केलाइड के रूप में बनता है। 120 किलो अफीम से 40 किलोग्राम मार्फीन बनती है। इस हिसाब से मुंद्रा पोर्ट पर पकड़ी गई 3 हजार किलो मार्फीन बहुत ही विराट मात्रा है।' मुंद्रा पोर्ट पर 3 टन हेरोइन की जब्ती से पहले 72 हजार करोड़ रुपए की 24 टन मार्फीन भी पहुंच चुकी थी, जो टैलकम पाउडर कहकर विजयवाड़ा से गुजरात तक गई और मार्केट में खपा दी गई। अक्टूबर माह में एक गुप्त सूचना के आधार पर राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) की टीम ने मुंबई पोर्ट पर छापा मारा, जहां उन्हें एक कंटेनर से 25 किलो हेरोइन बरामद हुई।

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी कीमत 125 करोड़ रुपए थी। इस संबंध में नवी मुंबई के 62 साल के एक कारोबारी जयेश सांघवी को गिरफ्तार किया गया। सांघवी ईरान से मूंगफली के तेल की खेप में इस हेरोइन को छिपाकर लाया था। यह कंटेनर वैभव एंटरप्राइजेज के संदीप ठक्कर ने इम्पोर्ट किया था, जिनका मुंबई के मसजिद बंदर इलाके में बड़ा ऑफिस है। हेरोइन लाने के लिए तस्करों की यह तरकीब नई थी। राजस्व खुफिया निदेशालय को शक है कि जयेश सांघवी एक बड़े सिंडिकेट का हिस्सा है और इस तरह की खेपें उसके जरिए भारत में पहले भी आई हैं, मगर अभी तक पुलिस उससे कुछ खास नहीं उगलवा पाई है। इसी साल जुलाई माह में राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई बंदरगाह से ही 293 किलो हेरोइन जब्त की थी, जिसकी कीमत 2 हजार करोड़ रुपए आंकी गई थी। उस कंसाइनमेंट को नवी मुंबई के जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से सड़कमार्ग के जरिए पंजाब भेजा जाना था। उस मामले में डीआरआई ने पंजाब के तरणतारण के रहने वाले संधू एक्सपोर्ट पंजाब के मालिक प्रभजीत सिंह को गिरफ्तार किया है। पिछले महीने मुंबई एयरपोर्ट से 5 किलो हेरोइन के साथ 2 महिलाएं भी गिरफ्तार हुई थीं। यह किसी भी एयरपोर्ट में मिलने वाली ड्रग्स की सबसे बड़ी खेप में से एक थी। उनके पास से मिली हेरोइन की कीमत 25 करोड़ रुपए थी। दोनों महिलाओं की पहचान मांबेटी के तौर पर हुई जो दक्षिण अफ्रीका के जोहानबर्ग से आई थीं। साउथ दिल्ली के इलाके में जहां बड़ी संख्या में अफ्रीकी नागरिक बसे हैं और रामकृष्ण मठ के आसपास रहने वाले विदेशियों के पास अफीम, मार्फीन, हेरोइन, चरस, गांजा जैसे नशीले पदार्थों का मिलना बहुत आम है। ये चंद बानगी हैं जो यह बताने के लिए काफी हैं कि हर महीने कितनी भारी मात्रा में नशीले पदार्थ भारत में आ रहे हैं और ड्रग्स का कारोबार हिंदुस्तान में कितने बड़े पैमाने पर चल रहा है।

अफीम की खेती, उत्पादन और उसको जब्त किए जाने के मामलों को अगर ग्राफ में देखें तो यह स्पष्ट है कि बीते 2 दशकों के दौरान अफगानिस्तान में यह लगातार बढ़ा है। अमेरिकी वाचडॉग स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल फॉर अफगान रिकंस्ट्रक्शन के मुताबिक, अफीम को जब्त किए जाने और तस्करों की गिरफ्तारी का इसकी खेती पर कोई असर नहीं पड़ता है। जानकारों का मानना है कि तालिबान के लिए ड्रग्स के कारोबार पर काबू पाना आसान नहीं है क्योंकि अफगानिस्तान के कई प्रांतों में अफीम की खेती ही लोगों की आमदनी का एकमात्र जरिया है।

● **ऋतेन्द्र माथुर**

अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था में 11 प्रतिशत हिस्सेदारी अफीम की

2018 में यूएनओडीसी के आंकलन के मुताबिक, अफगानिस्तान की कुल अर्थव्यवस्था में 11 प्रतिशत की हिस्सेदारी अफीम उत्पादन की थी। हालांकि, तालिबान दावा कर रहा है कि उसने अफगानिस्तान में अपने पिछले शासनकाल के दौरान अफीम की खेती पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी थी, जिसके चलते गैरकानूनी ड्रग्स का कारोबार थम गया था। 2001 में अफगानिस्तान में अफीम के उत्पादन में कमी जरूर देखी गई थी लेकिन बाद के सालों में तालिबान नियंत्रित इलाकों में अफीम की खेती बढ़ती गई। यहां अफीम को इस तरह से परिष्कृत किया जाता है कि उससे काफी अधिक नशा देने वाले हेरोइन और मार्फीन जैसे ड्रग्स तैयार हों। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि जैसे-जैसे मुनाफा बढ़ता जाता है, पूंजी की हवस और ताकत बढ़ती जाती है। पूंजी मुनाफे के लिए कुछ भी कर सकती है। वह 10 फीसदी के लिए कहीं भी चली जाती है, 20 फीसदी मुनाफा हो तो इसके खुशी का ठिकाना नहीं रहता। 50 फीसदी के लिए यह कोई भी दुस्साहस कर सकती है। 100 फीसदी मुनाफे के लिए तो यह मानवता के सारे नियम-कायदे कुचल डालने को तैयार हो जाती है और 300 फीसदी मुनाफे के लिए तो यह कोई भी अपराध ऐसा नहीं जिसे करने को तैयार न हो जाए।

एलएसी पर जारी रहेगी तकरार

क्या भारत-चीन संबंधों में तनाव व टकराव और बढ़ने के आसार हैं? क्या पिछले साल लद्दाख में हुई चीनी घुसपैठ सिर्फ एक बानगी है जो आने वाले समय में उसके मंसूबों को उजागर करती है? क्या बीजिंग सीमा विवाद पर भारत को लंबे समय तक उलझाए रखने की रणनीति पर चल रहा है और उसने उसके हिसाब से ही रणनीति बनाई है? अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने अपनी ताजा रिपोर्ट में जोर देकर कहा है कि चीन भारत की सीमा पर अपने दावों को हासिल करने के लिए रणनीतिक कार्रवाई पहले की अपेक्षा तेजी से कर रहा है। इसने यह भी कहा है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए यानी चीनी सेना ने पूर्वी लद्दाख में घुसपैठ कर वास्तविक अनुभव भी हासिल कर लिया है और अपनी योजनाओं को जमीनी स्तर पर उतारने की दिशा में वह आगे बढ़ रही है।

पेंटागन ने चीन से जुड़ी सैन्य व सुरक्षा मामले नामक एक रिपोर्ट हाल के दिनों में जारी की है। इसमें इस पर भी चिंता जताई गई है कि चीन ने तिब्बत व अरुणाचल प्रदेश के बीच विवादित जमीन पर सौ घरों वाला एक गांव बसा लिया है। यह गांव त्सारी चू नामक नदी के किनारे बसा हुआ है। यह इलाका 60 साल से चीन के नियंत्रण में हैं, लेकिन उसने अब वहां **एक गांव बसा लिया** है, जो पूरी तरह उसके नियंत्रण में है। भारत और चीन के बीच 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा है। इस गांव का महत्व यह है कि इसे सामान्य गांव के रूप में भले ही बसाया गया हो, जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल एक कैन्टोनमेंट एरिया के रूप में भी किया जा सकता है। पूर्वी कमान के प्रमुख लेफ्टीनेंट जनरल मनोज पांडेय ने कहा कि दुहरे प्रयोग वाला यह गांव भारत की निगाह में है और वह उसे ध्यान में रख कर ही अपनी योजनाएं बना रहा है।

अमेरिकी रक्षा विभाग ने इस रिपोर्ट में चीन की बढ़ती सैन्य मौजूदगी और तैयारियों पर चिंता जताई है। इसमें कहा गया है कि छह साल में चीन के पास 700 से ज्यादा परमाणु हथियार होंगे और 2030 तक इनकी तादाद बढ़कर एक हजार के पार हो जाएगी। पेंटागन की रिपोर्ट में कहा गया है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी आने वाले समय में भारत से सटे वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर अपनी मौजूदगी और बढ़ाएगी, अपने सैनिकों को वहां टिकाए रखने की तैयारी करेगी। इसमें यह भी कहा गया है कि दोनों देशों के बीच हुई बाचीत का कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। पेंटागन की रिपोर्ट में कहा गया है, पीएलए ने मई 2020 में भारत के नियंत्रण वाले इलाकों में घुसपैठ की शुरुआत की, इसके बाद कई विवादित जगहों पर सेना तैनात कर दी। इसके अलावा तिब्बत व शिनजियांग सैन्य जिले में बड़े पैमाने पर सैन्य तैनाती की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन ने सीफोरआई (कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर एंड इंटेलीजेन्स) प्रणाली लागू की है। इसके तहत पीएलए ने पश्चिमी हिमालय में अपने इलाके में ऑप्टिक फाइबर का जाल बिछा दिया है ताकि तेज रफ्तार से संपर्क स्थापित किया जा सके।

इसमें यह भी कहा गया है कि चीन ने भारत में सैन्य घुसपैठ करते हुए भारत के उकसावे का बहाना किया, वह आने वाले समय में एलएसी यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपनी सैन्य मौजूदगी बनाए रखेगा और एलएसी की अपनी परिभाषा को लागू करेगा, यानी जहां तक वह दावा करता है वहां तक अपने सैनिकों की तैनाती करेगा। अमेरिकी रक्षा विभाग हर साल इस तरह की रिपोर्ट तैयार करता है और चीन उसके फोकस पर हमेशा ही रहता है। पर्यवेक्षकों का कहना है कि इस बार मामला अधिक गंभीर इसलिए है कि चीन और अमेरिका के बीच रिश्ते पहले से बदतर हैं, भारत-चीन रिश्तों में तल्खी बनी हुई है और भारत-अमेरिकी नजदीकियां बढ़ी हैं।

चीन को रोकने की कोशिश का बड़ा कारण यह है कि 1980 के दशक में जब तत्कालीन चीनी नेता देंग शियाओ पिंग ने चीनी अर्थनीति में बुनियादी बदलाव किया तो अगले 20 साल में चीन की औसत आर्थिक विकास दर 10 प्रतिशत के आसपास रही। ऐसा समय भी आया जब चीन ने 20 प्रतिशत तक की वृद्धि दर्ज की। इसका नतीजा यह हुआ कि चीनी अर्थव्यवस्था दुनिया की दूसरी नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुकी है, उसके पास उसकी अपनी जरूरतों से ज्यादा उत्पादन भी है और पैसे भी। ये पैसे और ये उत्पाद चीन में नहीं खप सकते, लिहाजा उसे बाहर भेजना है और दूसरे देशों में सस्ती कीमत पर ये उत्पाद और तकनीक देकर वहां के व्यापार पर कब्जा जमाना है। इससे जुड़ा हुआ मामला है चीनी सपना यानी चाइनीज ड्रीम का, जिसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। शी जिनपिंग ने राष्ट्रपति बनने के कुछ दिन बाद 2014 में चाइनीज ड्रीम का ऐलान किया। आसान शब्दों में कहा जाए तो यह सपना चीन को पुनर्जीवित कर आर्थिक सैन्य और राजनीतिक मामलों में दुनिया का सबसे समृद्ध देश बनाना है। शी जिनपिंग ने कहा था कि यह काम 2049 में हो जाना चाहिए। चीनी क्रांति 1949 में हुई थी, यानी इस कृषक क्रांति या समाजवादी क्रांति के जब सौ साल पूरे हों तो चीन दुनिया का सबसे समृद्ध, प्रतिष्ठित और सुरक्षित देश रहे। इसका अर्थ लगाया गया कि 2049 में पूरी दुनिया पर चीन का बोलबाला रहे।

● **कुमार विनोद**

भारत-अमेरिका रिश्ते

चीन ने भले ही औपचारिक तौर पर भारत को अपना सैन्य साझेदार घोषित न किया हो, पर वह कई बार भारत को अपना मित्र व साझेदार कह चुका है। इसके अलावा दक्षिण चीन सागर में जिस तरह अमेरिका चीन की घेराबंदी कर रहा है और भारत उसमें बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहा है, उसकी छाप भी इस रिपोर्ट पर दिख रही है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान व अमेरिका का समूह क्वाडिलैटरल स्ट्रैटजिक डायलॉग्स यानी क्वाड जिस तरह तेजी से बढ़ रहा है और वाशिंगटन हिंद प्रशांत क्षेत्र यानी इंडो पैसिफिक एरिया में भारत की भूमिका की बात बार-बार कह रहा है, उससे भी साफ है कि अमेरिका की नजर भारत-चीन संबंधों पर है। वाशिंगटन चाहता है कि वह दिल्ली का इस्तेमाल बीजिंग के खिलाफ करे, भले ही इससे भारत-चीन में वैमनस्य बढ़े। पेंटागन की रिपोर्ट सच्चाई पर आधारित है, यह सच है, उसकी बातों में दम है और चीन से भारत को खतरा काल्पनिक नहीं, सच्चाई है, यह भी सच है। पर यह भी सच है कि अमेरिका भारत-चीन रिश्तों की तल्खी का इस्तेमाल चीन को रोकने की अपनी रणनीति में करना चाहता है। पेंटागन की रिपोर्ट पढ़ते समय यह बात भी ध्यान में रखना जरूरी है। यह अंतरराष्ट्रीय राजनीति का समीकरण है।

SCIENCE HOUSE
MEDICAL PVT. LTD.
For Any Medical &
Pathology Equipments
Contact Us
D-10™ Hemoglobin Testing System
For HbA$_{1c}$, HbA$_2$ and HbF
Flexible
to solve more testing needs
Comprehensive
B-thalassemia and diabetes testing
Easy
for simple operation
Dependability is about more than keeping your laboratory running smoothly; It's about the quality diabetes care you support. That's why we developed the D-10™ System with reliability and efficiency in mind.
A simple, fully-automated solution, the D-10™ System Combines diabetes and B-thalassemia testing, enabling rapid HbA$_{1c}$ or HbA$_2$/F/A$_{1c}$ testing using pripary tube sampling-so you can accomplish more in fewer steps, With the D-10™ System, It's easier to deliver a full picture of diabetes treatment progress-and that can be the difference for the people who count on you most.
17/1, Sector-1 Shanti Niketan, Near Chetak Bridge, Bhopal (M.P.) India-462023
GST.No. : 23AAPCS9224G1Z5 Email : shbple@rediffmail.com
Phone : +91-0755-4241102, 4257687, Fax : +91-0755-4257687

ऑस्ट्रेलिया बना सरताज

आंखों में आंखें डालकर खेलने वाली। उकसाने वाली। धमकाने वाली। गरियाने वाली। हमेशा जीत की तलाश में रहने वाली। ये कुछ पहचान है ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट की। आप इसे पसंद करें या नापसंद, कभी इग्नोर नहीं कर सकते। उस वक्त भी नहीं जब यह टीम अपने इतिहास के सबसे खराब दौर में से एक से गुजर रही हो। इस टी-20 वर्ल्ड कप ने इसी बात की पुष्टि की है। अहम मुकाबलों में सिक्के की उछाल के रूप में किस्मत भले ऑस्ट्रेलिया के पाले में गिरी, लेकिन टीम ने यह खिताब गजब के जज्बे और बहुत सारे आत्मविश्वास की बदौलत जीता है।

टूर्नामेंट से पहले ऑस्ट्रेलिया को लगातार पांच टी-20 सीरीज में हार झेलनी पड़ी थी। यह भी किसी एक या दो टीम से नहीं। जिसके साथ भी खेलने उतरी सबसे हार मिली। इंग्लैंड ने हराया। भारत ने हराया। न्यूजीलैंड ने मात दी। वेस्टइंडीज ने धो दिया। हद तो तब हो गई जब बांग्लादेश ने भी इसे पीट दिया। इन नतीजों के साथ ऑस्ट्रेलिया की टीम उस ख्वाब को पूरा करने यूएई पहुंची जो वह पिछले 14 साल से देख रही थी। 6 बार नाकामयाब रही। खिताब छोड़िए इस बार टीम को बहुत मुश्किल से सेमीफाइनल में पहुंचने का दावेदार माना गया था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने विजेता का ताज पहन लिया। इस टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े स्टार बनकर उभरे डेविड वार्नर। वैसे तो 5 फीट 5 इंच लंबा यह खिलाड़ी बल्लेबाजों की दुनिया में गगनचुंबी नाम है, लेकिन लंबे समय से फॉर्म में नहीं था। वार्नर इस कदर खराब फॉर्म में थे कि उनकी आईपीएल टीम सनराइजर्स हैदराबाद ने उन्हें पहले कप्तानी से हटाया फिर प्लेइंग-11 से भी बाहर कर दिया। हैदराबाद के कुछ मैचों के दौरान उनके स्टेडियम आने पर रोक लगा दिए जाने की खबर भी आई थी। ऑस्ट्रेलिया ने इसके बावजूद वार्नर पर भरोसा किया और वर्ल्ड कप की टीम में शामिल किया। अब वार्नर ने अपने प्रदर्शन से साबित कर दिया कि क्रिकेट में फॉर्म टेम्पररी होता है और क्लास परमानेंट।

ऑस्ट्रेलिया को इस वर्ल्ड कप में एक ऐसा ऑलराउंडर मिल गया जो आने वाले समय में दुनियाभर की क्रिकेट में वैसा ही तहलका मचा सकता है जैसा इंग्लैंड के लिए बेन स्टोक्स ने मचाया था। उस ऑलराउंडर का नाम है मिचेल मार्श। वे लंबे समय से खेल रहे हैं, लेकिन उम्मीद के मुताबिक डिलीवर नहीं कर पा रहे थे। इस टूर्नामेंट में आखिरकार अपना जलवा दिखा दिया। मिडिल ओवर में उनके रूप में ऑस्ट्रेलिया को सही मायने में एक पावर हिटर मिल गया है। उनकी बल्लेबाजी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया की टीम पावर प्ले और डेथ ओवर के बीच के फेज में भी मोमेंटम कायम रखने में सफल रही। इस मामले में टूर्नामेंट की ज्यादातर टीमों ने संघर्ष किया।

वहीं भारत की टीम की बात करें तो यह टीम अपेक्षा पर पूरी तरह खरी नहीं उतरी है। चाहे टीम के कप्तान विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी हों या फिर टीम के बॉलर्स हर कोई आलोचकों के निशाने पर है। वो तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स जो कल तक टीम इंडिया को पूरे टी-20 वर्ल्ड कप की बेस्ट टीम बता रहे थे आज डंके की चोट पर इस बात की घोषणा कर रहे हैं कि सिलेक्टर्स द्वारा बड़ी चूक हुई है। ऐसे लोगों का ये भी कहना है कि यदि टीम का चयन ईमानदारी से हुआ होता तो आज स्थिति कुछ दूसरी होती। हो सकता है टीम इंडिया टी-20 वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब होती। इसमें कोई शक नहीं है कि टीम इंडिया की जो हालत यूएई में हुई है उसने क्रिकेट के देश भारत को शर्मसार किया है। जिस तरह बीसीसीआई से लेकर कोच, कप्तान, एक्सपर्ट्स द्वारा भारतीय टीम की कमी को छुपाया जा रहा हो वो गहरी चिंता का विषय इसलिए भी है क्योंकि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हम अपने खिलाड़ियों के साथ धोखा कर रहे हैं।

हमें इस बात को समझना होगा कि अगर हमने इस समय टीम इंडिया को उसकी कमियों से अवगत नहीं कराया तो फिर आने वाले वक्त में हमारे पास संभालने को कुछ नहीं रहेगा। बात बहुत सीधी है टी-20 विश्वकप से टीम इंडिया के बाहर होने पर अब सिर्फ लकीर पीटी जा रही है। ध्यान रहे जिस न्यूजीलैंड से टीम इंडिया ने अपने दूसरे टी-20 मैच में करारी शिकस्त का मुंह देखा उसी न्यूजीलैंड की बदौलत टीम इंडिया टी-20 वर्ल्ड कप से बाहर हुई है। या ये भी कह सकते हैं कि ये न्यूजीलैंड ही था जिसने टीम को बाहर का रास्ता दिखाया और हर उस शख्स को जो भारतीय टीम को कप का प्रबल दावेदार मान रहा था, बताया कि विदेशी पिचों पर टी-20 फॉर्मेट पर मैच खेलना और उसे जीतना अब भी भारत के लिए टेढ़ी खीर है।

गौरतलब है कि यूएई से वापस आने के बाद कप्तान विराट कोहली ने टीम की परफॉरमेंस पर बात की है और उन कारणों पर विस्तृत चर्चा की है जिनके चलते आसान से मैचों में भारत को हार का सामना करना पड़ा। कप्तान कोहली का मानना है कि यूं इस तरह भारतीय टीम के टूर्नामेंट से बाहर होने के चलते खिलाड़ियों में निराशा है। भले ही इस टूर्नामेंट के अपने आखिरी मैच में भारत ने नामीबिया को 9 विकेटों से हरा दिया हो लेकिन ये कहना कहीं से भी गलत नहीं है कि भारतीय टीम शुरुआत से ही कप जीतने के मूड में नहीं थी।

● आशीष नेमा

हर खिलाड़ी निकला सुपरहीरो

वार्नर और मार्श के अलावा ऑस्ट्रेलिया की ओर से और भी कई सुपर हीरो निकले। सच तो यह है कि इस टीम का हर खिलाड़ी अपने आप में सुपरहीरो साबित हो रहा है। जिसका दिन होता है वही मैच निकाल देता है। अगला टी-20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में होगा। यह टीम घरेलू कंडीशंस में एक बार फिर खिताब की मजबूत दावेदार होगी। एक पहलू और याद रखिए। ऑस्ट्रेलिया को पहला वनडे वर्ल्ड कप जीतने में चार टूर्नामेंट और 12 साल लगे थे। फिर जब इसने जीत का स्वाद चखा तो पांच वर्ल्ड कप अकेले ले उड़ा। अब टी-20 में भी शुरुआत हो गई है। भले 14 साल लगे हों। दूसरी टीमों को सावधान हो जाना चाहिए।

वीर-जारा के सेट पर यश चोपड़ा ने रानी और शाहरुख को लगाई थी जमकर डांट

द कपिल शर्मा शो के एक एपिसोड में फिल्म बंटी और बबली 2 के एक्टर सैफ अली खान, रानी मुखर्जी, सिद्धांत चतुर्वेदी और शरवरी वाघ स्पेशल गेस्ट के रूप में नजर आएं। शो ने रानी ने कहा कि वो और शाहरुख खान वीर-जारा की शूटिंग के दौरान अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे थे। वो फिल्म के दूसरे पार्ट में दिखाई दीं, जहां शाहरुख को झूठे आरोपों में जेल में बंद एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में दिखाया गया था, और रानी ने उनके वकील की भूमिका निभाई थी।

रानी ने कहा कि उन्होंने हमेशा शाहरुख के साथ रोमांटिक सीन किए थे और वहां वो उनके सामने थे, एक बूढ़े आदमी के गेट-अप में, सफेद बाल और सफेद दाढ़ी के साथ। रानी ने खुलासा करते हुए बताया कि वो दोनों तब तक हंसते रहे जब तक डायरेक्टर यश चोपड़ा ने उन्हें डांटा नहीं। रानी कहती हैं, अब मैं शाहरुख के साथ सीन करूं तो मुझे उनकी आंखों में देख के रोमांस करना है। अब वो नहीं कर सकते हैं क्योंकि मुझे पिता वाली फीलिंग लानी है, उनको बेटी वाली फीलिंग लानी है, और वो हो ही नहीं पा रहा है हमसे। रानी आगे कहती हैं, हम दोनों से नहीं हो रही है।

और हम हंसे जा रहे हैं। फाइनली, यश अंकल ने इतना डांटा हमें, हम दोनों इतने घबरा गए की हमने बोला, नहीं नहीं, अभी हमें ठीक से करनी पड़ेगी। लेकिन उस समय इतना मुश्किल हुआ था।

फिल्म वीर-जारा, जिसमें प्रीति जिंटा, अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, मनोज बाजपेयी और दिव्या दत्ता ने भी अभिनय किया, ने 2004 में नेशनल फिल्म अवार्ड में संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली बेस्ट पॉपुलर फिल्म का पुरस्कार जीता था।

पृथ्वीराज कपूर की मदद से पेशावर से मुंबई आए थे बोनी कपूर के पिता, इंडस्ट्री की फर्स्ट फैमिली से रखते हैं ताल्लुक

वो सात दिन, जुदाई, मिस्टर इंडिया जैसी दर्जनों ब्लॉकब्ट फिल्में प्रोड्यूस कर चुके बॉलीवुड के पॉपुलर फिल्ममेकर बोनी कपूर के पिता सुरिंदर कपूर इंडिया सिनेमा के जाने-मानें प्रोड्यूसर थे जो पेशावर से मुंबई आकर बसे थे। कम लोग ही जानते हैं कि बोनी कपूर इंडस्ट्री की फर्स्ट फैमिली कहे जाने वाले कपूर खानदान से सीधा ताल्लुक रखते हैं। बोनी कपूर के पिता सुरिंदर कपूर का जन्म पेशावर में हुआ था। पृथ्वीराज कपूर के पिता बशेश्रवर नाथ कपूर भी पेशावर में पुलिस ऑफिसर हुआ करते थे, जो आपस में रिश्तेदार थे। पृथ्वीराज कपूर और सुरिंदर चचेरे भाई हुआ करते थे। पृथ्वीराज कैरियर बनाने के लिए पेशावर से मुंबई चले आए थे, जहां उनके हुनर ने उन्हें खूब फेम और कामयाबी हासिल करवाई थी। खुद सेटल होने के कुछ सालों बाद पृथ्वीराज कपूर ने सुरिंदर को मुंबई बुला लिया। यहां सुरिंदर ने शुरुआत में गीता बाली का पर्सनल असिस्टेंट बनकर काम किया। इसके बाद उन्होंने फिल्म प्रोडक्शन में कदम रखा। सुरिंदर, राज कपूर, शशि कपूर और शम्मी कपूर के कजिन थे। सुरिंदर के तीन बेटे बोनी कपूर, अनिल कपूर और संजय कपूर हैं।

गरीबी की वजह से पढ़ाई छोड़कर बेस्ट बस में कंडक्टर की नौकरी करते थे जॉनी वॉकर, फिर बन गए दिग्गज कॉमेडियन

जॉनी वॉकर एक ऐसे अभिनेता के तौर पर नजरों के सामने तैरने लगते हैं, जिन्होंने अपनी अदाकारी से न केवल लोगों को गुदगुदाया, बल्कि उनके चहरे पर मुस्कान भी बिखेर दी। जॉनी बचपन से ही एक्टर बनने का ख्वाब देखा करते थे। 1942 मे उनका पूरा परिवार मुंबई आ गया था। 10 भाई-बहनों में दूसरे नंबर पर रहे जॉनी परिवार का पेट पालने के लिए बेस्ट बस सर्विस में कंडक्टर की नौकरी करते थे। इस नौकरी के लिए उन्हें 26 रुपए मिलते थे। बता दें, जॉनी को गरीबी की वजह से महज छटवीं क्लास के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी। जॉनी को कंडक्टर की नौकरी करते-करते मुफ्त में फिल्म स्टूडियो जाने का मौका मिल जाया करता था। उन्हें जल्द ही फिल्मों में भीड़ वाले सीन में खड़े होने का मौका मिल गया। जिसके लिए उन्हें 5 रुपए मिला करते थे। इसी दौरान जॉनी वॉकर की मुलाकात फिल्म जगत के मशहूर विलेन अंसारी और के आसिफ के सचिव रफीक से हुई। लगभग 7-8 महीने के स्ट्रगल के बाद जॉनी वॉकर को फिल्म आखिरी पैमाने मे एक छोटा सा रोल मिला। जिसके लिए उन्हें 80 रुपए मिले थे। इसके बाद वे कई फिल्मों में कॉमेडियन के रोल में नजर आए।

लाइक-कमेंट का सवाल है बाबा

यह बड़ा निर्मम जगत है। यहां लाइक की फसल काटने के लिए रोज लाइक के बीज बोने ही पड़ते हैं। तमाम पोस्ट्स एक-एक लाइक को तरस गई हैं। लगता है कि लोगों को फेसबुकी सुंदरियों के प्रोफाइल पिक्चर्स पर भंवरों-सा मंडराने से ही फुर्सत नहीं मिल रही है।

फेसबुक वाल्स के शो-केस में कई पोस्ट्स सजी-संवरी बैठी हैं। उन्हें इंतजार है एक अदद प्यारे-प्यारे लाइक-कमेंट का, लेकिन कोई ऐसा करने के लिए फटकता ही नहीं। जैसे फुटपाथ के दुकानदार कभी-कभी ग्राहक के लिए तरसते रहते हैं, ठीक वैसे ही मेरी फेसबुक पोस्ट को लाइक-कमेंट के लिए तरसना पड़ रहा है। कोई मेहरबान है कि इधर आता ही नहीं। मेरी तमाम पोस्ट्स एक-एक लाइक को तरस गई हैं। लगता है कि लोगों को फेसबुकी सुंदरियों के प्रोफाइल पिक्चर्स पर भंवरों-सा मंडराने से ही फुर्सत नहीं मिल रही है।

सुंदरियों की एक झलक पर लाइक तो लाइक कमेंट पर कमेंट तक अपना नेह बरसाने वाले वैसे ही सक्रिय रहते हैं, जैसे आइटम-डांस में नायिकाओं के ठुमकों पर चिल्लरें बरसाने वाले। बेचारे हम जैसे गरीब आदमी का तो पोस्ट ही रुखा पड़ा है। जैसे 'कबीरा खड़ा बाजार में..ज्ञान दियो बिखराय..जिसको जितना चाहिए..समेट-समेट ले जाए!' मगर यहां तो कोई ज्ञान समेटने ही नहीं आता।

कितनी नव-यौवना कविताएं घूंघट के पट खोलने को आतुर खड़ी हैं। कोई उनके जलवों का दीदार ही नहीं करना चाहता। कितने बाबाजी गुरु-ज्ञान का घंटा लेकर साक्षात खड़े हैं। कोई उनकी सुध ही लेने वाला नहीं। कितनी बीमारियों के नुस्खे नीम-हकीम बने अपना झोला लिए खड़े हैं। लगता है कि कोई स्वस्थ ही नहीं होना चाहता। बड़ा ही निर्मम जगत है बाबा। लाइक लाइक होकर भी ना-लाइक बना हुआ है। इसमें फेसबुक के बाजार की रंगीनियत का कोई कसूर नहीं। भला कीजे भला होगा, बुरा कीजे बुरा होगा! जैसा तेरा गाना होगा, वैसा मेरा बजाना होगा। तू ना-लाइक है तो मैं तुझे लाइक कैसे करूं। तू लाइक करे तो मैं लाइक क्या कमेंट भी कर दूं।

लाइक की फसल काटने के लिए रोज लाइक के बीज तो बोने पड़ते हैं। ये नकद की फसल है बाबू। यह उधार की बंजर जमीन पर लाइक-कमेंट के अंकुर नहीं पोषती। मगर किसी-किसी मौसम फसल अच्छी भी हो जाती है। तब पोस्ट की उपजाऊ जमीन पर लाइक के साथ-साथ कमेंट के फल भी उग आते हैं। मगर ये फल नकद नहीं होते। सूद समेत कमेंट के रूप में लौटने भी पड़ते हैं। तभी तो फेसबुक पर लेन-देन का मौसम-चक्र बना रहता है। फलों के बीज से फिर-फिर फल निकलते हैं और उन फलों से फिर नए फल उगाए जाते हैं।

फेसबुक पर ऐसे ही तो कारोबारी-दोस्ती का निर्वाह होता है। लाइक के बदले लाइक और कमेंट के बदले कमेंट का भी खेल चलता है। कभी-कभी आपकी पोस्ट पर बड़े-बड़े सूदखोर साहूकार मित्र भी आ जाते हैं। वे अपने लाइक-कमेंट का हिसाब-किताब रखने का हुनर खूब जानते हैं। अव्वल तो वे लाइक का बटन दबाते ही नहीं और अगर गलती से दब जाए तो जजिया कर की वसूली से भी नहीं चूकते। वे दोस्त दोस्ती के लिए नहीं बनाते, बल्कि बंधुआ मजदूर के रूप में लाइक-कमेंट की साहूकारी वसूली के लिए बनाते हैं। वे खुद कभी किसी की पोस्ट लाइक नहीं करते। मगर अपने लाइक की स्वनामधन्य वसूली से भी गुरेज नहीं करते। जो मजदूर उनकी पोस्ट पर लाइक न करे, वह उनकी दोस्ती के गांव से देश-निकाला दे दिया जाता है।

अब यह अलग बात है कि बीच-बीच में ये साहूकार मजदूर मित्र को अपने लाइक के रूप में अंतरिम मेहनताना अवश्य चुकाते रहते हैं, ताकि मजदूर मित्र का हौसला बना रहे। कभी-कभी वे राजे-रजवाड़ों सा खुश होकर दरियादिली दिखाते हुए मजदूर मित्र को कमेंट रूपी बोनस भी इनाम-इकराम में बांट देते हैं। वे खुश होकर मजदूर के कमेंट बाक्स में लिखते हैं जैसे कि 'बढ़िया है, अच्छा है, खूब या नाइस वगैरह।' या कभी-कभी एक स्माइली भी भेंट स्वरूप गले से कंठी की तरह निकालकर कमेंट बाक्स में उछाल देते हैं! ये इनामी शब्द साहूकार मित्र इतनी मितव्ययिता से लिखते हैं कि लगता है कि यदि बंदे की इससे अधिक तारीफ लिख दी गई तो कहीं वह अतिरिक्त लिखे की रायल्टी न मांग बैठे। वे खुश दिखना भी चाहते हैं। मगर अपनी खुशी साहूकारी की आड़ में छुपा कर महफूज भी रखना चाहते हैं।

● **राजेश सेन**

श्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

जनजातीय गौरव दिवस

15 नवंबर, भोपाल

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री

जनजातीय समाज के विकास को मिली गति

जनजातीय गौरव दिवस पर सरकार ने खोले योजनाओं के द्वार...

मध्यप्रदेश में विविध, समृद्ध एवं गौरवशाली जनजातीय विरासत है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में न केवल इस विरासत का संरक्षण एवं संवर्धन किया जा रहा है, अपितु जनजातीय क्षेत्रों के समग्र विकास तथा जनजातीय वर्ग के कल्याण के लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। मध्यप्रदेश में विगत 17 वर्षों में जनजातीय कल्याण की दिशा में कई उल्लेखनीय कार्य किए गए हैं, जिससे प्रदेश का जनजातीय समाज देश में सबसे खुशहाल है।

जनजातीय गौरव दिवस

भारत की आजादी का 75वां वर्ष अमर शहीदों के प्रति कृतज्ञता का वर्ष है। मध्यप्रदेश में असंख्य जनजातीय वीरों ने स्वाधीनता के संग्राम में अपना योगदान दिया है। मध्यप्रदेश के माटी के ऐसे शहीदों के जन्म स्थल, कर्मस्थल एवं बलिदान स्थलों पर आजादी का अमृत महोत्सव श्रद्धांजलि के साथ मनाया जा रहा है। मध्यप्रदेश में 1 करोड़ 53 लाख से अधिक जनजातीय भाई-बहन निवास करते हैं, जो कि भारत में सर्वाधिक है। मध्यप्रदेश का हर पांचवा व्यक्ति अनुसूचित जनजाति वर्ग का है। मध्यप्रदेश में जनजातीय भाई-बहनों की संख्या पूरे भारत की कुल जनजातीय जनसंख्या का 14 प्रतिशत है और मध्यप्रदेश की कुल जनसंख्या का 21.1 प्रतिशत है। मध्यप्रदेश में कुल 52 जिले हैं जिनमें से 21 जिले एवं 89 विकासखंड जनजातीय जिले और विकासखंडों के रूप में जाने जाते हैं। इनमें से 6 जिले पूर्ण आदिवासी बाहुल्य जिले हैं। प्रदेश की 5 हजार 211 ग्राम पंचायतें पेसा एक्ट के अंतर्गत आती हैं। प्रदेश में 3 जनजातियां- बैगा, सहरिया एवं भारिया को विशेष पिछड़ी एवं संवेदनशील जनजातियों का दर्जा प्राप्त है, जिनकी जनसंख्या 15 जिलों में निवासरत है।

धरती के भगवान बिरसा मुंडा

भगवान बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के छोटा नागपुर स्थित उलिहातू ग्राम में हुआ था। वे जनजातीय जीवन मूल्य की सनातन परंपरा के अग्रदूत हैं। वे क्रांतिकारी अपराजेय योद्धा और लोकनायक के रूप में प्रतिष्ठ हैं, जिन्हें समाज ने धरती के भगवान का दर्जा दिया है। दिनांक 18 सितंबर 2021 को मध्यप्रदेश के जनजातीय जननायक राजा शंकरशाह और रघुनाथशाह का बलिदान दिवस जबलपुर में मनाया गया था। इसी श्रृंखला में भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती मनायी गई।

17 साल में जनजातीय कल्याण की दिशा में प्रमुख कदम

सामान्य जानकारी

- वर्ष 2003-04 में जनजातीय कार्य विभाग का बजट लगभग 746 करोड़ रुपए था जो अब बढ़कर 8 हजार करोड़ रुपए से भी अधिक हो गया है।
- विगत 17 वर्षों में प्रदेश में जनजातीय क्षेत्रों में प्राथमिक शालाओं की संख्या में 81 प्रतिशत, माध्यमिक शालाओं की संख्या में 55 प्रतिशत, हाईस्कूल की संख्या में 112 प्रतिशत, हायर सेकेण्डरी स्कूल की संख्या में 81 प्रतिशत और कन्या शिक्षा परिसरों की संख्या में 2633 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

कला, साहित्य एवं संस्कृति

- पिछले वर्ष से राज्य सरकार द्वारा 15 नवम्बर को मध्यप्रदेश में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर प्रदेश की जनजातीय प्रतिभाओं का सम्मान भी किया जाता है।
- राजा शंकरशाह- रघुनाथशाह के बलिदान दिवस 18 सितंबर से भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस 15 नवंबर तक जनजातियों की संस्कृति, परंपरा, लोक कला, जीवन मूल्य, रोजगार एवं समग्र विकास के कार्य अभियान चलाकर किए गए हैं।
- जननायक टंट्या भील की स्मृति में खंडवा जिले के ग्राम बड़ौदा अहीर में एक विशाल स्मारक का निर्माण कराया गया है।
- जननायक भीमा नायक की स्मृति में ग्राम धाबा बावड़ी, जिला बड़वानी में भीमा नायक प्रेरणा केंद्र का निर्माण किया गया है।
- भारत सरकार के सहयोग से छिंदवाड़ा में आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है।
- जनजातीय जननायकों श्री बिरसा मुंडा, टंट्या भील, वीरांगना अवंतीबाई, शंकर शाह-रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस पर प्रदेश के विभिन्न जिलों में उनके जन्म स्थल/बलिदान स्थल पर शहीद मेलों का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है।
- अलीराजपुर जिले में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी छीतू किराड़ का स्मारक निर्मित किया गया है।
- प्रदेश की प्रमुख जनजातियों- गोंड, बैगा, भील, कोरकू, भारिया, सहरिया एवं कोल जनजातियों की संस्कृति को लोक व्यापी बनाने के लिए जनजातीय संग्रहालय की स्थापना की गई है।
- देश की पहली जनजातीय चित्र वीथी लिखंदरा का निर्माण किया गया है।
- जनजातियों के रहवासी क्षेत्रों में संदर्भ संग्रहालयों की स्थापना की योजना तैयार की गई है।

पर्यावरण की सुरक्षा का संकल्प

इस संकल्प ने हमारे
मन-मानस में गहरी जड़ पकड़ ली है।

कोल इण्डिया लिमिटेड
विश्व की वृहत्तम कोयला उत्पादक संस्था
A Maharatna Company

प्रकृति के अस्तित्व में ही
हमारा अस्तित्व है